पंचम माला, खंड 14, अंक 31, मंगलवार, 25 अप्रैल, 1972/5 वैशाख, 1894 (शक)

Fifth Series, Vol. XIV, No. 31. Tuesday, April 25, 1972/Vaisakha 5, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 14 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIV Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 31, मंगलवार 25 अप्रैल, 1972/5 वैशाख, 1894 (शक)

No. 31, Tuesday, April 25, 1972/Vaisakha 5, 1894 (Saka)

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1-2
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
541.	इन्दौर महू रेल लाइन (पश्चिम रेलवे को बड़ी लाईन में बदलना	Conversion of Indore Mhow line into Broad Guage (Western Railway)	2-3
543.	आन्ध्र प्रदेश के चितूर जिले में भूमिगत पानी में कमी	Depletion of Ground Water Resources in Chittor District, Andhra Pradesh.	3-4
544.	राज्य व्यापार निगम में अधिकारियों के प्रयोग के लिये कारों का आयात	Import of Cars for use of STC Officials	4-6
546.	दिल्ली क्लाथ मिल्स, जे. के. सिन्थेटिक और फर्टीलाइजर फैक्टरी, कोटा पर बकाया धनराशि	Outstanding Dues Against DCM J. K. Synthetic and Fertilizer Factory at Kota	6
547.	प्लेटफार्मों का विस्तार	Extension of Platforms	7-8
548.	रेलपथ निरीक्षकों को स्टोर के उत्तरदायित्व से मुक्त करना	Relieving of Permanent Way Inspectors of Stores Responsibilities	8-9
552.	मलयेशिया में साबुन के कारखाने की स्थापना	Setting up of Soap Factory in Malaysia	9-10

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pagas

ता० प्र० संख्या
S. Q. No.

553.	उड़ीसा में बिजली का अभूतपूर्व संकट	Unprecendented Power Crisis in Orissa	10-13
555.	उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	Threat of strike by Employees of Northern and North Eastern Railways	13
556.	रनगुवा नहर परियोजना (मध्य प्रदेश) के कार्य की प्रगति	Progress of Work on Ranguva Canal Project (M. P.)	13-15
560.	गुजरात में ग्राम्य विद्युतीकरण	Rural Electrification in Gujarat	15-17

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S.Q. No.

542.	पोंग बांध (हिमाचल प्रदेश) के कारण हटाए गये लोगों के पुनर्वास के लिये आवश्यक भूमि	Land required for Rehabilitation of Pong Dam Oustees (H.P.)	17-18
545.	रेलवे के लिये आधुनिकतम उपकरणों के आयात पर विदेशी मुद्रा को बचाने के उपाय	Measures to save Foreign Exchange on Import of Sophisticated Equipment for Railways	18
549.	भारतीय रेलवे में आशुलिपिकों की वरिष्ठता के आधार पर स्थानापन्न पदोन्नति	Officiating Promotion to Stenographers on Seniority Basis on Indian Railways	18-19
550.	वैगनों का निर्यात	Export of Wagons	19
551.	बाढ नियंत्रण योजनाओं के अन्तर्गत तट बंधों के निर्माण के लिये राज्य को अनुदान	Grant to Bihar State for Constructing Embankments under Flood Control Schemes	20
554.	राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया व्यापार	Trade Turn over of STC	20-22

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
557.	गण्डक परियोजना के लाभ	Gandak Project Benefits	22
558.	जाम्बिया की रेलवे को उत्तर रेलवे के अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराना	Services of Northern Railway Officials Lent to Zambian Railways	23
559.	सूती कपड़ा के निर्यात के लिये द्रुत योजना	Crash Plan for Cotton Textile Exports	23-24
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
3778.	कानपुर में वरिष्ठ लिपिक की नियुक्ति	Posting of Senior Clerk at Kanpur	24-25
3779.	कोचीन तथा अन्य नगरों के बीच रेल सम्पर्क और कंटेनर सर्विस का विस्तार	Rail Link between Cochin and other cities and Expansion of Container Service	25
3780.	केरल में 1972-73 के दौरान रेलवे का विकास कार्य	Works of Development of Railways in Kerala during 1972-73	25
3781.	जमालपुर फेक्ट्री में निर्मित स्टीम क्रेन	Steam Cranes Manufactured in Jamalpur Factory	26
3782.	उत्तर प्रदेश और बिहार में समान विद्युत प्रशुल्क	Uniform Power Traffic in Uttar Pradesh and Bihar	26
3783.	बिहार और उत्तर प्रदेश में हाइड्रो थर्मल और न्युक्लीयर योजनाओं के नाम	Names of Hydro Thermal and Nueclear Schemes in Bihar and Uttar Pradesh	26-28
3784.	जल स्त्रोतों का उपयोग	Exploitation of Hydro Sources	28
3785.	मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युती करण योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व निमाड़ जिले का विद्युतीकरण	Electrification of East Nimar District under Rural Electrification Schemes in Madhya Pradesh	28-29
3786.	बुरहानपुर रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) पर कुछ गाड़ियों में स्थानों का आरक्षण	Reservation of Berths for Certain Trains at Burhanpur Railway Station (Central Railway)	29

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
3787.	मध्यप्रदेश में घाटे में चल रही कपड़ा मिलें	Textile Mills running in loss in Madhya Pradesh	29-30
3788.	मध्य रेलवे जोन में चल रही शिक्षा संस्थाएं	Educational Institutions run in Central Railway Zone	31
3789.	दक्षिण रेलवे पर स्थापित रेलवे वर्कशाप कारखाने	Location of Railway Workshop Factories on Southern Railway	31
3790.	रीवा जिला (मध्य प्रदेश) में चचाई जल प्रपात	Potential of Hydro Electric Power in Chachai Falls of Rewa District (Madhya Pradesh)	32
3792.	लघु उद्योगों को स्ट्रेचड नायलोनयार्न की सप्लाई	Supply of Stretched Nylon Yarn to Small Scale Industries	32-33
3793.	मेरठ जिले के कुर्सी गांव में बिजली लगाया जाना	Electrification of Kursi Village, District, Meerut	33
3794.	तुंगभद्रा नहर परियोजना (आंध्र प्रदेश पर खर्च की गई धन राशि	Amount spent on Thungabhadra Canal Project (A. P.)	33-34
3795.	विशाखापतनम तथा काकीनाड़ा से शून्य बिन्दू पर शुष्क किये गये फ्रोजन धींगों का निर्यात	Export of Frozen Prawns from Vishakhapatnam and Kakinada	34-35
3796.	नारियल जटा का मूल्य	Price of Coconut Husk	35
3797.	आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयां	Grievances of Handloom Weavers in Andhra Pradesh	35-36
3798.	इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में दूसरे तीसरे दर्जे के टिकट या सम्मानार्थ पासों के बदले में प्रथम श्रेणी के स्थान पहले से आरक्षित करवाना	Advance Reservation of First Class Berths against Second/Third Class Tickets or Complimentary Passes on Allahabad Division (Northern Railway)	36
3799.	उत्तर रेलवे में रेलवे की पाबन्दियों के बावजूद वैगन बुक करना	Booking of Wagons against Railway restrictions on Northern Railway	36-38

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
3800	पार्सल माल लाने ले जाने वाले ठेकेदार मैसर्स बल्लबदास को काली सूची में शामिल करना	Blacklisting of M/s Ballabha Das Handling Contractor for Parcels/ Goods	38
3801.	भ्रष्ठाचार के लिये दोषी ठहराया गया राजस्थान विधान सभा का उम्मीदवार	Candidates for Rajasthan Legislative Assembly convicted for Corruption	38-39
3802.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को हुई हानि	Loss incurred to National Projects Construction Corporation	39
3803.	के. एस. आर. टी. निगम में रेलवे के प्रतिनिधित्व का बढ़ाया जाना	Raising Railways Participation in KSRT Corporation	39-40
3804.	केरल में परम्परागत उद्योगों को स्थायित्व प्रदान करना	Stabilisation of Traditional Industries in Kerala	40
3805.	इलाहाबाद के साइकल स्टेंड के ठेकेदार की ओर बकाया राशि	Dues Outstanding against Cycle Stand Contractor at Allahabad	40-41
3806.	इलाहाबाद डिवीजन में स्टेशनों पर साइकल स्टैंड के ठेकेदारों की ओर बकाया राशि	Amount Outstanding against Cycle Stand Contractors at Stations over Allahabad Division	41
3807.	कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Coal	41-42
3808.	दक्षिण रेलवे में एस० एन्ड टी० डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिक फिटर्स टेलीग्राफस की अनियमित पदोन्नति	Irregular promotion of Electric Fiters Telegraphs of S. and T. Department Southern Railway	42
3809.	जापान को लोहे का निर्यात	Export of Iron to Japan	42-43
3810.	उदयपुर इन्स्टीट्यूट में रेलवे रिफ्रेशर कोर्स में सुधार	Improvement in Railway Refresher Course at Udaipur Institute	43

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

3811.	इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा आफिसर्स कैरिज का रिहायश के लिये दुरुपयोग	Officers Carriage misused for residential purposes by Senior Officers, of Allahabad Division Northern Railway	43-44
3812.	डिवीजनल सुपरिटेंडेंट, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Divisional Superintendent, Moradabad	44
3813.	बंगला देश के साथ फिल्मों का व्यापार	Trade in Films with Bangla Desh	44
3814.	उत्तर रेलवे में इलेक्ट्रिकल एन्ड मेकेनिकल मेनटेनर्स के पदों को ऊंचा बनाना	Upgradation of posts of Electrical and Mechanical Maintainers on Northern Railway	45
3815.	रेलवे प्रशिक्षण विद्यालयों में भेजे गये कर्मचारियों को यात्रा भत्ते का भुगतान	Payment of Travelling Allowance to Employees sent to Railway Training Schools	45-46
3816.	चाय निर्यात में कमी	Set back in Tea Exports	46-47
3817.	कोटा मथुरा लोकल ट्रेन में मोबाइल वैन का लगाया जाना	Mobile Van for Kota Mathura Local Train	47
3818.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल, मिल ब्यावर के प्रबन्ध को हाथ में लिया जाना	Take over of Mahalaxmi Textile Mill, Bewar	47-48
3819.	रेलवे के संचालन में सुधार	Reform in Operation of Railways	48
3820.	लोक तांत्रिक प्रक्रिया का महत्व	Efficacy of Democratic Process	49
3821.	मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते की पिण्डों तथा पटि्यों की चोरी	Imported Zinc in gots and slabs found missing from Wagons at Meerut City Station	49
3822.	यात्री गाड़ियों के डिब्बों में सुधार	Improvement in Compartments of Passenger Trains	50

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			

3823.	मिलों में नियन्त्रित मूल्य वाले कपड़े के भण्डारों का इकट्ठा हो जाना	Accumulation of Stocks of Controlled Varieties of cloth in mills	50
3824.	ग्वालियर रेयन्स की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Gwalior Rayons	50-51
3825.	व्यापार दल का इण्डोनेशिया का दौरा	Trade Team's visit to Indonesia	51
3826.	तृतीय एशियाई अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय रेलवे द्वारा भाग लिया जाना	Indian Railways participation in Third Asian International Trade Fair	51-52
3827.	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1972 पर होने वाला व्यय	Expenditure on International Trade Fair 1972	52
3828.	छोटा नागपुर (बिहार) में ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता	Financial help for Rural Electrification Programmes in Chhotanagpur Bihar	52-53
3829.	लन्दन में राष्ट्रमण्डल सम्मेलन	Commonwealth Conference in London	53
3830.	दक्षिण कोरिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore to South Korea	53
3831.	अन्तर्राज्यीय विद्युत पारेषण लाइनों के लिये मध्य प्रदेश को आर्थिक सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh for Inter-State Power Transmission lines	54
3832.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से विभिन्न देशों को सप्लाई किया गया गन्धक	Sulphur supplied through MMTC to various countries	54-55
3833.	बिहार के बाढग्रस्त क्षेत्रों के लिये राशि का नियतन	Allocation for Flood affected Areas in Bihar	55
3834.	आंध्र प्रदेश के गडप्पा जिले में पुलिवेन्डला चैनल योजना की मंजूरी।	Approval for Pulivendala Channel Scheme in Guddapal District Andhra Pradesh	55-56

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
3835.	सैक्यूलर एडोप्शन कोड	Secular Adoption Code	56
3836.	सालांदी परियोजना के प्राक्कलन	Salandi Project Estimates	56-57
3837.	सालांदी परियोजना के जलमग्न क्षेत्र के प्रभावित परिवारों को दिया गया मुआवजा	Compensation paid to Families effected by submerged area of Salandi Project Orrissa	57
3838.	आंध्र प्रदेश में काफी बोने की योजना	Coffee Plantation Scheme in Andhra Pradesh	
3839.	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य (डी. डी. आर.) के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with GDR	58
3840.	चितूर जिले में संकट ग्रस्त मिलों को हाथ में लेना	Take over of Sick Textile Mills in Chittor District	58
3841.	राज्य व्यापार निगम के चेयरमेन की दक्षिण अमरीका की यात्रा	STC Chairman's Tour to South America	58-59
3842.	विश्व में हुए निर्यात व्यापार में भारत का भाग	India's share in World Exports	59-60
3843.	दरभंगा जिले में झंझारपुर और हसनपुर के बीच नई रेलवे लाइन	New Railway line between Jhanjharpur and Hasanpur in Darbhanga District	60
3844.	अजमेर में टूटे फटे रेल के माल डिब्बों की नीलामी	Auction of Condemned Railwa Wagons in Ajmer	60
3845.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of judges of High Courts	61
3846.	पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Employees working in Kota Division (Western Railway)	61-62
3847.	रेलवे डाक सेवा के डिब्बे	R. M. S. Bogies	62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
3848. केन्दुवाडीह पुलिस थाने की पुलिस द्वारा पूर्व रेलवे के कुसुन्डा ईस्ट कैबिन में से लीवरमैन को ले जाना	Removal of Leverman at Kusunda East Cabin, Eastern Railway, by Police of Kenduadih Police Station	62
3849. धनबाद के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ड के कार्यालय (पूर्व रेलवे) के समक्ष बारी बारी से (रिले अनशन)	Relay Fast in front of Divisional Superintendant's Office, Dhanbad (Eastern Railway)	63
3850. धनबाद में चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों को उपगृहों (आउट हाउसेस) का आवंटन	Allotment of Out Houses to Class IV Staff at Dhanbad	63-64
3851. बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये विशेष विभाग की स्थापना	Setting up of a Special Cell to check Ticketless Travelling	64
3852. त्रिशूली परियोजना को नेपाल के हाथ में देना	Handling over of Trisuli Project to Nepal	64-65
3853. बंगला देश से व्यापार करने के लिये नेपाल को माल लाने ले जाने की सुविधा देना	Transit facility to Nepal to trade with Bangla Desh	65
3854. राज्य व्यापार निगम के निर्यात और आयात कार्यों को पृथक पृथक करना	Bifurcation of Export and Import functions of STC	65-66
3855. गाड़ीयों में और वातानुकूलित डिब्बे जोड़ना	Attaching of more ACC Coaches in trains	66
3856. मध्य प्रदेश में विद्युत पम्पों द्वारा सिंचाई	Irrigation through Power Pumps in M. P.	66-67
3857. मध्य प्रदेश में औरछा परियोजना का सर्वेक्षण	Survey of Orchha Project in Madhya Pradesh	67

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
3858.	सिन्ध नदी परियोजना प्रतिवेदन	Sindh River Project Report	67-68
3859.	अमरीका के साथ फिल्म करार का नवीकरण	Renewal of Film Agreement with USA	68
3860.	विद्युत के बारे में अनुसंधान योजना	Research Scheme on Power	68-69
3861.	देश में विद्युत का मूल्यांकन	Appraisal of Power in country	69-70
3862.	गुजरात को विद्युत की सप्लाई	Supply of Power to Gujarat	70
3863.	गुजरात के गांवों में पारेक्षण लाइनों का विस्तार	Extension of Transmission Lines in Village in Gujarat	71
3864.	गुजरात के नमक निर्माताओं को वैगनों की सप्लाई	Supply of Wagons to Salt Manufacturers of Gujarat	71
'865.	विद्युती करण परियोजनाओं (दक्षिण मध्य रेलवे) के लिये मुख्य विद्युत इंजीनियर का नया मुख्यालय	New Head Quarters of Chief Electrical Engineer for Electrification Project (South Central Railway)	72
3866.	भीमडोल और सीलमपेट रेलवे स्टेशनों (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच रेल फाटक पर नीचे का एक पुल बनाना	Construction of an under Bridge at Level Crossing between Bhimadolu and Stampet Railway Stations (South Central Railway)	72
3867.	बांदा रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of an over bridge at Banda Railway Station	72-73
3868.	अहमदाबाद के लिये सर्क्युलर ट्यूब रेलवे	Circular Tube Railway for Ahmedabad	73
3869.	अहमदाबाद मेल एक्सप्रेस गाड़ी के साथ तीसरी श्रेणी का शयनयान का जोड़ना	Attaching Third Claass Sleeper Coach to Ahmedabad Mail/Express .	73
3870.	गुजरात में सिंचाई योजनाओं सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन	Project Report on Irrigation Schemes in Gujarat	73-74

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

3871.	राजस्थान में असिंचित भूमि	Unirrigated Land in Rajasthan	75
3872.	दक्षिण पूर्व रेलवे के बैलाडिला कोटावलसा सेक्शन पर पैसेंजर गाड़ी चलाना	Introduction of Passenger Train on Balladila Kotabalasa Section on South Eastern Railway	75-76
3873.	सरकारी परियोजनाओं द्वारा किया गया निर्यात	Export performance of Public Sector Projects	76
3874.	वच्छाघाट और जड़ाउ हराभंगी परियोजना प्रतिवेदन	Vachhaghat and Jarau Harabhangi Project Report	76-77
3875.	कानूनी व्यवस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव	Proposal for reorganisation of legal System	77
3876.	पश्चिमी कोसी नहर परियोजना	Western Kosi Canal Project	77-78
3877.	अमरीका को भारतीय फिल्मों का निर्यात करने के लिये पारस्परिक व्यवस्था	Reciprocal Arrangement for export of Indian Films to America	78
3878.	परिसमाप्त हुई कपड़ा मिलें	Textile Mills gone into liquidation	78
3879.	असम के चाय बागानों की समस्यायें	Problems in Assam Tea Gardens	78-79
3880.	रूई में आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध	Total ban on import of cotton	79
3881.	गंगा नदी पर किनारे पर बसे ग्रामों को बाढ़ों और गंगा नदी के कटाव से बचाने के लिये योजना	Scheme to protect villages from floods and erosion on banks of Ganga River	80
3882.	बरौनी से कटिहार लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion to broad guage line from Barauni to Kathar (North Eastern Railway)	80
3883.	भागलपुर और महादेवपुर घाट (पूर्वोत्तर) के बीच मालवाहक जहाज सेवा का बन्द होना	Suspension of Cargo Ship between Bhagalpur and Mahadevpur Ghat (N. E. Railway)	80-81

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
3884.	भागलपुर, बरारी और महादेवपुर घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) में गैर सरकारी स्टीमर सेवा चलाना	Operating of private steamer service in Bhagalpur, Barani and Mahadev-pur Ghat North Eastern Railway	81
3885.	बिना टिकट यात्रा करने, खतरे की जंजीर खीचने और रेलवे में चोरी को रोकने के लिये अभियान चलाने हेतु सामाजिक शिक्षा के लिये संस्था	Institution for Social Education to campaign against ticketless travel alarm chain pulling and thefts on Railways	81-82
3886.	भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में पूंजी निवेश	Investment in Foreign Countries by Indian Industrial	82-84
3887.	पश्चिम रेलवे के शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर शेड निर्माण	Construction of shed at Shamgarh Railway Stations (Western Railway)	84
3888.	जर्मन जनवादी गणराज्य और भारत के बीच व्यापार	Trade between Inda and GDR	85
3889.	ब्रिटेन की कैमिल्स फार्मेस्यूटिकल्स ओर फ्लास्टिक के निर्यात में वृद्धि	Increase in export of Chemical Pharma-ceuticals and Plastics to U. K.	85
3890.	स्टोर डिपुओं रेलवे स्टेशनों (दक्षिण रेलवे) के बीच का फासला	Distance between store depots and Railway Stations (Southern Railway)	85-86
3891.	डिवीजनल रेलवे अस्पताल दिल्ली (उत्तर रेलवे) में पद समाप्त करना	Abolition of posts in Divisional Rail-way Hospital, Delhi (Northern Rail-way)	86
3892.	सिंचाई प्रयोजनों के लिये हुल्गु नदी को पानी की सप्लाई	Supply of Water for Hulgu River for Irrigation purposes	86-87
3893.	सिलीगुड़ी (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) में रेलवे सुरक्षा दल के सिपाहियों की गिरफ्तारी	Arrest of **RPF** Constables at Siliguri (Northern Frontier Railway)	87
3894.	बिहार में ताप विद्युत संयंत्र	Thermal Power Plant in Bihar	87

अता० प्र० संख्या
U.S.Q. No.

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3895.	समस्तीपुर से दरभंगा होते हुए रक्सौल तक बड़ी रेल लाइन	Broad Guage line from · Samastipur to Raxaul via Darbhanga	87
3896.	नरियार पन्नापुर ग्राम (पूर्वोत्तर रेलवे) के हाल्ट स्टेशन पर गाड़ियों का न रुकना	Non stopping of Trains at Halt Station at Nariar Pannapur Village (North East Railway)	87-88
3897.	गोरखपुर से रक्सौल (पूर्वोत्तर रेलवे) तक बड़ी लाईन	Broad Guage Line from Gorakhpur to Raxaul (North Eastern Railway)	88
3898.	जल विज्ञान और मौसम विज्ञान के समांग लक्षणों के दस सब जोनों से सम्बद्ध प्रारूप प्रतिवेदन	Draft Reports on Ten Sub-Zones of Homogeneous Hydrological and Meteriological Characteristics	88-89
3899.	ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों के लिये मंजूर की गई योजनायें	Scheme sanctioned by REC in States	89-90
3900.	भारतीय रेलवे में औषध कारकों के वेतन मानों को क्रियान्वित करना	Implementation of Pay Scales for Pharmacist in Indian Rallways	90
3901.	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को कैश विटनेस भत्ता	Cash Witness Allowances to Station Masters and Assistant Station Masters	90-91
3902.	वर्दियों के बारे में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) से अभ्यावेदन	Representation from Class III Staff regarding Uniforms (Northern Railways)	91
3903.	वर्दियों संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision on Report of Uniforms Committee	91-92
3904.	कोयला ढोने के लिये रेल वैगन	Railway Wagons for despatch of Coal	92
3905.	राज्य व्यापार निगम की क्रय क्षमता बढ़ाने हेतु प्रबन्ध	Arrangements to step up purchasing capacity of STC	92-93

विषय		Subject	पृष्ट/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
3906.	पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के उपाय	Flood Control Measures in West Bengal	93
3907.	निर्यात हेतु उत्पादन की योजना	Export Production Plan	93-95
3908.	407 अप रेलगाड़ी का सहरसा जंक्शन से बनमांखी जंक्शन तक तथा वापस (पूर्वोत्तर रेलवे बढ़ाया जाना	Extension of 407 UP from Saharsa Junction to Banmankhi Junction and back (North—Eastern Railway)	95
3909.	चाय के डिब्बों का वितरण	Distribution of Tea Caddies	96
3910.	कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे परियोजना	Circular Railway Project for Calcutta	97
3911.	पश्चिम बंगाल में वैगनों का निर्माण	Wagon Building in West Bengal	97
3912.	तालचेर विमलागढ़ रेल सम्पर्क	Talcher Bimlagarh Railway Link	97-98
3913.	ग्राम कटित स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर हमला	Attack on RPF Personnel at Gram Katia Station (North Eastern Railway)	98
3914.	रेलों में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये विभाग	Machinery to check corruption on Railways	98-99
3915.	रेलगाड़ियों के लिये फालतू बिजली के प्रयोग के लिए राज्य सरकारों से वार्ता	Negotiations with State Governments for Utilizing Surplus Electric Energy for Trains	99-100
3916.	रेलवे वर्कशाप, खड़गपुर का विस्तार	Expansion of Railway Workshop, Kharagpur	100
3917.	रूस को तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco to USSR	100
3918.	रेल वैगनों को असाधारण तौर पर रोके रखना और वैगनों की कमी	Inordinate Detention of Zail Wagons and Wagons Shortage	101-102

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
3920.	भारतीय रूई निगम की दोहरी नीति	Dual Policy by CCI	103
3921.	केरल व्यापार केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Trade Centres in Kerala	103
3922.	देवीघाट में पन बिजली परियोजना का विस्तार	Extension of Hydel Project at Devighat	103
3923.	अमरीका को बाईसिकलों का निर्यात	Export of Bicycles to USA	104
3924.	सिंचाई के विकास के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Irrigation Development	104
3925.	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये परिव्यय	Outlay for Rural Electrification of Hill Districts of U. P.	104-105
3926.	उत्तर प्रदेश में टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन	Railway line from Tanakpur to Bageshwar in Uttar Pradesh	105
3927.	जल तथा विद्युत विकास परामर्शवादी सेवा द्वारा आरम्भ किये गये कार्य	Jobs undertaken by Water and Power Development Consultancy Services	105-106
3928.	क्षेत्रीय विद्युत भार पारिक्षण केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Regional Load Despatching Stations	106-107
3929.	सिगनल और टेलीकम्युनिकेशन विभाग के अत्यावश्यक सेवा वर्ग के कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन और ब्रेक डाउन भत्ता	Free Food and Break Down Allowance to Essential Category Staff of S & T Department	107
3930.	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सिगनल और संचार व्यवस्था के कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था	Accommodation for Signal and Telecommunication Staff, Delhi Division (Northern Railway)	107-108
3931.	लोक सभा के दरभंगा उप-चुनाव में सेनाध्यक्ष के चित्रों का प्रयोग	Use of Photographs of Chief of Army Staff in Darbhanga Bye Election to Lok Sabha	108

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

3932.	रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा खिरई रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्वी रेलवे) पर गोली चलाया जाना	Firing by RPF Personnel at Khiral Railway Station (South Eastern Railway)	108-109
3933.	राजस्थान में नहर सम्बन्धी परियोजनाओं की धीमी प्रगति	Slow Progress of Canal Projects in Rajasthan	109
3934.	कपडवंज स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के लिये रेलवे वैगन	Rail Wagons for Kapadvanj Railway Station (Western Railway)	109-110
3935.	तारापुर आणविक बिजली घर के कार्यकारण के बारे में गुजरत चेम्बर्स आफ कामर्स के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत	Discussion with Delegation of Gujarat Chamber of Commerce Regarding Working of Tarapur Atomic Power Station	110
3936.	गुजारत में बिजली की कमी	Power shortage in Gujarat	110-111
3937.	सीरे का निर्यात	Export of Molasses	111-112
3938.	ऐलकोहल का आयात तथा निर्यात	Import and Export of Alchol	112
3939.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के केला साइडिंग पर रेलवैगनों से फलों के पार्सलों की कमी	Shortage of Fruit Parcels from Wegons on Keal Siding at New Delhi Railway Station	113
3940.	मेरठ शहर स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के विरूद्ध शिकायत	Complaint agalnst Booking Clerk, Meerut City Station	113
3941.	ऊन धुनाई की क्षमता	Wool Combing capacity	114-115
3942.	पश्चिमी बंगाल में बिजली का संकट	Power Crisis in West Bengal	115-116
3943.	गाड़ियों में कोयले तथा डीजल तेल की खपत	Consumption of coal and diesel oil in trains	116-117
3944.	रेलवे सेवा आयोग को बम्बई से नागपुर ले जाना	Shifting of Railway Service Commission from Bambay to Nagpur	117

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
3945.	विदेश व्यापार मंत्रालय में जन-सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Public Relation Officers in Foreign Trade Ministry	117-118
3946.	धर्मनगर और सिलचर से लुमडिंग तक रात में रेल गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of a Night Train From Dharmnagar and Silchur to Lumding	118
3947.	तम्बाकू के लिये विपणन बोर्ड	Marketing Board for Tobacco	118
3948.	जावांवाला सीटी रेलवे स्टेशन (कांगड़ा घाटी) का स्थानान्तरण	Shifting of Jawanwala City Railway Station (Kangra Velly)	119
3949.	त्रिपुरा को सीमेंट ले जाने के लिये वैगन	Wagons for Movement of Cement to Tripura	119-120
3950.	रेलवे बोर्ड में सहायकों के पद	Posts of Assistants in Railway Board	120
3951.	श्रेणी एक और श्रेणी दो के अधिकारियों के लिये स्थानान्तरण संबंधी नीति	Transfer Policy regarding Class I and Class II Officers	120-121
3952.	चर्बी के लिये आयात लाइसेंस	Import Licence for Tallow	121
3953.	आंध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र को टैंक वैगनों की सप्लाई	Supply of Tank Wagons to Royal-Seema Region of Andhra Pradesh	121-122
3954.	आंध्र प्रदेश के लिये वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में अभ्यावेदन	Representation against inadequate supply of wagons to Andhra Pradesh	122
3955.	दामोदर घाटी परियोजना के अन्तर्गत बिहार के लिये सिंचाई की योजना	Irrigation Scheme under DVC for Bihar	122
3956.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन मजदूर संघ की मांगें	Demands of NPCC Workers Union	123
3957.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, आगरा के जनरल सेक्रेटरी से ज्ञापन	Memorandum from General Secretary National Projects Construction Corporation, Agra	123-124

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

3958.	बिजली परियोजनाओं के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala for Power Projects	124
3959.	केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	Closure of cashew Factories in Kerala	124-125
3960.	काजू और काली मिर्च के निर्यात व्यापार में सुधार करने के लिये नई योजना	New Plan to improve Export Trade of Cashew and Pepper	125-126
3961.	केरल को बाढ़ से बचाने की योजना	Plan to protect Kerala from floods	126
3962.	धनबाद स्टेशन (पूर्व रेलवे) में कर्मशियल क्लर्कों, बुकिंग, पार्सल क्लर्कों तथा गुड्स आफिस में क्लर्कों की संख्या	Strength of Commercial Clerks in Booking Parcel and Goods Offices, Dhanbad Station (Eastern Railway)	127
3963.	यूरोपीय साझा बाजार के देशों तथा ब्रिटेन को निर्यात	Exports to EEC countries and the U.K.	127-128
3964.	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प का विकास	Development of Handicrafts under Central Scheme	128-129
3965.	दस्तकारी के क्षेत्रों के लिये मण्डी की सुविधायें	Marketing facilities for Craft Concentration areas	129-130
3966.	लेखा विभाग (पश्चिम रेलवे) में क्लर्क ग्रेड के एक में पदोन्नतियां	Promotion to Clerks Grade I in Accounts Department (Western Railway)	130
3967.	मंत्रालय में हिन्दी अफसरों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Officers in Ministry	130-131
3968.	पश्चिम कोसी नहर परियोजना	Western Kosi Canal Project	131
	21 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 936 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correcting statement to V. S. No. 936 dated 21-3-1972	131
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377	
	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा कथित सांकेतिक हड़ताल	Reported token strike by LIC employees	131-135

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
उड़ीसा में आदिवासी लड़कियों के अवैध और अनैतिक व्यापार का समाचार	Reported trafficking in Adivasi girls in Orissa	136-141
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	136-137
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	137-141
सदस्य की रिहाई	Release of Member	
(श्री भोगेन्द्र झा)	(Shri Bhogendra Jha)	142
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
43 वां और 45 वां प्रतिवेदन	Forty-third and Forty-fifth Reports	142
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	
7 वां प्रतिवेदन	Seventh Report	142
अनुदानों की मांगें, 1972–73	Demands for Grants, 1972-73	
विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs	143-167
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	143-144
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K.P. Unnikrishnan	144-145
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	147-150
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	150
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	150-151
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	151-152
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	152-154
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mahanty	154-155
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	156-157
श्री आर० के० सिंह	Shri R. K. Sinha	157-158

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री सी० सी० देसाई	Shri C. C. Desai	158-159
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	160-162
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	162-163
डी० एच० पी० शर्मा	Dr. H. P. Sharma	163
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	163-165
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	165-166
श्री तुलसीदास दासप्पा	Shri Tulsidas Dasappa	166-167

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 25 अप्रैल, 1972/5 वैशाख, 1894 (शक)

Tuesday, April 25, 1972/ Vaisakha 5, 1894 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at one Minute past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को यह सूचित करता हूँ कि श्री एच० सीताराम रेड्डी की 72 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल, 1972 को सलेम में मृत्यु हो गई है ।

श्री एच० सीताराम रेड्डी वर्ष 1946-48 में संविधान सभा के तथा वर्ष 1952-53 में मद्रास के करनूल निर्वाचन क्षेत्र से पहली लोक-सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वे मद्रास विधान सभा के सदस्य थे। वे 1947-52 में मद्रास सरकार में मंत्री भी थे ।

हम अपने इस प्रतिभाशाली मित्र की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे आशा है कि दुखित परिवार को संवेदना भेजने में सभा मेरे साथ होगी ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, श्री सीताराम रेड्डी की मृत्यु के समाचार से हमें गहरा दुःख हुआ है तथा मैं आपके द्वारा व्यक्त किये गये उद्‌गारों से पूरी तरह सहमत हूं ।

श्री रेड्डी यद्यपि पहली लोक सभा के सदस्य थे, पर उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन अपने जिले, बेल्लारी में शुरू किया था, जहां वे जिला बोर्ड के सदस्य थे तथा वे जिला दुर्भिक्ष समिति और जिला शिक्षा समिति के भी सदस्य थे ।

उनकी श्रमिक समस्याओं में गहरी दिलचस्पी थी तथा उन्होंने श्रीलंका और जेनेवा में हुई अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन और ब्रुसल्स में औद्योगिक अन्तर्राज्यीय परिवहन समिति में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया था । वे उटकमंड में हुए एशिया और सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग के सम्मेलन में भी हमारे प्रतिनिधिमण्डल के नेता थे ।

शिक्षा विषयक वैज्ञानिक अनुसंधान एक अन्य विषय था जिसमें उनकी बड़ी रूचि थी । वे भारतीय केन्द्रीय रूई समिति और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य भी थे । वे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रबन्ध समिति के सदस्य भी रहे ।

हमारी गहरी संवेदना और सहानुभूति दुःखी परिवार के सदस्यों तक पहुंचा दी जाये ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : श्री एच० सीताराम रेड्डी के निधन पर प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किए गये उद्गारों में हम उनके साथ हैं और मैं आपसे दुःखी परिवार को हमारी सबकी संवेदनाएं भेजने की प्रार्थना करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अपने दल और अपनी ओर से मैं प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किए विचारों में उनके साथ हूँ और मैं आपसे श्री एच० सीताराम रेड्डी के परिवार को हमारी अपनी हार्दिक संवेदनाएं पहुंचाने का अनुरोध करता हूं ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): On behalf my party, I express my heartfelt sarrow on the sad demise of Shri Reddy and request you to convey our condolences to the bereaved family.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री एच० सीताराम रेड्डी के दुखद निधन पर आपके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं में समाजवादी दल समेत मैं आपके साथ हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी संवेदना संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय : दिवंगत आत्मा की स्मृति में सब लोग कृपया कुछ देर मौन खड़े रहें ।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे ।

The members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Conversion of Indore-Mhow line into Broad Guage (Western Railway)

*541. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether at the annual session of the Western Railway Employees Union at Indore on the 26th March, 1972, he stated that the Railway authorities would soon submit a report

to him in regard to possibilities of conversion of Indore-Mhow line into broad gauge line; and

(b) if so, the time by which the said report is likely to be received ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी, हां। इन्दौर से महु तक बड़ी लाइन के विस्तार के लिए द्रुतगति से इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने का विनिश्चय किया गया है। आशा है कि दिसम्बर के लगभग सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी।

Shri Phool Chand Verma : May I know the aspects kept in view while preparing report ? Whether the strategic importance and industrial backwardness of the area have also been kept in view ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Yes, Sir, all these things were kept in view.

Shri Phool Chand Verma : The hon. Minister said that report will be received by December. How much time will be required to convert this small line of 14 miles and when it will be completed ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : This is a piece of 21 miles. Its survey will take some time, and as I have told the report will be received by December 1972 and work will start after that.

Shri Hukam Chand Kachwai : Indore is an important industrial town. Keeping this in view this should be connected with Khandwa and Ajmer by broad guage. Whether this aspect will be kept in view while doing survey ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में भूमिगत पानी में कमी

*543. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में भूमिगत पानी की मात्रा में तेजी से कमी होने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो जल के संरक्षण और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की सहायता से एक मास्टर प्लान बनाने और लागू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है। इसमें विरोधाभास दिखाई देता है। यदि चित्तूर जिले में भूमिगत पानी की कमी नहीं है तो भूमिगत जल निदेशालय ने जिले में नए कुए खोदने की अनुमति देना बन्द क्यों कर दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : कुए खोदना किसी भी राज्य की योजना में शामिल नहीं किया गया है। पक्का पथरीला क्षेत्र होने के कारण वे कुएं नहीं खोदते। परन्तु अब इन क्षेत्रों को भी सर्वेक्षण में शामिल कर लिया गया है। कृषि मंत्रालय आंध्र प्रदेश से चित्तूर तक को भी इसमें शामिल किए जा सकने के लिए बातचीत कर रहा है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : चित्तूर को योजना में शामिल करने के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। क्या विद्यमान गम्भीर स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल वहां भेजा जायेगा अथवा मंत्री महोदय स्वयं जिले का दौरा करेंगे।

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। कुए खोदते समय हम तथ्य का पता लगाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे और स्थिति को और खराब होने से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के प्रयोग के लिये कारों का आयात

*544. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों के प्रयोग के लिए अनेक विदेशी कारें आयात की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निगम के पास ऐसी कितनी कारें हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों और निदेशकों के उपयोग के लिए कोई विदेशी कार आयात नहीं की जा रही है। पर में यह जानना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम के पास इस समय कितनी आयातित कारें हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : राज्य व्यापार निगम के पास बहुतसी कारें हैं। ये कारें वे कारें हैं जो स्थानान्तरण पर दूतावासों के कर्मचारी छोड़ जाते हैं। इन कारों को नीलाम किया जाता है और यदि उचित मूल्य मिले तो सबसे अधिक बोली लगाने वाले को यह दे दी जाती हैं।

दूसरे कुछ ऐसे व्यक्ति और स्थान जैसे राष्ट्रपति भवन, राज भवन, मंत्रीमण्डलीय मंत्री और लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा अध्यक्षों को ये कारें तटकर आदि समेत उचित मूल्य पर दी जाती हैं।

राज्य व्यापार निगम में तीन व्यक्ति कार्यालय की कार का उपयोग कर सकते हैं वे हैं अध्यक्ष और दो निदेशक जो इसका उपयोग प्रति मास केवल एक निश्चित राशि का भुगतान करने पर कर सकते हैं। मेरे पास इस सम्बन्ध में सही-सही आंकड़े नहीं हैं कि इस समय राज्य व्यापार निगम के पास वास्तव कितनी कारें बिक्री के लिए हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कारों के सम्बन्ध में था और क्या मंत्री महोदय कारों के आयात की अनुमति दे रहे हैं ? वें इनका उपयोग हमारे विरोध के बावजूद भी कर रहे हैं, उन्हे करने दिया जाये। पर प्रश्न यह है कि राज्य व्यापार निगम के अधिकारी कितनी आयातित कारों का उपयोग कर रहे हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : जैसा कि मैंने कहा केवल तीन कारें, एक अध्यक्ष और दो निदेशकों के लिए और वह भी वह किराया देकर कर सकते हैं। वह भी अधिक समय तक नहीं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कार का मूल्य गिरने न पाये और तब तक कार बदल दी जाती है।

Shri B. P. Maurya : Whether the facility of having a car given to you and ministers will be extended to Members of **Parliament** because the present arrangement is that if somebody has great temptation for an imported Car, he should marry a foreign lady ?

Shri L. N. Mishra : I do not think Members of Parliament will marry a foreign lady for this.

श्री के० लकप्पा : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम से सम्बद्ध अधिकारी अपने उपयोग के लिये कारों का आयात करते हैं और उन्हें बड़ी भारी कीमत पर विदेशों में बेचते हैं और इस बारे में संदिग्ध व्यापार चल रहा है ? आयातित कारों की नीलामी के लिये अनेक लोग धनराशि जमा करते हैं, लेकिन उन्हें नीलामी में आयातित कारें प्राप्त नहीं होती। लेकिन संदिग्ध व्यापार में उन्हें सब आयातित कारें मिल जायेंगी। क्या सरकार इस बारे में जांच करेगी और इस बात का पता लगायेगी कि क्या उक्त अधिकारी इन कारों को बाहर बेचने का प्रयास कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त करते हैं ? यदि यह सच है तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : जब तक कारों का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया जाता है, कोई भी व्यक्ति, यहां तक की राष्ट्रपति भी कारों का सीधे आयात नहीं कर सकते। राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा कारों के आयात करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये कारें राजदूतों के कर्मचारियों की हैं। और जब उनका स्थानान्तरण होता है तब वे कारों की सार्वजनिक बिक्री नहीं कर सकते। उन्हें कारों को राज्य व्यापर निगम को बेचना पड़ता है। राज्य व्यापार निगम उन कारों की नीलामी करता है और सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को कार बेच दी जाती है, बशर्ते इस सौदे में उचित लाभ हो। यदि उचित लाभ नहीं होता तो राज्य व्यापार निगम नीलामी में कारों को बेचने से इंकार कर देता है। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कारों की बिक्री राज्य व्यापार निगम को किसी अधिकारी द्वारा की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उन तीनों आयातित कारों को, जिनका आपने सदन में उल्लेख किया था, 53 आयातित कारों की सूची में शामिल किया गया था, जैसा कि 17 फरवरी, 1972 को सूचना दी गई थी ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं कारों का नाम बता सकता हूँ और माननीय मंत्री अपने को संतुष्ट कर सकते हैं। अध्यक्ष डीलैक्स डाटसन, 1968 मॉडल निदेशक, श्री बी. आर. नाथ टोयोटो कोरोना, 1967 मॉडल, निदेशक, श्री बी. एस. मिश्र वैल्सली, 1970 मॉडल।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने यह नहीं बताया है कि क्या इन तीनों कारों को पहले उल्लिखित कारों की सूची में शामिल किया जाता है अथवा नहीं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं यह नहीं कह सकता कि उन्हें 53 कारों की सूची में शामिल किया जाता है। कारों के मूल्य में कमी होने के भय से इन्हें शीघ्रता से बेचा जाता है, अतः एक अधिकारी अधिक समय तक एक कार का उपयोग नहीं कर सकता। कार की शीघ्रता से नीलामी कर दी जाती है।

Outstanding Dues against DCM, J. K. Synthetics and Fertilizer Factory at Kota

*546. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount of Railway dues outstanding against Delhi Cloth Mills Fertilizer Factory and the J. K. Synthetics at Kota (Rajasthan); and

(b) the reasons for non-payment of the said dues ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कोटा स्टेशन के निकट दाघ देवी साइडिंग द्वारा सैवित मैसर्स श्री राम फर्टिलाइजर्स एन्ड केमिकल्स पर 11–4–72 को 3,79,880 रुपये की रकम बकाया थी।

मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स पर कोई रकम बकाया नहीं है।

(ख) उपर्युक्त राशि में विलम्ब शुल्क और रुकौनी शुल्क मिले हुए हैं। रेलवे के इन दोनों दावों का फर्म ने प्रतिवाद किया है।

Shri Lalji Bhai : The hon. Minister has stated the outstanding dues against Delhi Cloth Mills but he has not stated the outstanding dues against J. K. Synthetics. I want to know the reasons for the dues outstandinh and when they are likely to be realised ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The Railway is a commercial concern. The disputes regarding demurrhages are very common in it. The firm has made a claim of 3 lakhs of rupees againgt the Railways and we have claimed a demurrhages of Rs. 2 lakhs against it. It is a commercial concern and such types of disputes are very common in it.

Shri Lalji Bhai : When the outstanding dues will be recovered ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I cannot give the exact date but the efforts will be made to recover the outstanding dues at an early date.

प्लेटफार्मों का विस्तार

*547. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाप के इंजन तथा डीजल इंजन द्वारा क्रमशः औसतन कितने रेल डिब्बे खीचे जाते हैं;

(ख) क्या गाड़ियों के डीजलीकरण के कारण ऐसे सभी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों का विस्तार करना आवश्यक हो गया है जहां डीजल से चलने वाली गाडियां रुकती हैं क्योंकि ऐसी गाड़ियां अधिक लम्बी होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्लेटफार्मों तथा उनके ऊपर शेड़ों का विस्तार करने के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) भाप इजन और डीजल इंजन द्वारा खीचे जाने वाली बोगियों की संख्या उनमें लगे इंजनों की किस्म खण्ड की ढ़लान और गाड़ी की रफ्तार आदि के अनुसार भिन्न होती है। डब्ल्यू० पी० टाइप बड़ी लाइन का भाप इंजन एक्सप्रेस गाड़ी में लगने पर अधिक से अधिक 14 सवारी डिब्बे खींच सकता है और मुख्य लाइन पर डब्ल्यू० डी० एम०–2 डीजल इंजन 100 कि० मी० प्रति घंटे के हिसाब से अपेक्षाकृत समतल खण्डों पर, अधिक से अधिक 18 सवारी डिब्बे खींच सकता है। इसी प्रकार, वाई० पी० टाईप मीटर लाइन का भाप इंजन अधिक से अधिक 13 सवारी डिब्बे खींच सकता है और वाई० डि० एम० 4 डिजल इंजन, 65 कि० मी० प्रति घंटे के हिसाब से अपेक्षाकृत समतल खण्डों पर, अधिक से अधिक 22 सवारी डिब्बे खींच सकता है।

(ख) जी हां, उन स्टेशनों पर जहां वर्तमान प्लेटफार्म अपर्याप्त हैं।

(ग) 40 स्टेशनों के प्लेटफार्मों के विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्लेटफार्मों पर शेड़ों की व्यवस्था का कार्यक्रम डीजलीकरण के कार्यक्रम से अलग है। प्लेटफार्मों को ढ़कने के लिये शेड़ों की व्यवस्था के प्रस्ताव, रेलवे उपयोगकर्ता सुविधा समितियों के परामर्श और धन की उपलब्धता को देखते हुए, वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के समय सामान्यता: प्रत्येक वर्ष अनुमोदित किये जाते हैं।

Shri Shashi Bhushan : There is a proverb that cut your coat according to your clothes. The platforms are small but the diesel engine trains are very big the coach for Bhopal remains out of the platform. The porter could not reach there and even the ladies have to bring their luggage themselves. Similarly, it is very difficult to come out of the train. So I want to know your scheme regarding extension of platforms.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We have phased programme in this regard. It is true that with the introduction of diesel engines the length of the platforms have been reduced. 40 stations and platforms will be increased every year under the phased programme.

Shri Shashi Bhushan : I want to know the number of diesel trains running in the country at present and the number of diesel trains Government propose to introduce ? I also want to know whether there is any scheme for the small platforms also ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : At present one thousand diesel trains run on broad guage and 120 diesel trains run on meter guage. We will replace steam engines by diesel engine as and when necessary. The Government will also increase the number of small stations and platforms.

Shri S. M. Banerjee ; It is not only necessary to increase the length of the platforms, but the level of some platforms should also be raised. I want to know whether stepe will be taken in this direction ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The height of the platform will be taken into consideration besides the length of the platform.

श्री के० एस० चावड़ा : क्या दिल्ली अहमदाबाद के बीच प्लेटफार्मों के विस्तार करने का कार्य पूरा हो गया है ; यदि हां, तो सरकार दिल्ली और अहमदाबाद के बीच कब डीजल गाड़ियां चलायेगी ?

Mr. Speaker ; How the hon. Member has started this new topic ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस सम्बन्ध में कार्य किया गया है । में इस बारे में वास्तविक तारीख बताने में असमर्थ हूं लेकिन यह कार्य बहुत शीघ्र पुरा हो जायेगा ।

Shri Phool Chand Verma : I want to know whether it is not a fact that out of date steam engines are still being used at Ratlam Division on Western Railway ? I want to know whether Government people to replace them by diesel engines ?

Mr. Speaker : The Question relates to the extension of platforms.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Whenever some steam engine becomes useless, it is replaced by diesel engine.

रेलपथ निरीक्षकों को स्टोर के उत्तरदायित्व से मुक्त करना

*548. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांचू समिति की सिफारिश के अनुसार सभी रेलों में रेलपथ निरीक्षकों को स्टोर के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) भंडार संभालने का काम रेल पथ निरीक्षकों के कार्य का अभिन्न अंग है । फिर भी, भंडार लेखा प्रणाली को सरल बनाने तथा भंडार की मात्रा सीमित करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know the steps Government propose to take to simplify the procedure ? The hon. Minister has admitted the over burden of the permanent way inspector .Taking this into consideration what steps Government propose to take to improve the phase ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Formerly, the responsibility of store lies with the inspectors but now the responsibility of store lies with clerk, but the overall responsibility lies with the

permanent way inspectors. They will look after these stores but the other stores will be looked after by the Chowkidars. Measures are being taken to simplify the accountal procedures and steps are also being taken to limit the size of the stores holdings. In this way their responsibility has greatly been reduced.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether efforts are being made to implement the recommendation of the Wanchoo Committer ? It has been stated in those recommendations that the goods of other department also kept in those stores and all the responsibility lies on them. Taking all these things into consideration, whether the Committee has recommended that they will not be responsible for such stores ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I will read the recommendation of the Wanchoo Committee before the House, So that the position may be cleared. It has been stated in the Wanchoo Committee's report that:

"We are of the view that in all Cases the permanent way inspectors and the signal inspectors should be relieved of their stores charges and should be held responsible only for the unprest issue to, and required by, them for their day to day work."

Taking this into consideration he will be responsible only for those stores which are locked by him. He will not be directly responsible for other stores. We want to see that they will have the responsibility of as much less stores as possible.

मलयेशिया में साबुन के कारखाने की स्थापना

*552. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मलयेशिया में वहां की सरकार के सहयोग से 10 लाख रुपये के पूंजी-निवेश का एक साबुन का कारखाना लगाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां तो विदेशी मुद्रा में राज्य का कितना हिस्सा होगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) मैसूर सरकार साबुन कारखाना, बंगलौर, मे० पी० लाल स्टोर्स, क्वालालुम्पूर नामक मलयेशिया की एक फर्म के सहयोग से मलयेशिया में चन्दन के साबुन का एक कारखाना स्थापित कर रहा है। 10 लाख रु० की कुल इक्विटी पूंजी में भारतीय पार्टी का अंश एक लाख रु० होगा जो निर्यातों द्वारा पूरा किया जायेगा।

श्री धर्मराव अफजलपुरकर : वे शर्तें क्या हैं, जिनके अधीन मैसूर सरकार एक प्राइवेट फर्म के सहयोग से मलयेशिया में चन्दन के साबुन का एक कारखाना स्थापित कर रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैसूर सरकार वह सभी तकनीकी जानकारी, अनुभव तथा परामर्श प्रदान करेगी जिसमें व्यक्तियों का प्रशिक्षण, साबुन बनाने सम्बन्धी जानकारी, ढांचा, इंजीनियरिंग सम्बन्धी तकनीक, प्ररिक्षण प्रक्रिया आदि शामिल हैं। तकनीशियन, इन्जीनियर, प्रबन्ध अधिकारी भी मैसूर सरकार प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त मैसूर सरकार प्रति वर्ष एक लाख रुपये की सुगन्धित सामग्री भी प्रदान करेगी।

श्री धर्मराव अफजल पुरकर : क्या मैसूर सरकार एक प्राईवेट फर्म के सहयोग से जापान में भी ऐसा ही एक कारखाना खोलने पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मलयेशिया में साबुन कारखाने के बारे में है ।

श्री ए० सी० जार्ज : हमें ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

श्री के० लकप्पा : मैसूर के चन्दन के साबुन की सुगन्धी तथा सौन्दर्य में न केवल दक्षिर्ण-पूर्व एशिया को बल्कि योरूप को भी आकर्षित किया है । फिर भी यह खेद की बात है कि इस मंत्रालय ने मैसूर के चन्दन के साबुन के निर्यात तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं । भारत सरकार विशेषकर विदेश व्यापार मंत्रालय इस साबुन का निर्यात बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाने पर विचार कर रहा है ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैसूर के चन्दन के साबुन की सुगन्धी दूर-पूर्व से बहुत दूर जाकर सारी दुनिया में फैल गयी है। भारत सरकार विशेषकर विदेश व्यापार मंत्रालय की नीति चन्दन के साबुन और तेल के निर्यात को प्रोत्साहन देने की है। चन्दन के तेल और साबुन के निर्यात कर्ताओं को नकद उपदान आयात सम्पूर्ति तथा अन्य निर्यात सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ।

उड़ीसा में बीजली का अभूतपूर्व संकट

+

*553. **श्री राम सहाय पाण्डे** :
श्री बक्शी नायक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हाल ही में बीजली का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है और वहां अन्य उद्योगों के साथ-साथ रूरकेला इस्पात कारखाने पर भी इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है;

(ख) क्या सरकार ने स्थिति का मूल्यांकन किया है और इस संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मचकुंड जलाशय के वाहक्षेत्रों में कम वृष्टि के कारण इसमें जल की कमी और उसकी वजह से ऊर्जा की उपलब्धता में कमी होने के परिणामस्वरूप दक्षिण उड़ीसा में (जिसे मचकुंड परियोजना से बिजली मिलती है) विद्युत की गम्भीर कमी उत्पन्न हो गई है । इसके परिणामस्वरूप

दक्षिण उड़ीसा में उद्योगों को विद्युत सप्लाई में कटौती करना आवश्यक हो गया है। उड़ीसा के उत्तरी भाग से दक्षीण भाग को विद्युत का व्यपर्तन केवल 40 मैगावाट ही अनुबंधीत मांग के स्तर तक रूरकेला को विद्युत की सप्लाई सीमित करने के लिये आवश्यक हो गया है।

(ख) और (ग) उड़ीसा प्राधिकारी समय-समय पर स्थिति का मुल्यांकन कर रहे हैं और कमी को पूरा करने के लिए अब तक निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :—

(1) गंजम-बरहामपुर क्षेत्र में 15 मैगावट विद्युत-भार हीराकुंड-तलचर प्राणाली को हस्तांतरीत कर दिया गया है।

(2) दक्षिण उड़ीसा में बहुत उद्योगों से कहा गया है कि वे विद्युत लेने में स्वैच्छिक कमी करें।

Shri R. S. Pandey : From the statement it appears that the power could not be generated due to shortage of water in Machkund reservoir as a result of which power crisis developed there. May I know the number of such reservoir in the country which are suffering from water shortage as a result of which there are difficulties in the generation of power ? Also what is the total shortage of power in the country ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : आज देश में तीन ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी की कमी के कारण कम बीजली पैदा होती है। ये जलाशय हैं; शेरावथी, हीराकुंड और मचकुंड ।

श्री राम सहाय पांडे : देश में आज बिजली की कुल कीतनी कमी है ?

डा० के० एल० राव : देश में कुल दस लाख किलोवाट की कमी है; भारत के सभी राज्यों में 1 करोड़ 40 लाख किलोवाट घंटे का दैनिक उत्पादन ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : वक्तव्य से प्रतीत होता है कि उत्तर उड़ीसा के गंजम-बरहामपुर क्षेत्र में 15 मेगावाट विद्युत-भार दक्षिण उड़ीसा के हीराकुंड तलचर प्रणाली को हस्तांतरित किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण उड़ीसा में बिजली की भारी कमी है, जिसके कारण उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस 15 मैगावाट भार को हीराकुंड-तलचर प्रणाली को हस्तांतरित करने में क्या औचित्य है ?

डा० के० एल० राव : यह दूसरा उपाय है। हम उत्तर से दक्षिण अर्थात हीराकुंड तलचर प्रणाली से 15 मेगावाट बिजली इसलिये हस्तांतरीत कर रहे हैं ताकि गंजम-बरहामपुर क्षेत्र का भार पूरा हो सके ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : वक्तव्य में कुछ और कहा गया है। इसमें कहा गया है कि :

> "गंजम-बरहामपुर क्षेत्र में 15 मैगावाट विद्युत भार हीराकुंड-तलचर प्रणाली को हस्तांतरित कर दिया गया है" आप इसे अपने उत्तर से कैसे जोड़ते हैं।

डा० के० एल० राव : मुझे खेद है कि सम्भवत: इस वाक्य को नहीं समझा गया है। गंजम-बरहामपुर क्षेत्र के भार को मचकुंड प्रणाली से दूसरी प्रणाली को हस्तांतरित किया गया है। इसका अर्थ यही है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अभी हाल में राउरकेला इस्पात कारखाने के कोप्टिव प्लांट में कामबन्दी हुई । वहां बिजली की पैदावार में कमी है । बिहार में सूखे की गम्भीर स्थिति के कारण जिस पर हम सदन में चर्चा कर चुके हैं, स्थिति गम्भीर है, हीराकुंड जलाशय का स्तर भी नीचे चला गया है; अतः हीराकुंड और मचकुंड में बिजली की पैदावार बहुत कम हो गयी है । तलचर में भी दो इंजन काम नहीं कर रहे हैं । इंजन की कठिनाई अथवा वर्षा की कमी से जो बीजली के उत्पादन में कमी हुई है, उसके कारण उड़ीसा के सारे उद्योगों को कितनी हानि हुई है ? बिजली का बंद होना कितने दिनों से जारी है और सरकार स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न अब भी जारी है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या आप दो अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं दे सकता ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आपने एक समय वक्त दिया था कि जिनका व्यवहार सदन में अच्छा है, उनके साथ विशेष रूप से व्यवहार किया जायेगा । मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

डा० के० एल० राव : यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि उड़ीसा, जिसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य समझा जाता रहा, इस वर्ष तलचर, हीराकुंड तथा मचकुंड परियोजनाओं के एक साथ बंद होने से इस राज्य में अन्न का कम उत्पादन हुआ है । यह एक अस्वाभाविक बात है । हमें आशा है कि तलचर की मशीनरी 15 दिनों में ठीक हो जायेगी और बालीमेला जलाशय जून के बाद भर जायेगा और इस वर्ष के अंत तक प्रथम एकक में उत्पादन शुरू हो जायेगा । मेरे विचार में कुछ महीनों के बाद यह कठिनाई नहीं रहेगी ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैंने पूछा था कि उड़ीसा में कितने दिनों से यह बिजली का संकट चल रहा है, हमें कितनी हानि सहनी पड़ी और सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ताकि आने वाले सप्ताहों में स्थिति में सुधार हो सके । हिन्दुस्तान एरोनातिकल फैक्ट्री कोरापुर को बिजली की सप्लाई नहीं मिली । सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न क्यों नहीं पूछते ? यह बिलकुल पृथक प्रश्न है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह प्रासंगिक प्रश्न है । अभी प्रश्न काल का काफी समय है । आप एक मिनट की अनुमति क्यों नहीं देते ?

डा० के० एल० राव : उड़ीसा में बिजली की कमी अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है । यह केवल पिछले एक महीने में हुई और अगले कुछ दिनों में पूरी हो जायेगी । यदि तलचर एकक ठीक हो जाय । तो सारी कमी पुरी हो जायेगी लेकिन देश में कुछ ऐसे राज्य भी है जहां हम कुछ नहीं कर सकते । उड़ीसा के मामले में हमें आशा है कि 10,15 दिनों में तलचर की मशीन ठीक हो जायगी और उड़ीसा की बिजली की कमी पूरी हो जायेगी । कमी के तीन कारण हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ।

Shri Mala Deepak Singh Shakya : By what time the power cut will be withdrawn in South Orissa and whether there is some other alternative plan to provide power ?

डा० के० एल० राव : जैसे कि मैंने कहा है, यदि अगले 15 दिनों में तलवर एकक काम शुरू कर दे तो हम दक्षिणी प्रणाली को अधीक बिजली दे सकेंगे । मचकुंड क्षेत्र एक अच्छा जलग्रहण क्षेत्र है और आशा है कि जून के महीने में वर्षा होने पर यह कठिनाई दूर हो जायेगी ।

एक माननीय सदस्य : यदि वर्षा न आये तो ?

उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

+

*555. **श्री नवल किशोर शर्मा** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों ने हाल ही में पूर्ण हड़ताल की धमकी दी थी;

(ख) क्या इस प्रकार की धमकियां अन्य रेलों के कर्मचारियों से भी प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं प्रश्न पूछने के बजाय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत जल्दी बैठ जाने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

Progress of work on Ranguva Canal Project (M. P.)

*556. **Shri Nathuram Ahirwar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Ranguva Canal Project in Chhatarpur (M. P.) has since been approved by the Central Government and a sum of rupees two crores and ninety lakhs has been sanctioned therefor; and

(b) if so, whether the work on the said project has been started and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) The Government of Madhya Pradesh have proposed the Rangwan Project at an estimated cost of Rs. 186 lakhs. Some aspects of the Project are still under discussion between the State Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

Shri Nathuram Ahirwar : Since when Government has been discussing the Canal project ? Madhya Pradesh Government have sanctioned some amount but what is the hesitation on the part of Government of Uttar Pradesh due to which it is being delayed ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बांध बनाया था । अब मध्य प्रदेश ने दाब किया है कि वे इसका कुछ पानी सिंचाई के लिये इस्तेमाल करना चाहते हैं । इस लिये दोनो राज्यों के बीच विचार विमर्श होना स्वाभाविक बात है । अभी तक उनमें कोई समझौता नहीं हुआ है । यह पुराने ढंग की सिंचाई व्यवस्था है । हम इस पर विचार कर रहे हैं । मुझे विश्वास है कि हम इस समस्या का कोई न कोई हल निकाल लेंगे । मैं इस सम्बन्ध में बातचीत करूंगा ।

Shri Nathuram Ahirwar : When both the State Governments do not agree then why the hon'ble Minister does not solve the problem at his own land ? The length of this Canal is 67 miles. The Government of Uttar Pradesh while utilising the land of Madhya Pradesh had committed that they will be provided with water. The dam is being constructed whereas we are facing shortage of water. In view of this, will the hon'ble Minister try to get the water and complete the construction work ?

डा० के० एल० राव : यही तो मैंने कहा है । मैं इस समस्या का हल निकालने का प्रयत्न करूंगा । मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकेंगे ।

Shri Phool Chand Verma ; I wanted to know as to whether the last meeting took place between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Governments and what points were dis cussed in that meeting ?

डा० के० एल० राव : दोनों राज्यों के चीफ इंजीनियरों ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के चेयरमेन के साथ कोई तरीका निकालने के लिये बातचीत की थी । परन्तु वे कोई तरीका नहीं निकाल सके । फिर उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियर ने मध्य प्रदेश के चीफ इंजीनियर के साथ बातचीत करनी थी, परन्तु वह भी नहीं हो सकी । यह बहुत कम पानी का मामला है परन्तु यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । मुझे आशा है कि मैं एक या दो महीनों में इस समस्या को हल कर सकूंगा ।

Shri Arvind Netam ; May I know as to how much land of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh will be irrigated as a result of the project ?

डा० के० एल० राव : उत्तर प्रदेश में पहले ही काफी भूमि की सिंचाई की जा रही है । मध्य प्रदेश में वास्तव में कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है–इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है परन्तु मेरे विचार में खरीफ फसल में लगभग 20,000 एकड़ की और रबी फसल में 17,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

Shri Phool Chand Verma : This is wrong. Irrigation has not yet been started. He does not know the real position.

डा० के० एल० राव : जब कोई नहर ही नहीं है, तो सिंचाई कैसे होगी ? जैसाकि मैंने कहा है, मैं नहर की सीध के बारे में बातचीत करूंगा । इसमें गलत जानकारी देने की क्या बात है ?

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चीफ इंजीनियरों में अब तक कोई समझौता न होने के क्या कारण हैं।

डा० के० एल० राव : उन्होंने बातचीत की थी परन्तु उनमें मतभेद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना बनाई है और इससे काफी भूमि की सिंचाई होने लगी है। अब मध्य प्रदेश सरकार यह दावा कर रही है कि यह हमारा क्षेत्र हैं। वे कहते हैं कि उन्हें सिंचाई के लिये कुछ पानी मिलना चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि सिंचाई की यह पुरानी पद्धति है, इस पर विचार विमर्श किया जाना है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is a fact that the land of Madhya Pradesh was utilised and Uttar Pradesh wants to get real benefit and they do not want to give even one-fourth benefit to Madhya Pradesh; if so, whether efforts will be made to give maximum benefit to Madhya Pradesh also keeping in view the fact that it was is dacoit-infested area ?

डा० के० एल० राव : यह समस्त बांध स्थल मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। माननीय सदस्य का कहना है कि डाकूग्रस्त क्षेत्र होने के कारण इसमें सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है। महत्वपूर्ण कारण यह है कि मध्य प्रदेश सब से बड़े राज्यों में से एक है और वहां सिंचाई की न्यूनतम व्यवस्था है जबकि वहां सिंचाई की काफी क्षमता है। अत: इस राज्य को सिंचाई की अधीक सुविधाएं देना देश के हित में होगा।

Shri Ram Chandra Vikal : May I know the share of expenditure of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in respect of this project and whether water will be distributed accordingly ?

डा० के० एल० राव : यह संयुक्त जलाशय नहीं है। उत्तर प्रदेश ने अपने खर्च से इस जलाशय को बनाया है। अब प्रश्न यह है कि क्या मध्य प्रदेश को इस जलाशय में से एक नहर बनाने की अनुमति दी जाये। यदि नहर बनाई गई, तो इसके लिये मध्य प्रदेश को धनराशि खर्च करनी होगी। धन के बारे में कोई विवाद नहीं है। प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश को कितना पानी दिया जाये।

गुजरात में ग्राम्य विद्युतीकरण

*560. **श्री बेकारिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1971–72 और 1972–73 के लिए गुजरात की ग्राम्य विद्युत सप्लाई सहकारी समितियों को कोई ऋण मंजूर किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी है, उक्त सहकारी समितियों के नाम क्या हैं और किस प्रयोजन के लिए यह ऋण मंजूर किया गया है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) गुजरात राज्य की एक पाइलट ग्राम विद्युत सहकारी संस्था पर ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा धन लगाया जा रहा है। इस सहकारी संस्था के अधीन अमरेली जिले के कोडिनार तालुक और जुनागढ़ जिले के ऊना और वीरावल तालुकों के कुछ भागों में 107 ग्राम आते हैं जिनमें से 85 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। निगम ने इस सहकारी संस्था के लिए, रियायती शर्तों पर, 183.12 लाख रुपये की ऋण सहायता स्वीकार की है जिसे 1971 से विद्युतीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वियन हेतु पांच वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में 85 ग्रामों, 5030 पम्पों के विद्युतीकरण और 210 लघु तथा कृषि उद्योगों को विद्युत प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। निगम ने अभी तक 53.77 लाख रुपये की रकम दी है जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:–

1970-71	30 लाख रुपये
1971-72	23.77 लाख रुपये
	53.77

चालू वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा और धन राशि कार्यों की प्रगति के अनुसार दी जाएगी।

श्री वेकारिया : इस विवरण से पता चलता है कि वर्ष 1970–71 में मंजूर किया गया ऋण वर्ष 1971–72 में मंजूर किये गये ऋण से 7 लाख रुपये अधिक था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऋण की राशि में कमी किये जाने के क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : ग्राम्य विद्युतीकरण निगम ने यह राशि वितरित की है। यह राशि कार्य की प्रगति के अनुसार समय समय पर दी जाती है। यदि प्रगति न हुई हो, तो राशि को कम कर दिया जाता है। कार्य की प्रगति के सिवाय राशि को कम करने का कोई अन्य कारण नहीं है।

श्री वेकारिया : इन दो वर्षों में इस सहकारी समिति ने कितने ग्रामों में बिजली लगाई है, कितने पम्पसेट लगाये हैं और कितने उद्योगों को बिजली दी है?

डा० के० एल० राव : यह तो मैं नहीं बता सकूंगा। कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण होगा, यह मैंने अपने उत्तर में बता दिया है। किसी कार्य विशेष में कितनी प्रगति हुई है। यह मैं नहीं बता सकूंगा। इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को बता दूंगा।

Shri Nathuram Ahirwar : On what basis Rural Electrification Corporation sanctions power projects for the villages?

डा० के० एल० राव : इसका मुख्य प्रयोजन पिछड़े क्षेत्रों की सहायता करना है। परियोजना मंजूर करने की आम कसौटी यह है कि मंजूर की जाने वाली योजना से कोई निश्चित लाभ मिलना चाहिये। यदि कोई पिछड़ा हुआ राज्य है जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो इसमें भी रियायत दी जा सकती है।

Shri Laxmi Narain Pandey : Bastar region of Madhya Pradesh is also backward. May I know whether the hon'ble Minister would pay some attention to this region also ?

डा० के० एल० राव : बस्तर क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उस क्षेत्र के लिये परियोजना मंजूर करने में हमें बहुत प्रसन्नता होगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी ग्राम्य क्षेत्र के लिये रियायती या उचित दर पर बिजली उपलब्ध करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की गई है ?

डा० के० एल० राव : उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विद्युतीकरण की दर समस्त देश से अधिक है । समय समय पर हमने कुछ कार्यवाही की है परन्तु हमें सफलता नहीं मिली है । यहां की दर कुछ अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है ।

श्री डी० बसुमतारी : क्या असम में बिजली की खपत समस्त देश से कम है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० के० एल० राव : असम में बिजली की खपत सबमें कम है । देश में ग्रामों का औसतन विद्युतीकरण 20 प्रतिशत है। आसाम में 4 प्रतिशत है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दुबारा आरम्भ करता हूं । श्री विक्रम महाजन अनुपस्थित । श्री होरो, श्री जी० वाई० कृष्णन अनुपस्थित । श्री संकण प्रसाद अनुपस्थित । श्री रामावतार शास्त्री अनुपस्थित । श्री शिवस्वामी अनुपस्थित । श्री दामाजी अनुपस्थित । श्री सूर्यनारायण अनुपस्थित । श्री चन्द्रप्पन अनुपस्थित । प्रश्नों की सूची समाप्त ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पोंग बांध (हिमाचल प्रदेश) के कारण हटाये गये लोगों के पुनर्वास के लिए आवश्यक भूमि

*542. **श्री विक्रम महाजन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध (हिमाचल प्रदेश) के कारण हटाए गये लोगों के पुनर्वास के लिये राजस्थान में कितनी भूमि की आवश्यकता थी तथा उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने अब तक कितनी भूमि वास्तव में उपलब्ध कराई है; और

(ख) यह भूमि कहां-कहां है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) पोंग बांध का विस्थापितों के पुनर्वास के लिए राजस्थान नहर कमान में लगभग 2.25 लाख एकड़ क्षेत्र अलग रखा गया है । इसमें से

कितना क्षेत्र वास्तव में अलाट किया जाएगा यह आवंटन के लिए हकदार विस्थापितों की संख्या पर निर्भर रहेगा ।

लगभग 1.11 लाख एकड़ भूमि पहले से ही उपलब्ध है । चरण-दो के अधीन नौशेरा शाखा के 1973–74 तक पूर्ण हो जाने पर 90,000 एकड़ भूमि और उपलब्ध हो जाएगी । शेष 24,000 एकड़ भूमि परियोजना के चरण-दो के अंतर्गत दत्तोर शाखा के पूर्ण होने पर उपलब्ध हो जाएगी ।

(ख) इस समय उपलब्ध भूमि गंगानगर जिले में राजस्थान नहर की सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखाओं की कमान के अंतर्गत है ।

रेलवे के लिये आधुनिकतम उपकरणों के आयात पर विदेशी मुद्रा को बचाने के उपाय

*545. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के लिये आधुनिकतम उपकरणों के आयात पर विदेशी मुद्रा बचाने के उपायों का सुझाव देने के लिये गठित की गई सरकारी समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है जिसमें समिति की सिफारिशें दी गई हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1845/72**]

(ख) सरकार द्वारा सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं । लेकिन जहां तक पैरा 2 का सम्बन्ध है, (ख) में उल्लिखित विकल्प को स्वीकार कर लिया गया है ।

भारतीय रेलवे में आशुलिपिकों की वरिष्ठता के आधार पर स्थानापन्न : पदोन्नति

*549. **डा० संकटा प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल उन व्यक्तियों को वरिष्ठता के आधार पर स्थानापन्न पदोन्नति देने के बारे में सुझाव दिया गया था जिन्हे भारतीय रेलवे में 130–300 रु० के वेतनमान से 210-425 रु० के वेतनमान में आशुलिपिकों के चयन के लिये लिखित परीक्षा में बैठने की छूट दी गई है; और

(ख) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) इस तरह का कोई सुझाव रेल मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Export of Wagons

*550. **Shri Onkar Lal Berwa** ; Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the types of wagons proposed to be exported during the current plan ;

(b) the names of the countries to which these wagons will be exported; and

(c) the names of the Companies which have been entrusted with the work of manufacturing these wagons ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) the following types of wagons are generally exported :

1. Covered wagons
2. Bogie wagons
3. Timber wagons
4. Cattle wagons
5. Hopper wagons
6. Tank wagons
7. Covered G. A. S. wagons
8. Open E. A. S. wagons

(b) Orders for supply of wagons to the following countries are in hand :

1. Yugoslavia
2. Hungary
3. Ceylon
4. Iran
5. Iraq
6. Sudan
7. Poland, and
8. East Africa

(c) The following are the major manufacturers of wagons :

Braithwaite & Co.

Jessop and Co.

Burn and Co.

Indian Standard Wagon Co.

Textile Machinery Manufacturing Co. Ltd. (TEXMACO)

K. T. Steel Industries Ltd.

Hindustan General Industries Ltd.

Central India Machinery Manufacturing Co.

Grant to Bihar State for constructing Embankments under Flood Control Scheme

*551. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have accorded sanction for the grant of funds to the Government of Bihar for constructing embankments under the Flood-Control-Schemes; and

(b) if so, the broad outlines of the schemes sanctioned therefor ?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) The Government of India have recently agreed to provide additional financial assistance to the Government of Bihar during the remaining perion of the Fourth Plan with a ceiling of Rs. 9 crores for implementation of priority flood control schemes which have been considered necessary for reducing recurring flood damages and the cost of relief works in the State. The names of the priority schemes and estimated outlay during the last two years of the Fourth Plan are as follows :

Name of the Scheme	Estimated outlay during last two years of Fourth Plan. (Rs. in crores)
1. Construction of an embankment on the right bank of Ganga from Buxar to Koilwar.	2.0
2. Raising and strengthning of existing embankments along Ganga.	2.0
3. Construction of embankment and Protective works on Gandak (Bihar Share).	2.0
4. Embankments on the right side of PUN PUN river.	1.0
5. Mahananda embankment scheme and Kankai river scheme.	3.0
	10.0

Out of the estimated requirement of Rs. 10 crores during the last two years of the Plan, a sum of Rs. 1 crore is available in the State Plan.

राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया व्यापार

*554. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, राज्य व्यापार निगम और उसकी सहायक संस्थाओं द्वारा किये गये व्यापार तथा मुनाफे का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि ये अधिक मुनाफा कमायें ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम तथा इसके सहायक निगमों द्वारा किये गये व्यापार तथा उनके द्वारा कमाये गये लाभ के आंकड़े इस प्रकार हैं ;

(करोड़ रुपये)

	निर्यात	आयात	आन्तरिक	योग	कर लगने से पूर्व लाभ
राज्य व्यापार निगम					
1969–70	55.15	150.18	5.39	210.72	12.74
1970–71	70.58	141.90	5.36	217.84	6.43
1971–72	76.25	165.68	10.95	252.88	13.33
राज्य व्यापार निगम के सहायक निगम					
परियोजना तथा उपस्कर निगम †					
1969–70	–	–	–	–	–
1970–71	–	–	–	–	–
1971–72	16.20	25.60	–	41.80	0.47

† परियोजना तथा उपस्कर निगम 1971–72 (21–4–71) में ही निगमित हुआ था।

	निर्यात	आयात	आन्तरिक	योग	कर लगने से पूर्व लाभ
भारत का काजू निगम ††					
1969–70	–	–	–	–	–
1970–71	–	11.48	–	11.48	0.73
1971–72	0.25	29.02	0.02	29.29	2.34

†† भारत का काजू निगम 1970–71 में ही निगमित हुआ था।

	निर्यात	आयात	आन्तरिक	योग	कर लगने से पूर्व लाभ
हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम					
1969–70	1.90	–	0.62	2.52	0.01
1970–71	3.53	0.62	0.28	4.43	0.41
1971–72	4.13	0.35	0.14	4.62	(–)0 02
भारतीय चलचित्र निर्तात निगम †					
1969–70	–	–	–	–	0.04
1970–61	–	–	–	–	0.05
1971–72	–	–	–	–	0.04

	निर्यात	आयात	आन्तरिक	योग	कर लगाने से पूर्व लाभ

† भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का व्यवसाय अप्रत्यक्ष है और सेवा प्रभार कमीशन के आधार पर चलाया जाता है ।

राज्य व्यापार निगम (कनाडा) @

1969–70	–	–	0.11	0.11	(–) 0.02
1970–71	–	–	0.09	0.09	(–)0.05
1971–72	–	–	–	–	–

@ इस बीच बंद कर दिया गया है ।

(ख) यह निगम व्यापार से काफी लाभ कमाता है । इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम का व्यय अच्छी तरह से नियंत्रित है । नकदी को काम में लाने पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है । निगम अपना आवश्यकता से अधिक निधि को प्रयोग के लिए राज्य व्यापार निगम के समूह के भीतर एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को भी भेज देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपलब्ध संसाधन अधिक से अधिक हो जायें और ब्याज का भुगतान कम से कम हो ।

गण्डक परियोजना के लाभ

*557. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गण्डक परियोजना के पूरा होने के पश्चात् क्या-क्या लाभ हुए हैं ;

(ख) इससे किन-किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है और क्या इससे होने वाले लाभों का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) गण्डक परियोजना अभी निर्माणाधीन है। परियोजना के पूर्ण होने पर बिहार राज्य के सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों के 11.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर और देवरिया जिलों के 3.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिचाई लाभ प्राप्त होंगे । वर्ष 1971–72 के दौरान बिहार में 1.6 लाख हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 0.67 लाख हेक्टेयर सिंचाई शक्यता उत्पन्न की जानी प्रत्याशित है जिसकी तुलना में क्रमश: 0.29 लाख हेक्टयर तथा 0.32 लाख हेक्टेयर का समुपयोजन प्रत्याशित है । समुपयोजन में धीमे विकास के विविध कारण ये हैं—मौजूदा सट्टा प्रणाली लाभभोक्ताओं द्वारा क्षेत्र-नालियों के निर्माण में धीमी प्रगति, जल मार्गों के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण में देरी, आदि ।

जाम्बिया कि रेलवे को उत्तर रेलवे के अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराना

*558. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के बहुत से अधिकारियों की सेवाएं जाम्बिया रेलवे और जाम्बिया सरकार को उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) यदि हां तो क्या चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी तक के ऐसे रेल कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) इन कर्मचारियों का चयन किस प्रकार किया गया था और क्या इन पदों के बारे में सभी रेलों को परिपत्र जारी किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) ऐसे कितने कर्मचारियों का चयन किया गया जो उत्तर रेलवे के अधिकारियों के पुत्र हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०— 1846/72**]

(ग) जेम्बिया रेलवे की ओर से कुल छः मांगे प्राप्त हुई थीं । रेलवे के क्षेत्रीय प्रशासनों और उत्पादन यूनिटों से कहा गया था कि वे ऐसे व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करें जो उपयुक्त हों और जाने के इच्छुक हों । तीन अवसरों पर, जिनमें जरूरतों का अधिकतर भाग शामिल था, अंतिम प्रवरण जेम्बिया रेलवे द्वारा ही किया गया था चूंकि शेष तीन अवसरों पर जरूरतें बहुत थोड़ी थीं इसलिए अंतिम प्रवरण का काम रेलवे बोर्ड के दल पर छोड़ दिया गया था ।

(घ) ऐसी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है और पूरी सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सूती कपड़े के निर्यात के लिए द्रुत योजना

*559. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती कपड़े का निर्यात पुनः आरंभ करने के लिए एक द्रुत योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) सूती वस्त्र के निर्यात के बारे में तो ऐसी कोई द्रुत योजना नहीं है । वर्ष 1971–72 में लगभग 110 करोड़ रुपये के सूती वस्त्रों का निर्यात हुआ जबकि पिछले वर्ष 115 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था । पिछले वर्ष रुई की उंची कीमतों से भारत से सूती वस्त्रों के निर्यातों, विशेष रूप से सूती धागे के निर्यातों को

प्रतियोगिता करने की स्थिति पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा। भारत से धागा आयात करने वाले कुछ देशों की मांग भी अपेक्षाकृत काफी कम रही। सूती वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से निर्यात सहायता के सामान्य उपाय को जारी रखने तथा उसको मजबूत बनाने के अलावा अतिरिक्त स्वचालित करघे लगाकर वस्त्र उद्योग की निर्यात उत्पादन क्षमता बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयातित जटिल वस्त्र मशीनों के संबंध में निर्यातक मिलों की मांग के बारे में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। निर्यात उन्मुख सूती वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने की योजना बनाई गई है और आधुनिकीकरण की अन्य समस्याओं पर गंभीर रूप से विचार किया जा रहा है।

सूती वस्त्र निर्यात व्यापार के क्षेत्र में नये मार्ग खोजने की दृष्टि से सोवियत संघ के साथ व्यापार संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये है जिसके अनुसार सोवियत संघ सूती कपड़ों तथा अन्य उत्पादों में बदलने के लिए भारत को 20 हजार मे० टन रुई सप्लाई करेगा जिनका निर्यात सोवियत संघ को ही कर दिया जाएगा। चालू वर्ष के लिए रूपांतर प्रभार के रूप में भारत को लगभग 16.50 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

कानपुर में वरिष्ठ लिपिक की नियुक्ति

3778. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1969 से दिसम्बर, 1971 तक उत्तर रेलवे की विभिन्न डिवीजनों में स्थानान्तरण आदेशों पर कितने मामलों में अधिकारियों ने अदालती निषेधाज्ञा प्राप्त की ;

(ख) क्या वाणि शाखा के एक वरिष्ठ क्लर्क ने, जिसे जन-सम्पर्क वाले स्थान से हटाकर बिना जन-सम्पर्क के स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया था, इलाहाबाद डिवीजन के डिवीजनल अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय के द्वारा मानहानि का नोटिस दिया है ;

(ग) क्या उक्त वरिष्ठ लिपिक को प्रतिकूल सतर्कता रिपोर्ट के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे में स्थानान्तरित कर दिया गया था पर बाद में उसने अपनी नियुक्ति किसी प्रकार उसी डिवीजन में कानपूर में करा ली ; और

(घ) यदि हां, तो उसे उसी डिवीजन में कानपुर में नियुक्त करने के क्या कारण थे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) :

(क) 23

1969
इलाहाबाद मण्डल – 10
बीकानेर मण्डल – 1
1970
इलाहाबाद मण्डल – 4
मुरादाबाद मण्डल – 1
1971
इलाहाबाद मण्डल – 6
मुरादाबाद मण्डल – 1

(ख) जी हां ।

(ग) जी हाँ । लेकिन उसने स्वयं अपनी नियुक्ति नहीं करायी थी ।

(घ) चूंकि दक्षिण पूर्व रेलवे में उसके स्थानान्तरण से, उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाई करने में काफी विलम्ब हो सकता था, इसलिये उसको उत्तर रेलवे के किसी स्टेशन पर ही नियुक्त करने का निर्णय किया गया ।

कोचीन तथा अन्य नगरों के बीच रेल सम्पर्क और कंटेनर सर्विस का विस्तार

3779. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य मार्गों पर भी कंटेनर सर्विस आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन मार्गों पर यह सेवा तत्काल आरम्भ की जायेगी ;

(ग) क्या कोचीन और देश के अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों के बीच कंटेनर सर्विस चालू करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बाते क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) नयी दिल्ली और मद्रास बैंगलूर, नयी दिल्ली और सिकन्दराबाद, कोच्चिन और बेंगलूर बम्बई और दक्षिण रेलवे के आरुमृगनेरी स्टेशनों के बीच कंटेनर सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) जी हां ।

(घ) कोच्चिन को मद्रास, नयी दिल्ली और कलकत्ता के साथ कंटेनर सेवा द्वारा सम्बद्ध करने का विचार है ।

केरल में 1972-73 के दौरान रेलवे का विकास कार्य

3730. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 1972-73 के दौरान रेलवे के विकास के लिये किये जाने वाले कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ; और

(ख) इस अवधि के लिये योजना-वार वित्तीय आवंटन कितना किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) रेलवे विकास योजनाएं राज्य-वार अलग-अलग नहीं बनायी जाती अपितु विभिन्न मार्गों पर विशिष्ट परिचालनिक और यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर, रेलवे-वार, बनायी जाती हैं। इसलिए, केरल राज्य के लिए अलग से योजना वार वित्तीय आवंटन का संकलन नहीं किया गया है।

जमालपुर फेक्ट्री में निर्मित स्टीम क्रेन

3781. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त भारत में केवल जमालपुर की एक फैक्टरी है जो रेलवे की बड़ी लाइनों के लिये क्रेन की आवश्यकताओं को पूरी करती है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक निर्मित स्टीम क्रेनों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में कितनी बचत होने का अनुमान है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) एक सौ पैंतीस ।

(ग) लगभग तीन करोड़ रुपये ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में समान विद्युत प्रशुल्क

3782. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूल में से अधिक मात्रा में विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में समान विद्युत् प्रशुल्क लगाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अपने-अपने क्षेत्रों में इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ शहरों को छोड़कर, जहां घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए ऐतिहासिक कारणों से दरें निम्न हैं, प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए समान दरें हैं । कोई केन्द्रीय पूल इन दो राज्यों को थोक सप्लाई नहीं कर रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार और उत्तर प्रदेश में हाईड्रोथर्मल और न्युक्लीयर योजनाओं के नाम

3783. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली हाइड्रोथर्मल और न्युक्लीयर योजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या 1972-74 के वर्षों में ये सभी योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी ;

(ग) यदि नहीं, तो उन योजनाओं के नाम और संख्या क्या है जो 1972-74 के वर्षों में क्रियान्वित की जाएंगी ; और

(घ) इन दो राज्यों में ये सब योजनाएं कब तक क्रियान्वित की जाएंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चौथी योजना के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वियनार्थ हाथ में ली जाने वाली जल विद्युत् तथा ताप विद्युत् स्कीमों के नाम उपाबंध-एक में संलग्न हैं। चौथी योजना के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई परमाणु स्कीमें कार्यान्वियन के लिए शामिल नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 1973-74 तक जिन स्कीमों के क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना हैं उनकी संख्या और नाम उपाबंध-एक में दिये गये हैं।

(घ) चौथी योजना में सम्मिलित शेष सभी स्कीमों के पांचवीं योजना के अन्दर कार्यान्वित हो जाने की सम्भावना है।

विवरण

चौथी योजना के दौरान बिहार और उत्तर-प्रदेश में क्रियान्वियनार्थ स्कीमें

(क) मार्च, 1974 तक चालू हुई या चालू होने वाली स्कीमें :

1. **बिहार**

कोसी जल विद्युत्	4× 5= 20	मैगावाट
बरौनी विस्तार	2× 50=100	मैगावाट
पतरातू ताप विद्युत्	1× 50=	
	2×100=250	मैगावाट
कुल :	370	मैगावाट

2. **उत्तर प्रदेश**

यमुना जल विद्युत् चरण-एक	1× 17+1×11 = 28	मैगावाट
यमुना जल विद्युत् चरण दो (छिबरो)	4×60 = 240	मैगावाट
आंब्रा जल विद्युत्	3×33 = 99	,,
यमुना जल विद्युत् चरण-चार	1×10 = 10	,,
रामगंगा जल विद्युत्	1×60 = 60	,,
ओब्रा ताप विद्युत्	2×50 = 100	,,
ओब्रा ताप विद्युत्विस्तार चरण-एक	3×100= 300	,,
हरदुआगंज चरण-चार (ताप)	2×55 = 110	,,
कुल :	947	मैगावाट

(ख) स्कीमें जो आगे चलेगी और पाचवी योजना के दौरान चालू होंगी :

1. **बिहार**

सुवर्णरेखा जल विद्युत्	1× 65 = 65 मैगावाट
पतरातू ताप विद्युत् विस्तार	2×110 =220 ,,
उत्तर बिहार ताप विद्युत्	1×110 =110 ,,
कुल :	395 मैगावाट

2. **उत्तर प्रदेश** :

रामगगा जल विद्युत्	1× 60 = 60 मैगावाट
हरदुआगंज ताप विद्युत् विस्तार	1×110 =110 मैगावाट
पनकी ताप विद्युत् विस्तार	1×110 =110 मैगावाट
कुल :	280 मैगावाट

जल स्रोतों का उपयोग

3784. **कुमारी कमला कुमारी : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल स्रोतों का पता लगाने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना बनाने का प्रस्ताव है जिससे उसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष विकास निधि की सहायता से सारे देश में 12 मिलियन किलोवाट की कुल प्रतिष्ठापित विद्युत्-जनन क्षमता के लिए 62 संभाव्य विद्युत्-जनन स्कीमों के अनुसंधान का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। अनुसंधान राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है जिसमें उपस्कर की प्राप्ति और वितरण के लिए केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग का समन्वयक अधिकरण के रूप में लाभ उठाया जा रहा है।

(ख) इनमें से 38 स्कीमों का अन्वेषण-कार्य पूरा हो गया है और अन्य 10 स्कीमों के अनुसंधानों का 1973-74 तक पूर्ण होना संभावित है।

Electrification of East Nimar District under Rural Electrification Schemes in Madhya Pradesh

3785. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the schemes for electrification of East Nimar district (Madhya Pradesh) under the Rural Electrification schemes; and

(b) the amount given to the Government of Madhya Pradesh during first year of the Plan under this head ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The emphasis during the Fourth Plan continues to be on the electrification of pumpsets for increasing agricultural production; village electrification is a subsidiary part of this programme. The expenditure on rural electrification schemes since 1969-70 is being met from State Plan resources inclusive of Central assistance. The Rural Electrification Corporation in the Central Sector provides additive finance to the State Electricity Boards for rural electrification schemes. A provision of Rs. 20 crores has been made in the Fourth Plan for rural electrification schemes in Madhya Pradesh. So far the Rural Electrification Corporation has sanctioned 16 schemes in Madhya Pradesh envisaging loan assistance of Rs. 8.54 crores for the electrification of 37051 pumpsets and 759 villages. One rural electrification scheme relating to East Nimar District for the electrification of 2000 pumpsets and 28 villages is under the consideration of the corporation.

Up to 31st March, 1972, 3821 pumpsets and 180 villages have been electrified in East Nimar District. 16.8% of the villages of East Nimar District have been electrified as compared with the Madhya Pradesh State average of 12.2%.

(b) 1380 pumpsets and 54 villages were electrified in East Nimar District at the beginning of the Fourth Plan. 668 pumpsets and 28 villages were electrified in the first year of the Fourth Plan. The provision made in the first year of the Fourth Plan was Rs. 750 lakhs for the State of Madhya Pradesh. During the first year of the Fourth Plan, 12542 pumpsets and 244 villages were electrified in Madhya Pradesh.

Reservation of Berths for Certain Trains at Burhanpur Railway Station (Central Railway)

3786. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal for making arrangements for reservation of berths in the Amritsar Express, Varanasi Express, Punjab Mail and Calcutta Mail at Burhanpur Railway Station of the Central Railway; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Textile Mills running in loss in Madhya Pradesh

3787. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether most of the textile mills taken over by Government are running in loss in Madhya Pradesh;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the total loss suffered during the last three years, year-wise and the measures adopted to check the loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) Old and Worn out machinery, low productivity and high cost of cotton were some of the reasons for the mills making losses.

(c) A statement showing the financial results of the working of these mills during the last three years is attached. As regards the measures adopted to check the, loss, they are as follows:—

(1) Renovation programme taken up on priority basis.

(2) Rationalisation of labour.

(3) Proper utilisation of machine and planning of sales.

(4) Stream-lining of purchase of cotton through Central Cotton Purchase Committee.

(5) Centralised purchase of stores.

These measures have started showing resultsand almost all the mills have made profits in January and February, 1972.

Statement

(Rs. in lakhs)

S. No.	Name of the Mill	Year	Net profit/loss after depreciation. (—) ...Loss (+) ..Profit.	
1.	Hira Mills Ltd., Ujjain.	1969	(—) 21.90	
		1970	(—) 29.43	
		1971	(—) 34.80	(Provisional)
2.	New Bhopal Textiles Ltd., Bhopal.	1969-70	(—) 10.83	
		1970-71	(—) 9.07	
		1971-72 (April-Feb.)	(—) 6.43	(Provisional)
3,	Swadeshi Cotton and Flour Mills Ltd., Indore.	1969	(—) 16.49	
		1970	(—) 18.17	
		1971	(—) 38.94	(Provisional)
4.	Bengal Nagpur Cotton Mills Ltd., Rajnandgaon.	1969	(+) 2.20	
		1970	(—) 3.90	
		1971	(—) 5.49	(Provisional)
5.	Burhanpur Tapti Mills Ltd., Burhanpur.	1968-69	(—) 23.64	
		1969-70	(—) 12.38	The Management of this Mill was taken over in March, 1971.
		1971-72 (June-Feb)	(+) 8.23	

Educational Institution run in Central Railway Zone.

3788. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Higher Secondary Schools, High Schools and Colleges separately, being run by the Central Railway ;

(b) whether any person belonging to Scheduled Castes is working as Principal in any of the said schools; and

(c) if so, the name of that School ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Nil.

(b) & (c) Do not arise.

दक्षिण रेलवे पर स्थापित रेलवे वर्कशाप कारखाने

3789. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे की मुख्य वर्कशापों और कारखानों की संख्या कितनी है और वे किन राज्यों में स्थित हैं ;

(ख) उनमें से केरल में कितने हैं ; और

(ग) क्या आगामी पांच वर्षों में केरल में कुछ और वर्कशाप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कितनी और किन स्थानों पर ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दक्षिण रेलवे पर निम्नलिखित बड़े-बड़े कारखाने और फैक्टरियां हैं :—

(1) पैरम्बूर रेल इंजन कारखाना, मद्रास, तमिलनाडु।

(2) पैरम्बूर सवारी और माल डिब्बा कारखाना, मद्रास, तमिलनाडु।

(3) रेल इंजन, सवारी और माल डिब्बा केन्द्रीय कारखाना, गोल्डन राक, तमिलनाडु।

(4) रेल इंजन, सवारी और माल डिब्बा केन्द्रीय कारखाना, मैसूर, मैसूर राज्य।

(5) इंजीनीयरी कारखाना, अरकोणम्, तमिलनाडु ।

(6) सिगनल और दूर संचार कारखाना, पदोट्टनूर, तमिलनाडु।

(ख) कोई नहीं।

(ग) चूंकि इन वर्तमान कारखानों से दक्षिण रेलवे की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, अत: फिलहाल केरल में कोई नया कारखाना बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

रीवा जिला (मध्य प्रदेश) में चचाई जल प्रपात

3790. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि मध्य प्रदेश में रीवा जिले के चचाई जल प्रपात में पन बिजली की पर्याप्त संभावनाएं है ; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में निकट भविष्य में अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने टोंस घाटी में चचाई प्रपात के अनुप्रवाह में 690 मैगावाट के विद्युत् केन्द्र की प्रतिष्ठापना के वास्ते एक स्कीम प्रस्तुत की है जिसमें टोंस नदियों के जल का समुपयोजन करके 253 मैगावाट पक्की विद्युत् के विकास हेतु 183 मीटर के जल प्रपात और सोन नदी से टोंस घाटी में व्यपवर्तित कुछ जल का उपयोग सम्मिलित है ।

चूंकि इस परियोजना में अंतराज्यिक पहलू आते हैं इस लिये इस मामले पर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच विचार-विमर्श चल रहा हैं।

लघु उद्योगों को स्ट्रेचड नायलोन यार्न की सप्लाई

3792. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हौजरी निर्माताओं को स्ट्रेचड नायलोन यार्न आयात करने के लिए लाइसेंस दिये जाते थे और क्या अब यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है और अब उनका हिस्सा बड़े नायलोन यार्न निर्माताओं को दिया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बड़ी फर्म हौजरी निर्माताओं से यार्न का अत्यधिक मूल्य लेती हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में हौजरी निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उनको यार्न की उचित मूल्य पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी नहीं ।

विवरण

(क) हौजरी निर्माताओं को स्ट्रेचड नायलोन यार्न आयात करने के लिए लाइसेंस नहीं दिये गये हैं, क्योंकि देश में नायलोन यार्न का विनिर्माण शुरू हो चुका है । वे क्रिंपिंग मशीने रखने वाले

नायलोन यार्न निर्माताओं से अपेक्षित धागा ले लेते हैं अथवा स्वतंत्र क्रिम्प करने वालों से कमीशन आधार पर सीधे धागे का क्रिम्प करवा लेते हैं।

(ग) क्रिम्प किये हुए धागे की ऊंची कीमतों के सम्बन्ध में हौजरी निर्माताओं से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। वस्त्र आयुक्त ने इस मसले पर समझौता कराने के लिये हौजरी निर्माताओं और क्रिम्प करने वालों के बीच एक बैठक की व्यवस्था की। हौजरी निर्माताओं ने वस्त्र आयुक्त को सूचित किया है कि वे स्थानिय क्रिम्प करने वालों से क्रिम्प का काम करवाने की व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं।

मेरठ जिले के कुर्सी गांव में बिजली लगाया जाना

3793. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कुर्सी ग्राम (मुरादनगर) में ग्राम विद्युतीकरण डिवीजन, मेरठ द्वारा बिजली लगाए जाने का कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त ग्राम के निवासियों ने ग्राम्य विद्युतीकरण योजना कार्यालय, मोदीनगर में अपेक्षित धनराशि जमा करवा दी है; यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त ग्राम में ग्राम्य विद्युतीकरण योजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) मेरठ के ग्राम विद्युतीकरण प्रभाग में ग्राम कुर्सी के विद्युतीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड ने हाथ में लिया था। कुछ ग्रामवासियों ने पेशगी और सर्विस कनेक्शन शुल्क जमा करा दिये। जिन खम्भों पर निम्न वोल्टता लाइनें जाती हैं उनको गाड़ने के स्थल के संबंध में ग्रामीणों के बीच एक विवाद के कारण कार्य पूर्ण न किया जा सका। अब विवाद का निपटाने किया जा चुका है। कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है और ग्राम के विद्युतीकरण के अप्रैल, 1972 के अंत तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

तुंगभद्रा नहर परियोजना (आंध्र प्रदेश) पर खर्च की गई धनराशि

3794. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1967 से ले कर अब तक तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर परियोजना, अवस्था-II (आंध्र प्रदेश) के निर्माण पर, वर्षवार, कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) परियोजना के पूर्ण निर्माण का पुनरीक्षित अनुमान क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक से कोई अनुरोध किया गया है; और

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक निर्धारित समयानुसार, परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने 1967-68 से अब तक तुंगभद्रा उच्च-स्तरीय नहर परियोजना, चरण-दो के निर्माण पर निम्नलिखित धनराशि व्यय की है—

वर्ष	व्यय की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1967–68	0.52
1968–69	1.67
1969–70	1.82
1970–71	1.86
1971–72	2.00

(ख) आंध्र प्रदेश के लिए सम्पूर्ण परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 16.11 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए उपलब्ध संसाधनों की रोशनी में इसके पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

विशाखापतनम तथा काकीनाड़ा से शून्यबिन्दू पर शुष्क किये गये फ्रौजन धींगों का निर्यात

3795. **श्री के० कोदंडारामी रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रौजन धींगों का निर्यात अधिकांश तौर पर मद्रास और कोचीन से किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु जहाजों को विशाखापतनम और काकीनाड़ा पर आने को कहने का है ; और

(ग) क्या समुद्रजननि उत्पादों के नियमित निर्यात को सुनिश्चित करने हेतु विशाखापतनम तथा काकीनाड़ा पर आवश्यक नौवहन सुविधायें उपलब्ध कराने का सरकार का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० सी० जार्ज) : (क) कोचीन, मंगलौर, रत्नगिरि, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता के पत्तन हैं जहां से अब नियमित रूप से और काफी मात्रा में जमी हुई झींगा मछली का निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) सरकार ने विशाखापतनम तथा काकिनाडा से पोत-लदान की मांग पर विचार किया है और यह विषय 1971 में कांफ्रेंस लाइनों के साथ उठाया गया था और उन्हें इन सुविधाओं को प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया था। 1971 के दौरान पोत-लदानों के लिये विशेष रूप से किये गये अनुरोधों पर सरकार ने उस सम्बन्ध में प्रबन्ध भी किये थे।

(ग) सरकार इन सुविधाओं को देने की इच्छूक है लेकिन नियमित आधार पर प्रबन्ध करना तभी सम्भव होगा जब कि नियमित समय पर्याप्त मात्रा में जमे हुए उत्पाद भेजने के लिये आयें। इस समय काकिनाड़ा या विशाखापतनम दोनों में ही भेजे जाने के लिये माल की मात्रा इतनी नहीं है जिससे इन पत्तनों पर कोई जहाजरानी कम्पनी कोई जहाज नियत करने के लिये प्रोत्साहित हो।

नारियल जटा का मूल्य

3796. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** नारियल जटा के मूल्य के बारे में 28 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1357 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच जटा के मूल्य के बारे में उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसको देखते हुए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के सामने एक परिशोधन याचिका दाखिल की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयाँ

3797. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के लाखों हथकरघा बुनकरों का जीवन रूई के सूत, रंगों और रसायनों के अत्यधिक मूल्य के कारण बहुत ही कष्ट कर हो गया है ;

(ख) क्या सरकार को रूई के सूत को एक आवश्यक वस्तु घोषित करने और उसका एक उचित मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) आँध्र प्रदेश के कुशल बुनकरों, और सहकारी संस्थाओं के पास पड़े हथकरघा कपड़े के स्टाक में से कितने कपड़े को बंगला देश में निर्यात करने का विचार है ; और

(घ) उनकी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिये अन्य क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970 के मध्य से सूत की किमतों में वृद्धि का देश भर के हथकरघा बुनकरों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है। ये कीमतें अब गिरती जा रही हैं। रंग और रासायनिक पदार्थों की ऊंची कीमतों अथवा कम सप्लाई के सम्बन्ध में कोई शिकायतें सरकार के ध्यान में नहीं हैं।

(ख) तथा (घ) जी हां। चूंकि चालू वर्ष मे सूत की कीमतें गिर गई हैं और आगामी दो तीन महीनों में उनके उपयुक्त स्तर तक आ जाने की सम्भावना है अतः इसकी कीमतों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

(ग) आंध्र प्रदेश में हथकरघा कपड़े के स्टाक जमा हो जाने के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में दूसरे तीसरे दर्जे के टिकट या सम्मानार्थ पासों के बदले में प्रथम श्रेणी के स्थान पहले से आरक्षित करवाना

3798. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों के अन्तर्गत, दूसरे/तीसरे दर्जे के टिकटों या सम्मानार्थ पासों के बदले में प्रथम श्रेणी के स्थान पहले से आरक्षित करवाये जा सकते हैं;

(ख) क्या सरकार को इलाहाबाद के आरक्षण सम्बन्धी कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उन्होंने दूसरे या तीसरे दर्जे को टिकटों के बदले में पहले दर्जे के स्थान आरक्षित करने से इन्कार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दूसरे/तीसरे दर्जे के टिकटों अथवा मानार्थ पासों पर पहले दर्जे किराये और जिस दर्जे का पास/टिकट है उसके किराये के अन्तर का भुगतान करने पर पहले दर्जे की शायिकाओं का अग्रिम आरक्षण किया जा सकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में रेलवे की पाबन्दियों के बावजूद वैगन बुक करना

3799 **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1969 से अप्रैल, 1971 तक, महीनेवार, उत्तर रेलवे के माँजुरगढ़ी स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा रेलवे की पाबन्दियों के बावजूद कितने-कितने वैगन (पूरा बोझ) बुक किये गये ;

(ख) क्या जिम्मेदारी निश्चित करने के लिये कोई जांच की गई थी और यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) वह कर्मचारी/अधिकारी कौन हैं जो इन कदाचारों के लिये प्रथम दृष्ट्या जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : उत्तर रेलवे के मांजरगढ़ी स्टेशन के कर्मचारियों ने जनवरी 1969 से अप्रैल, 1971 तक की अवधि में रेलवे द्वारा लगायी गयी पाबन्दियों के बावजूद कुल 338 माल डिब्बे बुक किये थे। इनका महीनेवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

महीना		बुक किये गये माल डिब्बों की संख्या	महीना		बुक किये गये माल डिब्बों की संख्या
जनवरी,	69	—	जनवरी,	70	—
फरवरी,	69	—	फरवरी,	70	—
मार्च	69	—	मार्च,	70	—
अप्रैल,	69	2	अप्रैल,	70	—
मई,	69	2	मई,	70	2
जून,	69	—	जून,	70	—
जुलाई,	69	—	जुलाई,	70	28
अगस्त,	69	—	अगस्त,	70	13
सितम्बर,	69	—	सितम्बर,	70	71
अक्तूबर,	69	2	अक्तूबर,	70	80
नवम्बर,	69	—	नवम्बर,	70	27
दिसम्बर,	69	2	दिसम्बर,	70	94
			जनवरी,	71	1*
			फरवरी	71	14
			मार्च,	71	—
			अप्रैल,	71	—

* (12 दिनों को छोड़कर जिनके रिकार्डों का सत्यापन किया जा रहा है)।

(ख) जी हां, उत्तर रेलवे के अधिकारियों की एक समिति ने दिसम्बर, 1970 के अन्त तक के मामलों के सम्बन्ध में एक जांच की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पाबन्दियों के बावजूद इस तरह की बुकिंग के लिए उत्तर रेलवे के पांच अधिकारी उत्तरदायी थे। जनवरी और फरवरी, 1971 के मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्ति इस प्रकार थे :—

(क) मांजुरगढ़ी स्टेशन का स्टेशन मास्टर।

(ख) ग्लेक्सो प्रयोगशाला साइडिंग मांजुरगढ़ी का साइडिंग क्लर्क।

(ग) टुण्डला का वाणिज्यिक निरीक्षक।

(घ) अलीगढ़ का परिवहन निरीक्षक।

(ङ) टुण्डला का स्टाक नियंत्रक।

इन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अधीन भारी दण्ड दिये जाने के लिए कारवाई की जा रही है।

पार्सल माल लाने ले जाने वाले ठेकेदार मैसर्स बल्लवदास को काली सूची में शामिल करना

3800. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री अजीज इमाम :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कदाचार के कारण दक्षिण पूर्व और उत्तर रेलवे के पार्सल माल लाने ले जाने वाले ठेकेदार मैसर्स वल्लवदास को काली सूची में शामिल कर दिया गया है ;

(ख) क्या काली सूची में शामिल किये जाने के बाद इस फर्म ने रेलवे में मैसर्स इलाहाबाद लेबर सप्लाई एजेन्सी, हावड़ा, जिसका मालिक मैसर्स वल्लवदास के प्रबन्धक का पुत्र है, के नाम से ठेका लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार के लिये दोषी ठहराया गया राजस्थान विधान सभा का उम्मीदवार

3801. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार के लिये दोषी ठहराए गए किसी उम्मीदवार ने राजस्थान विधान सभा का निर्वाचन लड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उम्मीदवार का नाम क्या है तथा वह किस दल का उम्मीदवार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Loss Incurred to National Projects Construction Corporation

3802. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the National Projects Construction Corporation has suffered heavy lossess in 1970-71 and 1971-72;

(b) if so, the total loss suffered so far; and the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c) The amount of lossess sustained by National Project Construction Corporation, so far, is given below :—

1967-68	Rs.	29.21	lakhs
1968-69	Rs.	104.99	lakhs
1969-70	Rs.	100.17	lakhs
1970-71	Rs.	131.59	lakhs
1971-72	Rs.	100.00	lakhs (Provisional)

The main contributory factors leading to losses are the provision of depreciation of machinery; payment to idle labour on account of gradual retrenchment of surplus labour; payment of interest on borrowing to meet the lack of working capital; and uneconomic rates tendered in the case of some of the projects.

The Government have taken various steps to improve the working of National Project Construction Corporation. These include *inter alia* disposal of unserviceable and surplus machinery leading to a reduction of idle depreciation, retrenchment of surplus labour; improvement in the field inspection of various works undertaken by the Corporation and cost control. Besides a drive has been launched for obtaining new works in order to increase the out-turn of the Corporation.

के० एस० आर० टी० निगम में रेलवे के प्रतिनिधित्व का बढ़ाया जाना

3803. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई, 1969 में केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन में रेलवे के प्रतिनिधित्व को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत के समान स्तर तक बढ़ाने का निर्णय किया था;

(ख) क्या इस मामले में केन्द्र द्वारा किसी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं तथा उक्त बकाया राशि को शीघ्र ही देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जनवरी, 1969 में केन्द्रीय सरकार (रेलवे) ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया था कि 1-4-1969 से राज्य सड़क परिवहन निगमों को, जिसमें केरल राज्य सड़क परिवहन निगम भी शामिल है, दिये जाने वाले पूंजीगत अंशदान को बढ़ाकर 33⅓ प्रतिशत कर दिया जाये। यह निर्णय 31-3-1969 से पहले किये गये निवेशों पर लागू नहीं होता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

केरल में परम्परागत उद्योगों को स्थायित्व प्रदान करना

3804. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल जटा और काजू जैसे परम्परागत उद्योगों को राज्य में स्थायित्व प्रदान करने हेतु एक व्यापक योजना, योजना आयोग की स्वीकृति एवं सहायता के लिये उसे प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना आयोग द्वारा इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) केरल सरकार ने केवल नारियल जटा उद्योग को स्थायित्व प्रदान करने के लिये एक व्यापक योजना, योजना आयोग को प्रस्तुत की थी, काजू उद्योग के बारे में नहीं। इस योजना पर योजना आयोग द्वारा स्थापित किये गये एक अध्ययन दल द्वारा विचार किया गया। सभा पटल पर रखे गये विवरण में अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही के बारे में बताया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–1847/72]**

इलाहाबाद के साईकल स्टैंड के ठेकेदार की ओर बकाया राशि

3805. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-70 वर्षों के दौरान इलाहाबाद के साइकल स्टैंड के ठेकेदार से 8,000 रुपये वसूल नहीं किये जा सके;

(ख) क्या ठेकेदार का उल्लंघन किये जाने के कारण सम्बन्धित पार्टी का ठेका रद्द कर दिया गया था ; और

(ग) क्या बकाया राशि को अब वसूल कर लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) जी हां। इस ठेकेदार को 1-6-1967 से दो वर्ष के लिए इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के साइकिल स्टैंड का ठेका दिया गया था, लेकिन 14 किश्तें जमा करने के बाद उसने बिना सूचना दिये यह ठेका छोड़ दिया। अतः उसका ठेका रद्द कर दिया गया।

(ग) ठेकेदार से रेलवे को देय बकाया राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है ।

इलाहाबाद डिवीजन में स्टेशन पर साइकल स्टैंड के ठेकेदारों की ओर बकाया राशि

3806. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद डिवीजन के कतिपय स्टेशनों पर बने साइकल स्टैंड के ठेकेदारों की ओर कोई बकाया राशि है और यदि हां, तो बकाया राशि कुल कितनी है; और

(ख) उन कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो ठेकेदारों द्वारा देय राशि को समय पर वसूल करने में असफल रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां । इलाहाबाद मंडल में इलाहाबाद और अलीगढ़ रेलवे स्टेशनों के साइकिल स्टैंड के ठेकेदारों पर कुल मिलाकर लगभग 9029.00 रुपये बकाया हैं ।

(ख) चूंकि कर्मचारियों का इसमें कोई कसूर नहीं है और करारों के अनुसार रेलवे की बकाया देय रकम वसूली योग्य है, अतः कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

3807. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने कोयला उद्योग की मूल्य में वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कोयला उद्योग ने क्या मांग की थी और ब्यूरो ने कोयला उद्योग की मांग को किस आधार पर स्वीकार किया है; और

(ग) कोयले के मूल्य में वृद्धि से रेलवे और कोयले के अन्य उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सरकार ने ब्यूरो की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, अंशतः ।

(ख) 1972 में रेलों को कोयले की सप्लाई के लिए कोयले के मूल्य में प्रति मीटरिक टन 3.75 रुपये की वृद्धि करने के लिए अधिकांश कोयला खानों ने कहा है । कोयले के उत्पादन की प्रवृत्ति और कोयला निकालने के खर्च के अध्ययन के आधार पर ब्यूरो ने कोयले की कुछ किस्मों के लिए प्रति मीटरिक टन 0.37 रुपये से 2.26 रुपये तक मूल्य में वृद्धि करने की सिफारिश की है ।

(ग) कोयले के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण रेलों को प्रति वर्ष लगभग 1.6 करोड़ रुपये का अधिक खर्च होने का अनुमान लगाया गया है । रेलों के लिए कोयले के मूल्य में वृद्धि होने से

इसका अन्य दूसरे उपभोगकर्ताओं पर भी प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । सरकार ने कोयले के मूल्यों को निर्धारित करते समय ब्यूरो की सिफारिशों का भी ध्यान रखा है।

दक्षिण रेलवे में एस० एण्ड टी० डिपार्टमेंट के "इलेक्ट्रिक फिटर्स टेलीग्राफ्स" की अनियमित पदोन्नति

3808. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण रेलवे में सिगनल एण्ड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के "इलैक्ट्रिक फिटर टेलीग्राफ्स" का इण्डियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के अनुसार "ब्लाक सिगनल मैनटेनर्स" के रूप में पदोन्नत हो सकते हैं;

(ख) क्या "डिवीजनल पर्सनल आफिसर" मद्रास ने अपने पत्र संख्या एम० पी० 535/13/III दिनांक 18 मार्च, 1972 के अनुसार "इलैक्ट्रिक फिटर टेलीग्राफ्स" को "टी० सी० एम० एस०" के पद के 'ट्रेड टेस्ट' के लिए बुलाया है जो उनकी वैध पदोन्नति नहीं है।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि "ए० टी० सी० एम० एस०" की पदोन्नति का मार्ग "ई० एफ० टीज०" की "टी० सी० एम० एस०" की रूप में ऐसी पदोन्नति के कारण बन्द हो जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को "एस्टेब्लिशमैन्ट मैनुअल" के अनुसार उनके "एवेन्यू चार्ट" पदोन्नति पाने के आदेश दिये बिना ऐसे ट्रेड टेस्टों को रोकने के लिए आदेश जारी करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) दक्षिण रेलवे पर तार विभाग के विद्युत फिटर के लिए ब्लाक सिगनल अनुरक्षकों के पदों पर पदोन्नति-सरणि की व्यवस्था नहीं है।

(ख) अनुरक्षण के एकीकृत प्रणाली के शुरू करने के फलस्वरूप, विद्युत फिटरों (टेलीग्राफ) की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है । कंट्रोल रूम में अस्थायी तौर पर दूर-संचार अनुरक्षक के रूप में दो कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था क्योंकि उस समय अर्हता प्राप्त कर्मचारी सुलभ नहीं थे। नियंत्रक कार्यालय में अधिक समय तक काम करने के कारण दोनों कर्मचारियों को दूर-संचार अनुरक्षक के पदों की परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया था ।

(ग) यदि सीधी भर्ती के कोटे की जगह विद्युत फिटरों (टेलीग्राफ) को समाविष्ट कर लिया जाये तो सहायक दूर-संचार अनुरक्षकों की पदोन्नति-सरणि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जापान को लोह का निर्यात

3809. **श्री बी० के० दासचौधरी : क्या विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत द्वारा तथा ब्राजील, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, पेरु, चिली, मलयेशिया और अमरीका द्वारा जापान को सप्लाई किये गये लौह-अयस्कों की तुलनात्मक किस्मों का कोई अध्ययन किया है;

(ख) जापान द्वारा उपरोक्त देशों को अदा किये गये मूल्यों की तुलना में भारत को भारतीय लौह अयस्क के लिये कितना मूल्य अदा किया गया; और

(ग) तथा जापान को निर्यात किये जाने वाले भारतीय लौह् अयस्क के निर्यात मूल्य को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व इन सब बातों पर विचार किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) जापान को भारत से निर्यात किये जाने वाले लौह-अयस्क में विभिन्न ग्रेडों का लौह-अयस्क शामिल रहता है और उनके लिये जो जहाज पर किमतें प्राप्त होती हैं वे सामान्यत: किसी विशिष्ट ग्रेड के लौह् अयस्क की विश्व बाजार कीमतों के अनुरूप होती हैं ।

Improvement in Railways Refresher Course at Udaipur Institute

3810. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make improvement in the Refresher Course for Railway employees at the Udaipur Institute ;

(b) whether the teachers there are even less informed than the Drivers who go there for training; and

(c) if so, the steps being takan by Government to make suitable arrangements in this regard ?

The Minister of Railways : (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 'आफीसर्स केरिज' का रिहायश के लिये दुरुपयोग

3811. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों को अस्थायी तौर पर 'इंस्पेक्शन कैरिजैज' का बिना कोई शुल्क अदा किये रिहायश के लिए प्रयोग करने की अनुमति है जब कि इलाहाबाद स्टेशन पर रेलवे विश्राम गृह को सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा उक्त "कैरिजैज" पर कब्जे के फलस्वरूप नवम्बर, 1971 से जनवरी, 1972 तक, नवम्बर, 1970 से जनवरी, 1971 की तुलना में कम संख्या में निरीक्षण किये गये; और

(घ) यदि हाँ, तो इस कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) जी हाँ, जब विश्रामगृह में स्थान उपलब्ध नहीं होता।

(ख) अस्थायी रूप से ठहरने के लिए निरीक्षणयानों का उपयोग करने पर कोई प्रभार नहीं लिया जाता क्योंकि इस तरह के उद्देश्यों से विभागीय यानों के उपयोग में कोई अर्थोत्पत्ति नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायत

3812. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मुरादाबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायत मिली थी कि भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कहा जाता है कि उसकी गतिविधियां राष्ट्रविरोधी रहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) शहर कांग्रेस कमेटी, मुरादाबाद के उपाध्यक्ष से, मण्डल अधीक्षक मुरादाबाद के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का दोषारोपण किया गया था।

(ख) एक शिकायत मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर जवानों के लिए कैंटीन को बन्द कर देने के बारे में थी और दूसरी एक सैनिक स्पेशल के संचलन में देरी के बारे में। इस मामले की जांच-पड़ताल हो रही है।

बंगला देश के साथ फिल्मों का व्यापार

3813. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
डा० रानेन सेन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच फिल्मों के व्यापार का प्रश्न हल हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत तथा बंगला देश व्यापार करार में बंगला देश से फिल्मों के आयात तथा बंगला देश से फिल्मों के निर्यात की व्यवस्था है जिनका प्रत्येक ओर से मूल्य 15 लाख रु० से अधिक न हो। दोनों सरकारें इससे सहमत हैं कि चलचित्र फिल्मों का व्यापार भारतीय चलचित्र निर्यात निगम तथा बंगला देश के फिल्म विकास निगम द्वारा सम्भाला जायेगा।

उत्तर रेलवे में इलेक्ट्रिकल एन्ड मैकेनिकल मैन्टेनर्स के पदों को ऊंचा बनाना

3814. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पी० सी०–681 पी० ई०–214 दिनांक 9 नवम्बर, 1972 में रेलवे में 'इलेक्टिकल' तथा "मेकेनिकल मेनटेनर्स" के वेतनमानों के सम्बन्ध में उल्लिखित अनुदेशों को, उत्तर रेलवे में क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे में डिवीजन-वार अब तक कुल कितने पदों को ऊंचा बनाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अनुदेशों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 9–11–71 के रेलवे वोर्ड के पत्र में निहित अनुदेशों को उत्तर रेलवे प्रशासन ने मण्डल अधीक्षकों को परिपत्रित कर दिया है जो उन्हें कर्यान्वित करने के उद्देश्य से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। उन अनुदेशों का यथाशीघ्र कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए उनसे जोर देकर कहा गया है ।

रेलवे प्रशिक्षण विद्यालयों में भेजे गये कर्मचारियों को यात्रा भत्ते का भुगतान

3815. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे एस्टेब्लिशमेन्ट रुल 331 के अनुसार रेलवे प्रशिक्षण विद्यालयों में भेजे गये रेलवे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता मिलता है और यदि हाँ, तो उन्हें इसका भुगतान न किये जाने के क्या कारण है ;

(ख) क्या "रनिंग स्टाफ" को भी 50 प्रतिशत "रनिंग" भत्ता दिया जाता है ;

(ग) क्या रेलवे आफिसर्स कालेज बड़ोदा में अधिकारियों को पूर्ण यात्रा भत्ता दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) भारतीय रेल स्थापना संचिता, भाग I के नियम 331 (2) के अनुसार रेलवे प्रतिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण पाने वाले रेल कर्मचारी उसी दशा में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के हकदार है जब कि उसी संहिता के नियम 429 के अनुसार उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था न की गयी हो ।

(ख) पुनश्चर्या और पदोन्नति सम्बन्धी पाठ्य क्रमों के लिए प्रशिक्षण स्कूलों में पढ़ने वाले रनिंग कर्मचारियों को मील भत्ते के बदले निम्नलिखित दरों पर भत्ता दिया जाता है:—

शंटिंग इंजनों पर काम करने वाले शंटरों और फायरमेनों को	एक दिन या उसके किसी भाग के लिए 120 कि० मी०।
अन्य रनिंग कर्मचारियों को	एक दिन या उसके किसी भाग के लिए 160 कि० मी०।

जहां मुफ्त भोजन की व्यवस्था होती है, वहां ऊपर निर्दिष्ट भत्ते का आधा ही उनके नाम जमा किया जाता है।

(ग) स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले परिवीक्षाधीन अधिकारी यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता या मुफ्त भोजन के अधिकारी नहीं है। पुनश्चर्या या विशेष पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले अन्य अधिकारियों को, उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार, या तो निःशुल्क भोजन दिया जाता है या भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, भाग I के नियम 331 (2) के अन्तर्गत निर्धारित उतरते चढ़ते क्रम में दैनिक भत्ता दिया जाता है। यदि वे दैनिक भत्ते के लिए विकल्प देते हैं तो उन्हें भोजन के लिए भुगतान करना पड़ता है।

(घ) अधिकारियों को विकल्प देने की अनुमति है क्योंकि भोजन का खर्च, उनके द्वारा केवल नीचे के ग्रेड में लिये गये दैनिक भत्ते के अनुसार ही निश्चित किया जाता है जबकि अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में, विभिन्न वेतन श्रेणियों के कर्मचारियों का देय दैनिक भत्ते के अनुसार भोजन का खर्च निश्चित किया गया है।

चाय निर्यात में कमी

3816. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रमुख विश्व बाजारों के नाम क्या हैं जहां भारतीय चाय निर्यात में कमी हुई है ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और गिरावट कहां तक हुई है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हालांकि भारत से चाय के कुल निर्यात 1970 में 148.81 करोड़ रु० मूल्य के 20.84 करोड़ कि० ग्रा० से बढ़कर 1971 में 160.34 करोड़ रु० मूल्य के 21.26 करोड़ कि० ग्रा० के हुए और इस प्रकार चाय के निर्यात में 11.53 करोड़ रु० मूल्य की 42 लाख कि० ग्रा० की वृद्धि हुई, लेकिन कुछ देशों को चाय के निर्यातों में गिरावट आई है जिसके कारण ये हो सकते है : माँग तथा पूर्ति की स्थिति, वाणिज्यिक उतार-चढ़ाव, पर्याप्त तथा समय पर पोत-लदान की सुविधाओं का अभाव आदि।

जिन देशों में, वर्ष 1970 की तुलना में वर्ष 1971 में भारतीय चाय के निर्यातों में गिरावट आई है उनके नाम हैं : ब्रिटेन, मिश्र का अरब गणराज्य और आस्ट्रेलिया । पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड्स तथा सूडान को किये गये चाय के निर्यातों में भी थोड़ी सी गिरावट आई । वर्ष 1970 तथा वर्ष 1971 में इन देशों को किये गये भारत की चाय के निर्यात इस प्रकार हैं ।

(हजार कि० ग्रा० में)

देश	1970	1971
ब्रिटेन	98,877	71,339
मिश्र का अरब गणराज्य	11,318	9,172
आस्ट्रेलिया	3,710	3,062
पश्चिम जर्मनी	3,752	3,537
नीदरलैंड्स	2,751	2,461
सूडान	12,902	12,474

चाय बोर्ड इन सभी देशों में भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिये सघन कार्य करता रहा है और परिवहन, जहाजरानी आदि से सम्बन्धित कठिनाइयों का दूर करने के प्रयास भी करता रहा है ।

Mobile Van for Kota-Mathura local train.

3817. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to attach a mobile van for medical treatment of Railway Employees to Kota-Mathura local train, as is being done on Kota-Bina line; and

(b) if so, the time by which it will be done ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

महालक्ष्मी, टैक्सटाइल मिल ब्यावर के प्रबन्ध को हाथ में लिया जाना

3818. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल, ब्यावर का प्रबन्ध "रिलिफ अंडरटेकिंग" के अन्तर्गत हाथ में लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मिल का प्रबन्ध कब हाथ में लिया गया था ; और

(ग) जब से उक्त मिल का प्रबन्ध हाथ में लिया गया है तब से क्या इसने लाभ कमाया है ; और यदि हां, तो कितना ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 9 जनवरी, 1967 को महालक्ष्मी मिल्स कं० लि०, ब्यावर के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया ।

(ग) जी नहीं ।

रेलवे के संचालन में सुधार

3819. **श्री पी० वेंकटा सब्बया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संचालन में सुधार पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेले रेल परिचालन में सुधार लाने के लिए विविध आधुनिक विधियां अपनाकर जैसे भाप कर्षण के बदले अधिक तेज डीज़ल एवम् बिजली कर्षण अपनाना, अधिक मालवहन क्षमता वाले अधिक आधुनिक किस्म के मालडिब्बे चलाना, सेन्टर बफर कपलरों से सज्जित मालडिब्बे लगाकर हर एक गाड़ी के भारवहन में वृद्धि करना, सिगनल एवम् दूर-संचार की आधुनिक विधियां जिनसे गति और संरक्षा बढ़ जाती है, जैसे स्वचल ब्लाक सिगनल प्रणाली, रूटरिले अन्तर्पाशि और पेनल अन्तर्पाशि-व्यवस्था, प्रमुख विन्यास यार्डों का आधुनिकीकरण और प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों जैसे कार्य-अध्ययन तथा और अधिक मात्रा में परिचालन सम्बन्धी अनुसंधान को व्यवहार में लाना, सतत् प्रयास कर रही हैं । चिक तेज़ सवारी गाड़ियां, मुख्य-मुख्य शहरों से होकर जाने वाली तेज मालगाड़ियां, कन्टेनर सेवा, तीव्र पारवहन सेवा, माल भाड़ा अग्रेषक योजना आदि चलाकर सेवा में सुधार भी किया गया है ।

(ख) इन उपायों के परिणामस्वरूप, यह सम्भव हो सकता है कि भौतिक संसाधनों जैसे इंजन, मालडिब्बे और रेलपथ की लम्बाई - में अनुपातत: कम वृद्धि होने पर भी 1950–51 और 1970–71 के बीच, यात्री किलोमीटर संख्या तथा भाड़ा मी० टन किलोमीटर संख्या की मात्रा में क्रमश: 77.6 प्रतिशत और 188.7 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकी है । प्रतिदिन 10 लाख शुद्ध मी० टन किलोमीटर की ढुलाई लिए अपेक्षित इंजनों और मालडिब्बों की संख्या में मान्य गिरावट आयी है । दुर्घटनाओं की संख्या में भी ठोस कमी होना सम्भव हो सका है । प्रति दस लाख गाड़ी किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की संख्या 1951–52 के 54.1 की तुलना में 1969–70 में 10.6 रह गयी है ।

(ग) रेल परिचालन में सुधार लाने के लिए अपनाये गये विभिन्न उपायों को और भी तेज किया जायेगा जिससे और अधिक सुधार आये।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता

3820. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान सभाओं के हाल ही के निर्वाचनों में केवल 55 प्रतिशत मत डाले गये ;

(ख) क्या मतदाताओं द्वारा मतदान न करना इस बात का प्रमाण है कि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता से अनभिज्ञ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) मार्च, 1972 में हुए 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में गत साधारण निर्वाचनों में 59.57 प्रतिशत मतदान हुआ जब कि 1967 में 59.55 प्रतिशत हुआ था ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई अनुमान अपने अपने विचारों पर निर्भर करता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरठ सिटी स्टेशन पर मालडिब्बो से आयातित जस्ते की पिण्डों तथा पट्टियों की चोरी

3821. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1972 में मेरठ सिटी स्टेशन के यार्ड में तीन मालडिब्बों से 55,000 रुपये के मूल्य की आयातित जस्ते के पिण्डों तथा पटि्टयों की चोरी हो गई थी ;

(ख) क्या यह चोरी मेरठ सिटी रेलवे सुरक्षा दल के पर्यवेक्षी कर्मचारियों की सांठ–गाँठ अथवा उपेक्षा के कारण हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सियालदह से मेरठ के लिये बुक किये गये माल-डिब्बे में से टीन की 25 सिलियां, जिनका मूल्य लगभग 25,000 रुपये आंका गया है, कम पायी गयी थीं । मेरठ सिटी यार्ड में यह देखा गया कि इस मालडिब्बे का एक ओर का दरवाजा खुला हुआ है ।

(ख) उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये जांच जारी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Improvement in Compartments of Passenger Trains

3822. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a large number of compartments of passenger trains are not in good condition ;

(b) whether the overhead lights in a large number of 1st class compartments have been removed and a wooden board has been pasted in their place and blades of most of the fans do move. but do not give out air ;

(c) whether wash basins provided in bath-rooms, are such that water therefrom overflows and spreads in the entire bathroom;

(d) whether a large number of windows cannot be shut properly and because of that dust and coal particles continue to find their way into the compartments; and

(e) whether Government's attention has been drawn to the aforesaid defects, and if so, the time by which these are likely to be removed ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) to (d) No.

(e) Constant attention is paid to ensure that passenger coaches are maintained in good condition without any defect and deficiency.

Accumulation of Stocks Controlled Varieties of Cloths in Mills

3823. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government are aware that huge stocks of controlled varieties of cloth have piled up in the various textile mills as a result of heavy shrinkage in the off-take of cloth; and

(b) if so, the sanction proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No such information has come to the notice of Government.

(b) Does not arise.

Production Capacity of Gwalior Rayons

3824. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the annual production capacity of Gwalior Rayons located at Nagda (Madhya Pradesh).

(b) whether Government accorded approval to any proposal to increase its production capacity during the last two years;

(c) the percentage of requirements in the country met by the factory; and

(d) whether the goods produced by the factory are also exported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) According to Gwalior Rayons their annual production capacity is of the order of 62,000 tonnes.

(b) No, Sir.

(c) 77 percent.

(d) No, Sir.

व्यापार दल का इण्डोनेशिया का दौरा

3825. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किसी व्यापार दल ने इण्डोनेशिया का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो वहां किन-किन विषयों पर बातचीत हुई तथा क्या क्या निर्णय हुए ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हाल ही में किसी सरकारी व्यापार दल ने इंडोनेशिया का दौरा नहीं किया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय रेलवे द्वारा भाग लिया जाना

3826. **श्री गंगादेव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1972 में नई दिल्ली में होने वाले तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय रेलवे भी प्रमुख भाग लेने वालों में होगी ;

(ख) क्या इसमें वातानुकूलित भोजनयान भी दिखाया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा प्रदर्शनार्थ रखी जाने वाली वस्तुओं के बारे में मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां । भारतीय रेलें तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रमुख भाग लेने वालों में से एक है ।

(ख) वातानुकूल भोजन-यान प्रदर्शित करने पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) रेल मण्डप में प्रदर्शनार्थ रखी जाने वाली वस्तुएं मुख्यतः रेलों से सम्बन्धित होंगी जो इस प्रकार है :—

(1) स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारतीय रेलों का विकास ।

(2) चलस्टाक एवं अन्य सम्बद्ध उपस्करों के निर्माण में भारतीय रेलों द्वारा प्राप्त आत्म-निर्भरता ।

(3) विकासशील देशों के बाजारों में चल स्टाक और अन्य रेल उपस्करों के निर्यात की सम्भावनायें ।

(4) रेल उपयोगकर्त्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं में उत्तरोत्तर विकास ।

(5) कर्मचारी कल्याण-कार्य ।

Expenditure on International Trade Fair 1972

3827. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the amount to be spent by the Government of India on the preparations for the International Fair to be held in Delhi in 1972; and

(b) the extent of benefit and increase in trade likely to be derived therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) Ministry of Foreign Trade is likely to incur an expenditure of about Rs. 6 crores out of which permanent assets worth about Rs. 4 crores will be created.

(i) The direct income from the Fair will be about Rs. $3\frac{1}{2}$ crores;

(ii) The direct and indirect foreign exchange earnings are estimated to be around Rs. 8 crores ;

(iii) It will afford a good opportunity to project the correct image of India and show to the comity of nations the progress that India has made since Independence in the various fields like light and heavy engineering, small and large industries, chemicals and fertilisers, iron and steel, aeronautics, ship building and power and atomic energy etc. ;

(iv) The pavilions of foreign countries will enable us to take a comparative view of our performance and generate new ideas and unravel fresh possibilities for economic cooperation with developing Asians countries and with developed Asian and non-Asian countries ;

(v) The fair will provide a convenient opportunity for India to draw attention to its role and for other participating countries to examine ways and means of strengthening and expanding a practical programme of action based on an integrated strategy for regional economic cooperation; and

(vi) An assessment of direci trading activity the fair will generate can be made after the fair is over.

छोटा नागपुर बिहार में ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

3828. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में छोटा नागपुर (बिहार) में ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संस्थाओं में कितनी राशि उपलब्ध होगी;

(ख) क्या इस संबंध में छोटा नागपुर की अपेक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम को अब तक बिहार के छोटा नागपुर प्रमंडल में विद्युतीकरण के लिए बिहार राज्य

विद्युत बोर्ड से दो स्कीमें प्राप्त हुई हैं। इन दोनों स्कीमों की अनुमानित लागत लगभग 76 लाख रुपये हैं जिसमें से लगभग 34 लाख रुपये 1972–73 के दौरान उपलब्ध किये जाने होंगे। ये स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम में विचाराधीन हैं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने (कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन) कृषि वित्त निगम को छोटानागपुर से संबंधित ग्राम विद्युतिकरण की एक स्कीम प्रस्तुत की है। जिसके लिए 1972–73 में 36.48 लाख रुपये की राशि प्रत्याशित है। यह स्कीम कृषि वित्त निगम के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) ग्राम विद्युतीकरण के लिए वित्तीय निवेशों के मामले में छोटानागपुर की उपेक्षा नहीं की गई है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने छोटानागपुर में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 1970-71 तक 115 लाख रुपये व्यय किये हैं।

Commonwealth Conference in London

3829. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a Conference of Commonwealth Countries is going to be held in London during the month of April, 1972 with a view to taking a decision in regard to the attitude of Commonwealth Countries towards European countries after U. K.'s entry into the European Common Market; and

(b) if so, the attitude of the Government of India in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foregn Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir. A Conference of Senior Officials of the Commonwealth countries who are eligible for "associate" status with EEC under the Treaty of Accession was held in London on April 5-6-1972. India is not eligible for "associate" status with EEC, but, on invitation, had attended the Conference, as an observer.

(b) It is the intention of the Government of India to participate in similar Conferences in future.

दक्षिण कोरिया को मेंगनीज अयस्क का निर्यात

3830. **श्री कृष्ण मोदी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को दक्षिण कोरिया से मेंगनीज अयस्क के लिए क्रयादेश मिला है;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य का क्रयादेश मिला है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी हां,। लगभग 7.70 लाख रुपये मूल्य के लगभग 4500 मे० टन मैंगनीज अयस्क की सप्लाई के लिए एक आर्डर खनिज तथा धातु व्यापार निगम को दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुआ है। इस संविदा को अन्तिम रूप दिया जा रहा है

अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण लाईनों के लिए मध्य प्रदेश को आर्थिक सहायता

3831. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए 1971-72 में 1.99 करोड रुपये की आर्थिक सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन लाइनों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए आर्थिक सहायता दी गई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1971-72 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता के रूप में 111.77 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है, जिसको सम्मिलित करने से राज्य को 1969-70 से अबतक अन्तर्राज्यिक पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए दी गई वित्तीय सहायता की कुल रकम 1.9927 करोड़ रुपये हो जाते हैं।

(ख) 1969–70 से अब तक अन्तर्राज्यिक पारेषण लाइनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को दी गई वित्तीय सहायता के विवरण नीचे दिये जाती हैं :—

क्रम सं०	लाइन का नाम	स्वीकृत ऋण (लाख रुपये)		
		1969–70	1970–71	1971–72
1.	सतपुड़ा अम्बाजारी, 220 किलोवोल्ट एस/सी लाइन	25.00	62.50	24.00
2.	चांदनी–भूसावल, 132 किलोबोल्ट लाइन दूसरे सर्किट का तार खींचना	–	–	21.07
3.	रिहांद-मोर्वाअमरकंटक, 132 कि० वो० (दूसरे सर्किट का तार खींचना)	–	–	65.20
4.	बोधघाट-बलिमेला एस/सी लाइन 220 किलोवाट	–	–	1.50
	जोड़	25.00	65.50	111.77
	सकल जोड़			199.27

Sulphur supplied through M. M. T C. to various Countries

3832. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value of sulphur supplied to companies in various countries by the M.M.T.C. during the last two years; and

(b) the names, location and ownership of the said companies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए राशि का नियतन

3833. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए वर्ष 1971 में कितना धन दिया गया था; और

(ख) बिहार में बाढ़-नियंत्रण पर गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर 1971 में बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता उपायों तथा पुनः स्थापन कार्यों पर व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, वह 46.3 करोड़ रुपये है । इसमें से बिहार सरकार को व्यय की प्रगति के आधार पर 4 करोड़ रुपये के अनुदान सहित 20 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं ।

(ख) बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य-योजनाओं के अंग हैं । चौथी पंजवर्षीय योजना में अपनाई गई क्रियाविधि के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उनकी विविध निकास स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था ब्लाक-ऋणों और अनुदानों के रूप में की जाती है और किसी विषेश परियोजना या विकास शीर्ष से जुड़ी हुई नहीं होती है। अतः बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता पृथक रक्षित नहीं है और राज्य सरकारों को बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था करनी होती है ।

बिहार सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण पर निम्नलिखित धनराशि व्यय की है ।

1969–70.........224.5 लाख रुपये

1970–71.........241.8 ,, ,,

1971–72.........200.5 ,, ,, (प्रत्याशित)

आंध्र प्रदेश के गडप्पा जिले में पुलिवेन्डलाचैनल योजना की मंजूरी

3834. **श्री वाई० इश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने "पुलिवेन्डला चैनल योजना" गडप्पा जिला आंध्र प्रदेश को प्रारम्भ करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा आईजाकुतदारों पर लगाये गए अग्रिम समुन्नति शुल्क का इकट्ठा करना रोक दिया गया है और रद्द कर दिया गया है; और

(ग) सर्वदा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पड़ने वाली इस योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी और कार्य कब प्रारंभ होगा तथा इसपर कुल कितना अनुमानित व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी कोई सूचना अब तक आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार का 1972–73 के दौरान 2.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की परियोजना पर कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव है । राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है और वह किसी विशिष्ट सेक्टर अथवा परियोजना के साथ जुड़ी हुई नहीं होती । 1972–73 के लिए आंध्र प्रदेश की वार्षिक योजना 105 करोड़ रुपये की हैं जिसमें केन्द्रीय सहायता 46.56 करोड़ रुपये की है।

"सैक्यूलर एडोप्शन कोड"

3835. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सैक्यूलर एडोप्शन कोड, एन इमीजियेट नीड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस विषय पर एक व्यापक विधान बनाने के लिये उपाय किए जा रहे हैं ।

सालांदी परियोजना के प्राक्कलन

3836. **श्री कुमार माझी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सालांडी परियोजना के प्रारम्भिक प्राक्कलन क्या थे और उक्त परियोजना को अनुमानतः कितने समय के अंदर पूरा होना था; और

(ख) परियोजना कब आरंभ हुई थी और उस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) अक्तूबर 1969 में स्वीकृत 465.60 लाख रुपये की अनुमानित लागत की सालन्दी परियोजना के 1965

में पुर्ण हो जाने की आशा थी । स्कीम की संशोधित अनुमानित लागत के 1427.68 लाख रुपये होने का अनुमान है जिसमें से अबतक लगभग 1400 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं । बांध, बराज और मुख्य नहर पूरी की जा चुकी हैं । सिर्फ फाटक (गेट) का प्रतिष्ठापन और वितरण-प्रणाली के कुछ निर्माण-कार्य पूर्ण किये जाने बाकी हैं ।

सालांदी परियोजना के जलमग्न क्षेत्र के प्रभावित परीवारों को दिया गया मुआवजा

3837. **श्री कुमार माझी :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में सालांदी परियोजना के परिणामस्वरूप बहुत से परिवार जिनमें से अधिकांशत: आदिवासी हैं विस्थापित हो गए हैं;

(ख) परियोजना से प्रभावित प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए परिवारों को किस दर से मुआवजा दिया गया है;

(ग) कितने परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है और सरकार उनके दावों को कब तक निपटा देगी; और

(घ) क्या उन अनेक परिवारों के विरूद्ध जो अपने आवास के लिए पड़ती भूमि लेना चाहते थे, मामले दर्ज कर लिए गए है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आंध्र प्रदेश में काफी बोने की योजना

3838. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में काफी बोने की किन्हीं योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) आंध्र प्रदेश का वन विभाग 1960-61 से विशाखापत्तनम तथा पूर्व गोदावरी जिलों में काफी उगाने की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है । 1971 तक 1229 एकड़ क्षेत्र में काफी बोई गई । एक विस्तार कार्य क्रम के अन्तर्गत 1972-78 की अवधि के दौरान चिन्तापल्ली तथा पडेरू के 2025 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में काफी बोने का विचार है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ श्रीलंका से वापस आये 600 परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था होगी ।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य (जी० डी० आर०) के साथ व्यापार समझौता

3839. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ हाल ही में कोई व्यापार समझौता किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत सरकार तथाजर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की सरकार के बीच चार वर्षों (1972–75) की अवधि के लिए वैध एक व्यापार तथा भुगतान संलेख पर बर्लिन में 11 नवम्बर, 1971 को हस्ताक्षर किये गए थे। इस संलेख की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

चित्तूर जिले में संकट ग्रस्त मिलों को हाथ में लेना

3840. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर जिले में तिरुपति के पास रेनीगुण्टा स्थित सूती कपड़ा मिल को सरकार द्वारा हाथ में लेने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कुछ समय पूर्व ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें तिरुपति काटन मिल्स लि० रेनीगुण्टा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बारे में अनुरोध किया गया था। इस मामले की परिस्थितियों की पूरी तरह से जांच करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त की गई एक अन्वेषण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन की दक्षिण अमरीका की यात्रा

3841. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन ने वस्तुस्थिति के अध्ययन के लिए हाल ही में दक्षिण अमरीका का दौरा किया था और यदि हां, तो उनकी यात्रा पर कितना खर्च आया ;

(ख) क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप- मंत्री (श्री ए०सी०जार्ज) : (क) जी हां। वस्तु स्थिति के अध्ययन सम्बन्धी दौरे पर विदेशी मुद्रा में 5386.50 रु० तथा भारतीय मुद्रा में 22,101 रु० व्यय हुआ।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष द्वारा अपने दौरे के सम्बन्ध में दिये गये प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नोक्त हैं :—

(1) कि राज्य व्यापार निगम के न्युयार्क कार्यालय को भारत तथा दक्षिण अमरीका के बीच व्यापार के विकास की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

(2) कि एक छोटा व्यापार प्रतिनिधिमण्डल बाजार सम्बन्धी व्यापक जांच के लिए दक्षिणी अमरीका को भेजा जाए ;

(3) कि राज्य व्यापार निगम को दक्षिण अमरीका के व्यापारियों को भारत द्वारा निर्मित वस्तुओं को देखने के लिए भारत में आमन्त्रित करने के लिए अधिक उदार होना चाहिए ;

(4) कि एक समन्वय समिति, जो राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रायोजित की जा सकती है, विभिन्न भारतीय सरकारी अभिकरणों के बीच राज्य व्यापार निगम खनिज तथा धातु व्यापार निगम, इंजीनियर्स इंडिया, रूई निगम, जहाजरानी निगम और ऐसे सरकारी उपक्रमों के बीच, जो दक्षिणी अमरीका को निर्यात और उससे आयात करने में रुचि रखते हो, सक्रिय परामर्श तथा समन्वय करने हेतु स्थापित की जाये ; तथा

(5) कि राज्य व्यापार निगम में एक छोटा प्रबन्ध ग्रुप स्थापित किया जा सकता है जो दक्षिणी अमरीका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हो।

विश्व में हुए निर्यात व्यापार में भारत का भाग

3842. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में विश्व में हुए निर्यात-व्यापार में भारत का भाग बहुत कम रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात व्यापार में कमी होने के क्या कारण हैं और इसमें वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) विश्व व्यापार में भारत के भाग से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति बाह्य तथा आंतरिक, दोनों प्रकार के कारणों का प्रभाव पड़ा है। हमारी प्रमुख परम्परागत निर्यातों के लिए विश्व मांग कुछ कारणों से तेजी से नहीं बढ़ रही है। चाय जैसी वस्तुओं को गत कई वर्षों से आयातक देशों में मांग के मंद विकास बेशी उत्पादन तथा कम कीमत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पटसन माल के निर्यातों पर संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं के विकास तथा साथ ही भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान

से प्रतियोगिता का कुप्रभाव पड़ा था । अन्य विकासशील देशों में उनकी क्षमता के विकास तथा विकसित देशों में कोटा प्रतिबन्धों का हमारे सूती वस्त्रों के निर्यातों पर कुप्रभाव पड़ा है। देश के भीतर हाल में कुछ महत्वपूर्ण निविष्ट साधनों जैसे इस्पात आदि की कमी हो जाने से निर्यातों के विकास में रुकावट आई है। बहुत से देशों में औद्योगिक माल की मांग बढ़ रही है, परन्तु भारत के औद्योगिक उत्पादन का आधार इस मांग को पूरा करने के लिए अभी तक पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं हुआ है। कुछ वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन भी, जो हमारे निर्यात व्यापार में आती हैं अपर्याप्त रहा है और इसका हमारी निर्यात बेशियों पर कुप्रभाव पड़ा है ।

सरकार समय समय पर निर्यात संवर्धन करने तथा विश्व निर्यात में भारत का भाग बढ़ाने के उपाय करती रही हैं। निर्यात नीति संकल्प जो 30 जुलाई, 1970 को संसद के समक्ष रखा गया था, सरकार को निर्यात व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। निर्यात संवर्धन उपायों में प्रतिपूर्ति लाइसेंस योजनाओं द्वारा आयातित कच्चे माल की सप्लाई क्षमता अवरोधों को हटाया जाना, निर्यात शुल्क को समाप्त करना अथवा कम करना, आयात तथा निर्यात शुल्कों की वापसी आदि शामिल है।

New Railway Line between Jhanjharpur and Hasanpur in Darbhanga District.

3843. **Shri Ram Bhagat Paswan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to lay a new Railway line between Jhanjharpur and Hasanpur in Darbhanga District; and

(b) if so, when ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Sakri and Jhanjharpur are already connected by rail. A traffic survey is proposed to be undertaken for a rail link from Sakri to Hasanpur.

(b) The proposal will be further considered after the results of the proposed survey become known.

Auction of Condemned Railway Wagons in Ajmer

3844. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) how many times condemned Railway wagons were auctioned during the last year in Ajmer;

(b) the number of traders who purchased; and

(c) the rate at which the wagons were auctioned together with the number of wagons and the total sale proceeds thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Six times during 1971-72.

(b) 22.

(c) 540 wagons were auctioned at rates ranging from Rs. 500/- to Rs. 9,910/- per wagons; the total sale proceeds were Rs. 18,18,220/-.

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

3845. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या न्यायपालिका में से और प्रेक्टिस कर रहे वकीलों में से सीधी भर्ती द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कुछ प्रतिशतता निर्धारित है;

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायपालिका में से और प्रेक्टिस कर रहे वकीलों में से सीधी भर्ती द्वारा कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं ; और

(ग) इनमें से कितने न्यायाधीश अल्प संख्यक जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के थे ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं । बार और न्यायिक सेवा से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा कोई प्रतिशतता विहित या अनुज्ञात नहीं की गई है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर, बार और न्यायिक सेवा के सदस्यों के नामों पर विचार किया जाता है और ऐसा करते समय न्यायपीठ में विविध प्रकार के अनुभव का भी ध्यान रखा जाता है ।

(ख) वर्ष	बार से	न्यायिक सेवा से
1969	44	45
1970	46	30
1971	35	39
1972	22	16
(1. 4. 72 तक)	147	130

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Confirmation of Emyloyees working in Kota Division (Western Railway)

3846. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state **:**

(a) the number of temporary employees in Kota Division of the Western Railway;

(b) the period for which they have been holding temporary posts ; and

(c) whether there is any scheme to declare them permanent ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) 1539 as on 1.1.1972.

(b) Temporary employees with service of		No.
Less than 3 years		861
Between 3 to 5 years		277
Between 5 to 7 years	......	220
Between 7 to 10 years	......	147
More than 10 years		34

(c) A special drive has been instituted by the Railway Administration for conversion of temporary posts into permanent ones wherever justified and for confirmation of eligible staff.

R. M. S. Bogies.

3847. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railways have met the requirement of bogies for R. M. S.; and

(b) if so, the number of new bogies being manufactured for R. M. S.?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) ; (a) & (b) The requirements of R. M. S. are, by and laege, adequately met either in regular postal vans or in III class compartments. Arrangements have also been made for the construction of 135 postal vans.

केन्दुवाडीह पुलिस थाने की पुलिस द्वारा पूर्व रेलवे के कुसुन्डा ईस्ट कैबिन में से लीवरमैन को ले जाना

3848. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अक्तूबर, 1971 को कुसुन्डा ईस्ट कैबिन में 16 00 से 24.00 बजे की ड्यूटी पर काम करने वाले लीवरमैन को केन्दुवाडीह पुलिस थाने की पुलिस बिना रेल अधिकारी की आज्ञा के और रेल गाड़िया गुजारने की उसकी ड्युटी से उसे मुक्त कराये बिना बलात् ले गई जिससे असुरक्षित कार्य और दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) लीवरमैन रामेश्वर प्रसाद जिसे आक्रमण के एक मामले में अन्य छः आक्रमणकारियों के साथ पुलिस तलाश कर रही थी कुसुंडायार्ड मास्टर की इस हिदायत के बावजूद कि वह पुलिस स्टेशन में आकर अपने को हाजिर कर दे, गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। 7-10-71 को जब वह 16.00 बजे से 24.00 बजे तक ड्यूटी पर था तो वह बिहार राज्य के कॆंडुआडीह पुलिस स्टेशन की पुलिस द्वारा लगभग 19.30 बजे ईस्ट केबिन के पास आम सड़क पर गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वह ड्यूटी पर रहते हुए केबिन छोड़कर हाजतरफा करने का लिये चला गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद के डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट के कार्यालय (पूर्व रेलवे) के समक्ष बारी-बारी से (रिले) अनशन

3849. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद को डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति के आहवान पर 4 से 6 नवम्बर, 1971 तक धनबाद, पूर्व रेलवे, के डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट के कार्यालय के समक्ष रेल कर्मचारियों द्वारा बारी-बारी से (रिले) अनशन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनको शिकायतें तथा मांगे क्या थी और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) उनकी मुख्य मांगे निम्नलिखित थीं :—

(i) 3–2–71 से 10–2–71 तक की अवधि में धनबाद मंडल में हुई हड़ताल के सिलसिले में अदालती मामलों और निलम्बन आदेशों को वापिस लिया जाय।

(ii) उक्त हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को सेवा में व्यवधान क्षमा किया जाय।

(iii) उक्त हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाय।

(iv) रेलों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाय।

इन मांगों के सम्बन्ध में संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है :—

(i) धनबाद मंडल में हड़ताल के सिलसिले में पुलिस ने दस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मुकदमे अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं। सामान्य नियमों के अधीन इन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया हैं। इन मामलों के सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय को प्रतीक्षा करनी होगी।

(ii) गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने पर सेवा में स्वत: व्यवधान आ जाता है और यह व्यवधान प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर क्षमा किया जाता है।

(iii) गैरकानूनी हड़ताल की अवधि के लिए कोई वेतन स्वीकार्य नहीं है।

(iv) रेलों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है।

धनबाद में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपगृहों (आउट हाउसेस) का आवंटन

3850. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यहा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों ने अधिकारियों और निरीक्षकों के उपगृहों (आउट हाउसेस) का चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का आवंटन करने के लिए प्रशासन को कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) धनबाद में कितने उपगृहों (आउट हाउसेस) में रेलवे के कर्मचारी और बाहर के लोग रह रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए विशेष विभाग की स्थापना

3851. **श्री राम सहाय पांडे** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **रेल** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध उपाय सुझाने के लिये नियुक्त की गई समिति ने इस समस्या को रोकने के लिये राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न रेलवे जोनों पर विशेष विभाग स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिए गये सुझाव की मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध उपाय सुझाने के लिए किसी समिति की नियुक्ति नहीं की गयी। परन्तु रेल मंत्री और हरियाणा के मुख्य मंत्री के मार्ग-दर्शन में एक संयुक्त समिति गठित की गयी थी जिसमें रेलों के हरियाणा प्रदेश के अधिकारीगण शामिल थे। इस समिति का उद्देश्य हरियाणा राज्य में बिना टिकट यात्रा की बुराई को दूर करने के लिए उपाय करना था। इस समिति ने नवम्बर 1971 से लेकर $2\frac{1}{2}$ महीने तक हरियाणा राज्य में बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध एक अभियान चलाया। अपनी अन्तिम रिपोर्ट में अन्य उपायों के अतिरिक्त, इस समिति ने निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है:--

(क) इस तरह के अभियानों की आवधिकता निर्धारित करना।

(ख) अभियान कितने समय तक चले, इसका निर्धारण।

(ग) अतिरिक्त कर्मचारियों और मजिस्ट्रेटों की स्वीकृति और पर्याप्त प्रचार। बिना टिकट यात्रा की इस समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बजाय वर्तमान कर्मचारियों को ही पुनः नियोजित और समंजित करने का विचार है। विशेष कक्ष की स्थापना के लिए कोई शिफारिश नहीं की गयी है। जैसा कि सुझाव है अभियान समय-समय पर चलाये जाने का विचार है तथा पर्याप्त प्रचार व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

त्रिशूली परियोजना को नेपाल के हाथ में देना

3852. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा निर्मित त्रिशूली परियोजना को शीघ्र ही नेपाल को सौंपने का विचार है और यदि हाँ, तो कब ;

(ख) परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है ; और

(ग) क्या इस परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली में से कुछ भारत को भी दी जाएगी और यदि हां, तो उसकी माला कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालम में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां। त्रिसूली जल-विद्युत् परियोना को डिसिल्टिंग बेसिन के निर्माण के पूर्व हो जाने के पश्चात् जिसके पूर्ण होने में दो कार्य-ऋतुएं लगेंगी, नेपाल सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

(ख) परियोजना की प्रतिष्ठापित विद्युत्-जनन क्षमता 21 मैगावाट है।

(ग) जी, नहीं।

बंगला देश से व्यापार करने के लिए नेपाल को माल लाने-लेजाने की सुविधा देना

3853. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नेपाल को राधिकापुर के रास्ते बंगला से व्यापार करने के लिए माल लाने-लेजाने की सुविधा दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा नेपाल सरकार के विशेष अनुरोध पर दी गई है अथवा पिछले अगस्त में हुए भारत-नेपाल व्यापार करार के अनुसरण में ; और

(ग) नेपाल को इस सुविधा के देने से भारत को कितना लाभ होगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चावल तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की बंगला देश की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नेपाल तथा बंगला देश के बीच व्यापार को, पारस्परिक रूप से स्वीकृत तदर्थ प्रबन्धों के माध्यम से, सुकर बनाने की अपनी इच्छा प्रकट की है।

(ख) तथा (ग) नेपाल के व्यापार का विकास तथा विविधीकरण करने के लिए नेपाल को स्थलमार्ग प्रदान करने का प्रश्न एक पृथक मसला है। गत वर्ष व्यापार तथा परिवहन संधि पर हस्ताक्षर करते समय, नेपाल तथा भारत के बीच इस संबंध में सहमति हुई थी कि ऐसे स्थलमार्ग क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय सहयोग प्रबन्धों के माध्यम से उस समय दिये जायेंगे जब भारत तथा संबद्ध क्षेत्रीय सदस्य देशों के बीच व्यापार तथा परिवहन प्रबंध पारस्परिक रूप से संतोषजनक आधार पर हों।

राज्य व्यापार निगम के निर्यात और आयात कार्यों को पृथक-पृथक् करना

3854. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम के निर्यात और आयात संबंधी कार्यों को पृथक् करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और इसके क्या लाभ होंगे ; और

(ग) इस पर निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गाड़ियों में और वातानुकूलित डिब्बे जोड़ना

3855. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलों की गाड़ियों में और वातानुकूलित डिब्बे जोड़े जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष गाड़ियों में ऐसे कितने डिब्बे जोड़े गये और वे किस जौन में चलती हैं; और

(ग) क्या यह स्थायी तौर पर किया जा रहा है या अस्थायी तौर पर और यदि यह अस्थायी तौर पर किया जा रहा है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) परिक्षण के तौर पर 1-6-1972 से पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर 43/44 दार्जिलिंग मेल में सियालदह और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक पूरा वातानुकूलित डिब्बा चलाने का विचार है। पिछले वर्ष के दौरान निम्नलिखित सेवाएं चालू की गयी थीं :—

(i) उत्तर रेलवे पर 11 अप/12 डाउन हवड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस में नियमित रूप से सप्ताह में पांच दिन दिल्ली और इलाहाबाद के बीच एक वातानुकूलित डिब्बा।

(ii) उत्तर, मध्य और दक्षिण-मध्य रेलों पर गर्मी के महीनों के दौरान परीक्षण के रूप में 21 डाउन /22 अप एक्सप्रेस में नयी दिल्ली और हैदराबाद के बीच सप्ताह में दो बार एक वातानुकूलित डिब्बा।

(iii) उत्तर रेलवे पर 59 अप/60 डाउन श्रीनगर ऐक्सप्रेस में नयी दिल्ली और पठानकोट के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाले वातानुकूलित यान की सेवा 3-2-72 और 31-3-72 तक अतिरिक्त भीड़-भाड़ की निकासी के लिए बढ़ाकर दैनिक कर दी गयी थी।

Irrigation through Power Pumps in M. P.

3856. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had approved a scheme for irrigation through power pumps to be installed in Madhya Pradesh rivers and had sanctioned certain amount to the Madhya Pradesh Electricity Board for the purpose last year;

(b) if so, the broad outlines thereof ;

(c) whether the Betwa, Dhasan, Ur, Urmil and Kain rivers of Bondelkhand are also covered under this scheme ; and

(d) if so, the time by which the scheme is likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (d) During the Fourth Plan the emphasis in rural electrification schemes continues to be on the electrification of irrigation pumpsets for increasing agricultural production. These programmes include provision of power for river lift irrigation schemes. The Rural Electrification Corporation in the Central Sector provides additive finances to the States Electricity Boards for acceleration of rural electrification schemes. In respect of Madhya Pradesh, the Corporation has so far sanctioned 16 schemes envisaging loan assistance of Rs. 8.54 crores for the electrification of 37051 pumpsets and 759 villages. In respect of electrified lift irrigation schemes in the Bondelkhand area, the Corporation has sanctioned in 1971-72, one scheme envisaging loan assistance of Rs. 55 lakhs relating to the Dhasan river in Sagar District. This scheme is expected to be completed in about 5 years and on completion will provide electricity to 2000 pumpsets and 50 villages.

Survey of Orchha Project in Madhya Pradesh

3857. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether priliminary survey of Orchha power and irrigation project in Tikamgarh District, Madhya Pradesh has been conducted;

(b) if so, the estimated expenditure on the project, the quantum of power to be generated and the area to be irrigated thereby; and

(c) the time by which the work on the project is likely to start ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c) Survey work by the State authorities is in progress. The probable power output at Orchha would be about 70 MW and the area that could be irrigated about 12,000 hectares. The estimated cost of project and time by which work will start will be known as soon as the project report is finalised.

Sindh River Project Report

3858. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Water and Power Commission has received the project report of the Sindh river project (first phase) from the Government of Madhya Pradesh ; if so, when; and

(b) the time by which the said project is likely to be approved by the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) Yes, Sir. In January, 1971.

(b) The processing of the project is nearly complete and it is expected to be accepted for inclusion in the developmental plans of Madhya Pradesh in the near future.

अमरीका के साथ फिल्म करार का नवीकरण

3859. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष से भारत में दिखाई जाने वाली अमरीकी फिल्मों के लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी थे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अमरीका से फिल्मों का आयात करने के लिए भारत सरकार ने अमरीका के निगमित चलचित्र निर्यात संगम, बम्बई के साथ जो करार किया था वह 30 जून, 1971 को समाप्त हो गया अतः इस तारीख के पश्चात् अमरीका से फिल्मों का आयात करने के लिये कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया । इस प्रकार के लाइसेंसों के नवि-करण का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत के बारे में अनुसंधान योजना

3860. **श्री वी० मायावन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड ने अब तक विद्युत के बारे में अनुसंधान योजना से सम्बद्ध कार्य में कितनी प्रगति की है जो देश में 20 सिंचाई तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्रों पर लागू है ; और

(ख) इससे प्राप्त परिणामों को कब तक व्यावहारिक रूप दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड ने 1961-62 में अनुसंधान यूनिटें स्थापित करने के लिए एक आयोजित कार्यक्रम आरंभ किया था और इस समय इस स्कीम के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्डों की 15 यूनिटें और शिक्षा संस्थाओं की तीन यूनिटें अनुसंधान में लगी हुई हैं । इसमें विद्युत शक्ति के जनन, पारेषण और वितरण तडित्-संबंधी अध्ययनों तथा ग्राम विद्युतीकरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 12 समस्याएं भी सम्मि-लित हैं । अब तक कुछ मुख्य उपलब्धियां ये हैं– ट्रांस्फार्मर में निकले हुए बेकार तेल का पुनरुपयोग अतिरिक्त उच्च वोल्टता वाली पारेषण लाइनों के लिए बेहतर और किफायती डिजाइन तैयार करने

के लिए तडित् से होने वाली पारेषण लाइनों में गड़बड़ियों को रिकार्ड करने के वास्ते हुक-आन-टाइप क्लाइड़ोग्राफ का विकास, ग्राम विद्युतीकरण के लिए इकहरे तार वाली अर्थ-रिटर्न प्रणाली का प्रयोग, विद्युत प्रणालियों के लिए कई प्रकार के यंत्रों और रिलेज का अपने देश में ही विकास । इसके परिणाम राज्य बिजली बोर्डों को उपलब्ध करा दिये गये हैं ताकि विद्युत प्रणालियों के प्रचालन, अभिकल्प और निर्माण में उनका उपयोग किया जा सके ।

देश में विद्युत का मूल्यांकन

3861. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री एस० ए० मरूगनन्तम :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या देश में विद्युत उद्योग के बारे में हाल ही में मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) किन-किन क्षेत्रों और राज्यों में इसकी भारी कमी रही है और किन-किन क्षेत्रों और राज्यों में फालतु विद्युत का कोई तुरन्त लाभ नहीं उठाया जा रहा है तथा उसके कारण क्या हैं ;

(घ) इन असंतुलनों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) जी, हां । सातवीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति ने 1974-75 तक की क्षेत्रवार और राज्यवार विद्युत-मांगों और विद्युत उपलब्धता का मूल्यांकन कर लिया है।

(ख) सर्वेक्षण में ऐसा परिकल्पित है कि 1970-71 के अन्त तक की लगभग 10.8 मिलियन किलोवाट विद्युत की अखिल भारतीय पीक मांग 1974-75 के अन्त तक बढ़कर लगभग 17.7 मिलियन किलोवाट हो जाएगी। चौथी योजना के अन्त तक पीक भारों पर उपलब्ध विद्युत-जनन क्षमता की मात्रा कम हो जाएगी और तब त्वरित विद्युत विकास के प्रस्ताव जैसे-जैसे कार्यान्वित होते जाएंगे इसमें वृद्धि शुरू हो जाएगी ।

(ग) 1970-71 के दौरान, मुख्यत: उत्तरी क्षेत्र के पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश और जम्मू व काश्मीर राज्यों में विद्युत की कमी विकट रूप से अनुभव की गई ।

हरियाणा और पंजाब में ऊर्जा के उपभोग पर कटौती लागू की गई । 1970-71 में नेवेली विद्युत क्षेत्र में मुख्यत: अपर्याप्त लिग्नाइड की उपलभ्यता के कारण तमिलनाडु में किए गये कुछ भार वितरण (लोड़ शैडिंग) को छोड़कर देश में विद्युत की स्थिति संतोषजनक थी ।

1971-72 के दौरान मुख्यतः तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र में और कुछ हद तक नासिक तार केन्द्र में विद्युत जनन यूनिटों के मजबूरन बंद करने के कारण पश्चिमी क्षेत्र के गुजरात और महाराष्ट्र में भार-

वितरण (लोड़ शैडिंग) और ऊर्जा कटौती लागू की गई हैं। दक्षिणी क्षेत्र मुख्यतः मचकुंड जलाशय में निम्न जल स्थितियों और नेवेली में विद्युत के उत्पादन में कमी जोकि साधारण अनुसूची से बहुत कम है, के कारण आंध्र प्रदेश में पर्याप्त भार वितरण (लोडशैडिंग) का आश्रय लिया गया है। मचकुंड में निम्न जल स्थितियों के कारण दक्षिणी उड़ीसा में भी विद्युत सप्लाई की स्थिति खराब हो गई है जिसके परिणामस्वरूप उद्योगों में स्वेच्छा से कटौती की गई है। मुख्यतः श्रमिक झगड़े के परिणामस्वरूप नेवेली में विद्युत-जनन में कमी के कारण तमिल नाडु में कुछ सीमा तक भार वितरण (लोड शैडिंग) किया गया है। उत्तरी क्षेत्र पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी विद्युत सप्लाई की स्थिति असंतोषजनक है। इस समय पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश और दक्षिण क्षेत्र में केरल और मैसूर में कुछ फालतु विद्युत उपलब्ध है। भार आवश्यकताओं और पारेषण क्षमता के अधीन समस्त उपलब्ध फालतु विद्युत का समुपयोजन आस पास की प्रणालियों में किया जा रहा है।

(घ) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने दशाब्दी 1971-81 के लिए विद्युत विकास (विद्युत-जनन) के लिए एक योजना बनाई है जिसमें विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए निश्चित करते हुए विद्युत् विकास के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता को, ध्यान में रखा गया है। उपलभ्य विद्युत्-जनन सुविधाओं के पूर्ण समपयोजन को सुनिश्चित करने के लिए अन्तराज्यिक पारेषण पथों और भार प्रेषण सुविधाओं के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी किया गया है।

गुजरात को विद्युत की सप्लाई

3862. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वैकारिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में गुजरात में उद्योगों और कृषि के लिए विद्युत् की सप्लाई में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस समय तथा आगामी दो वर्षों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए गुजरात की कुल आवश्यकता का कोई मुल्यांकन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गुजरात में उद्योगों द्वारा विद्युत् ऊर्जा की खपत, जो 1968-69 के अंत में 2222 मिलियन यूनिट थी, 1970-71 के अंत तक बढ़-कर 2711 मिलियन यूनिट हो गई। उसी अवधि के दौरान कृषिगत क्षेत्र खपत की मात्रा 335 मिलियन यूनिट से बढ़कर 405 मिलियन यूनिट हो गई।

(ख) जी, हां। सातवें वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण ने इस समय और 1972-73 और 1973-74 के दौरान गुजरात में अबाधित पीक मांगों का अनुमान क्रमशः 800 मेगावाट, 950 मेगावाट और 1100 मेगावाट लगाया है। क्रमशः 1040 मेगावाट, 1230 मेगावाट और 1440 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता लाना आवश्यक होगा। इन आवश्यकताओं की तुलना में, उपलब्ध होने वाली संभावित प्रतिष्ठापित क्षमता के क्रमशः 880 मेगावाट (तारापुर से 200 मेगावाट अभी उपलब्ध नहीं हो रही है), 1162 मेगावाट और 1349 मेगावाट होने की आशा है।

गुजरात के गांवों में पारेषण लाइनों का विस्तार

3863. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम विद्युतीकरण निगम ने गांवों में पारेषण लाइनों के विस्तार के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) गुजरात के किन गांवों में अब तक बिजली पहुंचायी गयी है और चालू वर्ष में किन गांवों में बिजली पहुंचायी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम से जिन ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं को सामान्यतः वित्तीय सहायता मिल सकती हैं उनकी लागत में ये चीजें शामिल होती हैं– उपकेन्द्रों से वितरण ट्रांस्फार्मरों तक पारेषण प्रणाली का विस्तार, 11 के० वी० से स्टेप-डाउन उपभोक्ता प्वाइंटों तक वितरण लाइनों का विस्तार और पम्पसेट/नलकूपों को सर्विस कनेक्शन उन राज्य बिजली बोर्डों अर्थात असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जहां पर ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम है, निगम ने ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति में तेजी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च वोल्टता पारेषण जाल-प्रणाली के विस्तार के लिए ऋण-सहायता की व्यवस्था करने की एक विशेष स्कीम शुरू की है। अब तक निगम ने गुजरात बिजली बोर्ड को 13 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकृति दी है जिसमें 661 ग्रामों और 21412 पम्पसेटों के विद्युतीकरण के लिए 7.92 करोड़ रुपये की ऋण-सहायता परिकल्पित है ।

(ख) 4706 ग्रामों में, जोकि कुल (18584 ग्रामों) का 25.4% है, मार्च, 1972 के अन्त तक गुजरात में बिजली लग चुकी है जबकि अखिल भारतीय औसत 20.7 % है। 1972-73 के दौरान 500 और ग्रामों में बिजली लगने की सम्भावना है।

गुजरात के नमक निर्माताओं को वैगनों की सप्लाई

3864. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के नमक निर्माताओं को वैगनों की अनियमित सप्लाई के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) उच्चतर प्राथमिकता वाले यातायात का संचलन तरजीही रूप से करने के लिए रेलों द्वारा किये गये वादों के समनुरूप नमक के यातायात की यथासंभव शीघ्र निकासी के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है । वर्ष 1971-72 के दौरान गुजरात के स्टेशनों से बड़ी लाइन के 31,569 और मीटर लाइन के 40,474 माल डिब्बों में नमक लादा गया था ।

3865. **श्री एस० बी० गिरि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विद्युतीकरण परियोजनाओं (दक्षिण-मध्य रेलवे) के लिए मुख्य विद्युत इंजीनियर का नया मुख्यालय

(क) क्या मद्रास से विजयवाड़ा तक की विद्युतीकरण परियोजना का अधिकांश भाग दक्षिण-मध्य जौन में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण-मध्य जौन का महाप्रबंधक इस कार्य का सर्वोच्च प्रभारी होगा; और

(ग) मुख्य विद्युत इंजीनियरिंग का मुख्यालय कहां होगा जो इस वास्तविक कार्य का प्रभारी अधिकारी होगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) विजयवाड़ा ।

भीमडोल और सीतमपेट रेलवे स्टेशनों (दक्षिण-मध्य रेलवे) के बीच रेल फाटक पर नीचे का एक पुल बनाना

3866. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम गोदावरी सहकारी चीनी मिल लिमिटेड ने रेलवे प्रशासन से मद्रास से कलकत्ता तक की मुख्य सड़क पर दक्षिण-मध्य रेलव के विजयवाड़ा डिवीजन में भीमडौल और सीतमपेट रेलवे स्टेशनों के बीच रेल फाटक पर एक नीचे का पुल बनाने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी/नीचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किये जाने होते हैं और उसके साथ उन्हें अपने हिस्से का खर्च वहन करने का भी वचन देना होता है । अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रायोजित नहीं किया गया है । रेल प्रशासन तभी कोई कार्रवाई कर सकता है जब राज्य सरकार द्वारा इस तरह का प्रस्ताव प्रायोजित कर दिया जाय ।

Construction of an over-bridge at Banda Railway Station.

3867. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for the construction of an overbridge at Banda Railway Station on Jhansi-Manikpur line of Central Railway ; and

(b) if so, the time by which it will be completed ?

The Minister for Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

अहमदाबाद के लिए सर्क्युलर/ट्यूब रेलवे

3868. **श्री वैकारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद नगर के लिए सर्युक्लर/ट्यूब रेलवे के संबंध में सर्वेक्षण करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदाबाद मेल/एक्सप्रेस गाड़ी के साथ तीसरी श्रेणी का शयन-यान का जोड़ना

3869. **श्री वैकारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद मेल/एक्सप्रेस गाड़ी के साथ दिल्ली से सौराष्ट्र के लिए तीसरी श्रेणी का कोई शयनयान नहीं जोड़ा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, ।

(ख) 1 अप / 2 डाउन दिल्ली– अहमदाबाद मेल गाड़ी में स्थानाभाव के कारण ।

(ग) 1-5-72 से 1 अप / 2 डाउन दिल्ली–अहमदाबाद मेल का डीजलीकरण करके दिल्ली और ओखा के बीच एक तीसरे दर्जे का 2 टियर शयनयान चलाने का प्रस्ताव है ।

गुजरात में सिंचाई योजनाओं सम्बंधी परियोजना प्रतिवेदन

3870. **श्री वैकारिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की विभिन्न सिंचाई योजनाओं संबंधी परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गए है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख) चौथी योजना के दौरान गुजरात में निम्नलिखित नई परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है:—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (एकड़)
1. साबरमती जलाशय	1758.56	91,000
2. बजाज-सागर	1765.83	माही परियोजना के अंतर्गत
3. पानम्	684.78	54,670
4. मधुवन्ती सिंचाई स्कीम	51.81	5,297
5. झंजेश्वरी सिंचाई स्कीम	65.72	4,130
6. धारी सिंचाई स्कीम	28.85	2,000
7. खारीकट नहर प्रणाली	27.41	10,200

राज्य सरकार ने भी निम्नलिखित नई परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं, जिनकी तकनीकी जांच की जा रही है :

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (एकड़)
1. दमनगंगा	1738.76	1,15,000
2. सिपू	394.66	62,500
3. कालिन्द्री	46.31	3,900
4. फोक्ल	165.53	10,000
5. दातारवाडी	108.22	6,100
6. मादर	417.29	42,400
7. बगद	74.66	3,800
8. नारा	77.97	2,700
9. मोज बांध	54.89	13,500
10. सोरठी	65.72	4,600
11. वात्रक	295.63	36,000
12. छपरवाडी स्कीम	149.57	9,300
13. मछन नाला स्कीम	89.03	8,600

राजस्थान में असिंचित भूमि

3871. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ;

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान कितनी भूमि की सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) राजस्थान में कुल फसली क्षेत्र लगभग 143 लाख हेक्टेयर है जिसमें से इस समय बृहत, मध्यम और लघु सिंचाई के अन्तर्गत लगभग 25.6 लाख हेक्टेयर को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हैं । चौथी योजना के अन्त में इस क्षेत्र के 27 लाख हेक्टेयर तक बढ जाने की प्रत्याशा हैं ।

राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती हैं और वह किसी सेक्टर या परियोजना से जुड़ी हुई नहीं होती । राजस्थान का चौथी योजना परिव्यय 302 करोड़ रुपये का है जिसमें केन्द्रीय सहायता 220 करोड़ रुपये है ।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान नहर परियोजना पर कार्यों को तेज करने के लिए 6.2 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी गई थी ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के बेलाडिला-कोटा वलसा सेक्शन पर पैसेंजर गाड़ी चलाना

3872. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के बेलाडिला-कोटा वलसा सेक्शन पर कमर्शियल गुड्स तथा पैसेंजर यातायात चालू किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां । इस लाइन को वाणिज्यिक यातायात के लिए खोलने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस लाइन की क्षमता केवल इतनी ही है कि उसका उपयोग निर्यात होने वाले अयस्क यातायात के संचलन के लिए ही किया जा सकता है जिसके लिए यह लाइन मुख्यतः बनायी गयी थी। उस खण्ड का विद्युतीकरण भी किया जा रहा है। विद्युतीकरण से सम्बन्धित काम के

कारण क्षमता में फिलहाल कुछ और गिरावट आयेगी। इस कारण वाणिज्यिक यातायात के लिए इस लाइन को खोलना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। फिर भी, वैलाडिल्ला-कोइटवलासा लाइन की क्षमता में अपेक्षित स्तर तक वृद्धि करने के प्रयोजन से दक्षिण पूर्व रेलवे को तत्काल सर्वेक्षण करने को कहा गया है।

सरकारी परियोजनाओं द्वारा किया गया निर्यात

3873. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक परियोजना द्वारा वर्ष 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के दौरान किये गये निर्यात का मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मोटी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मुख्यतः देश से निर्यात में लगे हुए सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के निर्यात निष्पादन का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। निर्यात व्यापार में उनका भाग उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकट होता है :—

	अभिकरण का नाम	अनुमानित निर्यात		
		1969–70	1970–71	1971–72
		(करोड़ रुपये में)		
1.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम	91	105	97
2.	राज्य व्यापार निगम (परियोजना तथा उपस्कर निगम सहित)	55	71	73
3.	हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम	2.24	3.51	4.30
4.	भारतीय चलचित्र निर्यात निगम	0.32	0.47	0.60
5.	काजू निगम	—	—	0.22

वच्छाघाट और जड़ाऊ हरभंगी परियोजना प्रतिवेदन

3874. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वच्छाघाट और जड़ाऊ हरभंगी योजनाओं की परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को मिल चुकी हैं ; और

(ख) क्या इन पर कार्य इसी वर्ष आरम्भ हो जाएगा ।

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील,) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को जोर-हरभंगी परियोजना प्राप्त हो गई है और उसने इसकी जांच कर ली है। राज्य सरकार से केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की कुछ टिप्पणियों के उत्तर प्रतीक्षित है। इसके कार्यान्वयन का कार्य सिर्फ तभी शुरू किया जा सकता है, जब राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो जाएं और योजना आयोग परियोजना पर विचार कर ले । उड़ीसा सरकार से वच्छाघाट परि-योजना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

कानूनी व्यवस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव

3875. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानूनी व्यवस्था को अधिक सस्ता बनाने हेतु इस के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं ।

विधि व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 मुख्यतः मुकदमों का खर्च कम करने और विलम्ब से बचने की दृष्टि से पुनः परीक्षा के लिए विधि आयोग को निर्दिष्ट की गई है ।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना

3876. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की प्रगति के बारे में 14 मार्च, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार की नव-निर्वाचित सरकार के साथ इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के बारे में कोई विचार विमर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नेपाल की सीमा में पड़ने वाली इस परियोजना का खर्चा उठाने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बिहार सरकार भी परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए इच्छुक है और उसने नहर के प्रथम 22 मीलों में कार्यों के लिए राज्य योजना के ढांचे से बाहर

कुछ विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है । ऐसी विशेष सहायता की व्यवस्था की संभाव्यता की जांच की जा रही है।

अमरीका को भारतीय फिल्मों का निर्यात करने के लिए पारस्परिक व्यवस्था

3877. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, अमरीका को भारतीय फिल्मों का निर्यात करने और भारत में अमरीकी फिल्मों का आयात करने के लिए कोई पारस्परिक व्यवस्था करने हेतु कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की रूप रेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अमरीकी फिल्मों के आयात के लिए अमरीका के चलचित्र निर्यात संगम के साथ हुए करार की अवधि 30.6.1971 को समाप्त हो गई तथा उसका नवीकरण नहीं किया गया है । राज्य व्यापार निगम के माध्यम से, संभाव्य सीमा तक, पारस्परिकता के आधार पर आयात करने के वैकल्पिक प्रबंध किये जा रहे हैं ।

परिसमाप्त हुई कपड़ा मिलें

3878. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी कपड़ा मिलों का परिसमापन हो गया है ;

(ख) इन कपड़ा मिलों में कुल कितनी सरकारी पूंजी लगी थी ; और

(ग) बंद मिलों से अपनी पूंजी वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

असम के चाय बागानों की समस्याएं

3879. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के चाय बागानों के समक्ष अनेक समस्याएं हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन की जानकारी दी गई है ; और यदि हां, तो इनकी रूप रेखा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस उद्योग की प्रगति के लिए उत्पादन शुल्क में तुरंत कमी करने का अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी हां। आसाम को मिलाकर संपूर्ण भारत में चाय उद्योग की समस्याएं बढ़ती हुई लागतों, घटती हुई लाभ की मात्रा और उत्पादन शुल्क के भार के बारे में हैं। सरकार इन का बराबर पुनरीक्षण कर रही है।

रुई के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध

3880. **श्री पी० के० देव** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रुई के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी तथा कितने मूल्य की रुई का आयात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) रुई के आयात उसकी कुल उपलब्धता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विनियमित किये जाते है। विभिन्न कारणों से उसके आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं होगा।

(ग) (सितम्बर—अगस्त)

1968—69		1969—70		1970—71	
मात्रा लाख गांठों में	मूल्य करोड़ रुपये में	मात्रा लाख गांठों में	मूल्य करोड़ रुपये में	मात्रा लाख गांठों में	मूल्य करोड़ रुपये में
4.29	58.92	9.03	112.45	8.52	109.85

Scheme to Protect Villages from floods Erosion on banks of Ganga river.

3881. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated to save villages on the banks of the Ganga River particularly in the Diyara area and Bhagalpur and Monghyr Districts of Bihar from the floods and erosion; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) The following schemes have been formulated by the Government of Bihar for the protection of Dhiara and other area in Monghyr District against floods and erosion:

(1) A Pilot Scheme for development of Binda Diara on the right bank of the Ganga envisaging the construction of raised platforms, tubewells for irrigation and drinking water supply and providing electric supply for domestic & other purposes at an estimated cost of Rs. 25 lakhs.

(2) A scheme for repair and strengthning of 5 existing spurs for the protection of Mansi area on the left bank of Ganga at a cost of Rs. 22.6 lakhs.

(3) A scheme for strengthening of 4 existing spurs and constructing one new spur for protection against erosion in the Mansi area on the left bank of Ganga at a cost of Rs. 43 lakhs.

The implementation of scheme (1) and (3) above is under consideration of the State Government. Scheme (2) is under execution and is likely to be completed before the floods of 1972.

No scheme has yet been formulated for the areas in Bhagalpur district.

Conversion to Broad Guage Line from Barauni to Katihar (North Eastern Railway)

3882. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the metre-guage line from Barauni to Katihar on the North Eastern Railway is also included in the scheme for conversion of metre guage lines into broad guage lines; and

(b) if so, when this work is likely to be undertaken ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b) Conversion of Barabanki-Samastipur (Barauni) metre guage section into broad guage has been approved and included in the 1972-73 Budget. Conversion of Barauni-Katihar metre guage section into broad guage will be considered at a later stage.

Suspension of cargo ship between Bhagalpur and Mahadevpur Ghat (Ne. Railway)

3883. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether booking of the goods traffic at Bhagalpur Railway Station on North Eastern Railway and the operation of the Cargo Ship meant for transportation of wagons between Bhagalpur and Mahadevpur Ghat have been suspended;

(b) if so, whether the difficulties of the traders and farmers of North Bhagalpur, North Monghyr, Saharsa and Purnea Districts have greately increased as a result thereof; and

(c) whether the farmers and traders of the said region will have to send thier goods *via* Barauni and Farakka and consequently pay higher freight ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) This transhipment point has been closed for goods traffic after the opening of B. G. line across Farakka which has not only made movement to North Eastern region stable and fluid, but has released considerable capacity for transhipment at Garhara. The difficulties of traders and farmers of North Bhagalpur, North Monghyr, Saharsa and Purnea districts have not increased as a result of this closure as capacity of this transhipment point had been seriously affected due to very unfavourable riverine conditions between Mahadevpurghat and Bararighat consequent on which movement over this section was subject to frequent restrictions even before the closure. The traffic to M. G. sections in Bihar is now moving more regularly *via* Farakka and also *via* Garhara.

(c) A portion of traffic originating on the Thanabihpur—Katihar section on the North Eastern Railway and traffic originating on the Bhagalpur—Farakka section of the Eastern Railway will have to pay slightly higher freight with the closure of the ferry services at Bhagalpur. However, the volume of this traffic is in-significant being only about 6— of the previously moving by this transhipment point and movement by the alternative routes is faster and therefore more convenient for the trade.

Operating of Private Steamer Service in Bhagalpur, Barari and Mahadevpur Ghat (North Eastern Railway)

3884. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Railways propose to operate the private steamer service in Bhagalpur, Barari and Mahadevpur Ghat in North-Eastern Railway; and

(b) if so, the reasons therefor

The Minister of Railways (Shri K Hanumanthaiya) (a) No.

(b) Does not arise.

बिना टिकट यात्रा करने, खतरे की जंजीर खींचने और रेलवे में चोरी को रोकने के लिये अभियान चलाने हेतु सामाजिक शिक्षा के लिये संस्था

3885. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा करने, खतरे की जंजीर खींचने और रेलवे की सम्पत्ति की चोरी की समस्याओं के विरुद्ध सामाजिक शिक्षा के अभियान को बल देने के लिए एक संस्था खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में पूंजी निवेश

3886. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री वयालार रवि :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशों में पूंजी निवेशित कर रखी है और देश से बाहर संयंत्र एवं कारखाने स्थापित किये हुए हैं ;

(ख) क्या लाभ का भारत को प्रत्यावर्तन करने के स्थान पर भारतीय उद्योगपति विदेशों में धन जमा कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जिन भारतीय उद्योगपतियों ने देश के बाहर 29 संयंत्र और कारखाने स्थापित किये हैं तथा जिन्होंने उत्पादन कार्य आरंभ कर दिया है, उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त 67 अन्य संयुक्त उद्यम हैं जो सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं और क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सहयोग के क्षेत्र	भारतीय सहयोगी का नाम
1	2
इथोपिया	
1. वस्त्र मिल	मैसर्स बिरला ब्रदर्स (प्रा०) कलकत्ता।
2 साबुन कारखाना	मैसर्स बम्बई सोप फैक्टरी, बम्बई।
3. ऊनी वस्त्र मिल	मैसर्स डंकन ब्रदर्स एण्ड कं० कलकत्ता।

1	2
कीनिया	
4. वस्त्र मिल	श्री आर० एम० गोकुलदास, बम्बई।
5. ग्राइप वाटर संयंत्र	मैसर्स के० टी० डोंगरे एण्ड कं०(प्रा०)लि०, बम्बई
6. ऊनी वस्त्र मिल	मैसर्स रेमण्ड वुलन मिल्स लि०, बम्बई।
7. लाइट इंजीनियरी काम्प्लैक्स	मैसर्स एच० एल० मल्होत्रा एंड संस (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
8. कार्क कारखाना	मैसर्स इंडियन कार्क मिल्स, बम्बई।
लीबिया	
9. पाइप बनाने का कारखाना	मैसर्स इंडियन ह्यूम पाइप कं० लि०, बम्बई।
मारीशस	
10. पच्चीकारी वाली टाइलें और रोलिंग बनाने का कारखाना	मैसर्स सिद्धार्थ जसुभाई, अहमदाबाद।
नाइजीरिया	
11. इंजीनियरी सामान	मैसर्स बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
12. सालवैन्ट एक्सटैन्शन संयंत्र	मैसर्स बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
13. रेज़र ब्लेड कारखाना	मैसर्स एच० एल० मल्होत्रा एंड संस, कलकत्ता।
उगांडा	
14. पटसन मिल	मैसर्स बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
श्रीलंका	
15. सिलाई की मशीनें	मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता।
16. ग्लास फैक्टरी	मैसर्स स्वास्तिक ग्लास वर्क्स, चन्द्रपुर।
17. पी वी सी लैदर क्लाथ का उत्पादन	मैसर्स भोर इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बम्बई।
ईरान	
18. फालतू हिस्सों तथा मोटर गाड़ियों के संघटकों का उत्पादन	मैसर्स महेन्द्र एण्ड महेन्द्र, बम्बई।

1	2
मलयेशिया	
19. इस्पात के फर्नीचर का उत्पादन	मैसर्स गोदरेज एंड बोइस मैन्यु कं० बम्बई ।
20. कनफैक्शनरी यूनिट	मैसर्स पैरी कनफैक्शनरी लि०, मद्रास ।
21. सूक्ष्म औजार तथा गेज़ बनाने का कारखाना	मैसर्स गुप्ता मशीन टूल्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
22. वस्त्र मिल	मैसर्स बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
सिंगापुर	
23. मोटर गाड़ियों के सहसाधन	मैसर्स टेकसंरा (प्रा०) लि०, बम्बई ।
थाईलैंड	
24. संश्लिष्ट रेशे की कताई का संयंत्र	मैसर्स बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
आयरलैंड	
25. गुच्छेदार कालीन के धागे का उत्पादन	मैसर्स मफतलाल गागलभाई, बम्बई ।
ब्रिटेन	
26. असबसटास सीमेंट उत्पाद संयंत्र	मैसर्स बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि० कलकत्ता ।
कनाडा	
27. गत्ता कारखाना	मैसर्स अनिल हार्डबोर्ड लि०, बम्बई ।
पश्चिम जर्मनी	
28. तेल के इंजनों, चावल कूटने की मशीनों आदि का उत्पादन	मैसर्स किर्लोसकर आयल इंजनस, पूना ।
29. होज क्लिपों का उत्पादन	श्री एन० कृष्णनन, बंगलौर ।

Construction of shed at Shamgarh Railway Station (Western Railway)

3887. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the need for a shed for the convenience of passengers at Shamgarh Railway Station on Western Railway; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Railway (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b) A IIIrd class waitinghall measuring 14.48 M X 9.60 M already exists at Shamgarh Station which is considered adequate to meet the requirements of the passengers dealt with at this station.

Trade between India and G. D. R.

3888. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Foreigd Trade** be pleased to state :

(a) the value of goods exported to and imported from German Democratic Republic during the last two years; and

(b) the extent of increase in the trade between the two countries during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) The requisite information is as follows :—

(Rupees in lakhs)

Year	India's imports from the GDR	India's exports to GDR	Total Volume of trade
1969	2228	1927	4155
1970	2143	2235	4378
1971 (Jan-Sept.)	1500	1832	3332

It will be seen from the above table that there was an increase of Rs. 223 lakhs in the total volume of trade between India and the German Democratic Republic during 1970 over 1969.

Increase in export of Chemical Pharmaceuticals and Plastics to U. K.

3889. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the percentage of increase in the export of chemicals, pharmaceuticals and plastics to U. K. during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : The information is furnished below :—

(Value in lakhs of rupees)

Year	Exports	Percentage of increase over the previous year exports.
1968-69	129	
1969-70	163	26%
1970-71	171	5%

स्टोर डिपुओं और रेलवे स्टेशनों (दक्षिण रेलवे) के बीच का फासला

3890. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री स्टोर डिपुओं द्वारा एर्नाकुलम और त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशनों की सेवा के बारे में 28 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1247 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सप्लाई स्टोरों और स्टेशनों के बीच काफी लम्बा फासला होने से राज्य में रेलवे की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या केरल में एक स्टोर डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) आम स्टोर डिपो स्थापित करने के लिए साधारणतया क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सामान्य भण्डार डिपुओं की स्थापना के लिए सामान्य कसौटी यह है :

(1) संभरण संस्थापनों से उनकी सन्निकटता ।

(2) डिपुओं और उनके द्वारा सेवित क्षेत्रों के बीच परिवहन की सुविधाएं ।

(3) विभिन्न खपत स्थलों की तुलना में डिपो की केन्द्रीय स्थिति ।

Abolition of posts in Divisional Railway Hospital, Delhi (Northern Railway)

3891. **Shri B. S. Chowhan** : : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some posts have been abolished in the Divisional Railway Hospital, Delhi last year;

(b) if so, the categories of such posts;

(c) the reasons for abolishing them; and

(d) whether the employees working on those posts have since been transferred; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) ; (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Tabte of the Sabha.

Supply of water for Hulgu river for Irrigation purposes

3892. **Shri Ishwar Chaudhary** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Hulgu river is a seasonal river;

(b) whether Government propose to formulate any scheme to make it a perennial river; and

(c) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sbri B. N. Kureel) : (a) to (c) Like other rivers in South Bihar, Phalgu river in Gaya District is seasonal in nature.

The Baksha Dam is currently under construction in the basin of this river. The Government of Bihar are also investigating the possibility of the Mohane Dam.

Arrest of R. P. F. Constables at Siliguri (Northern Frontier Railway)

3893. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether two R. P. F. Constables were arrested at Siliguri while breaking open the railway wagon on about 1st April, 1972; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railway (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No. They were two pointsmen who were arrested.

(b) They were arrested and the case under Railway Property (Unlawful Possession) Act against them is under investigation.

Thermal Power Plant in Bihar

3894. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the question of setting up a Thermal Power Station between Chakia and Motipur for regular supply of electricity in North Bihar to meet the requirements of electricity of Champaran and Saran districts; and

(b) if so, the action taken in that direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) & (b) A scheme for setting up a 220/240 MW thermal power station at a site near Muzaffarpur in North Bihar at an estimated cost of Rs. 46.68 crores has been prepared. It has since been examined in detail, and cleared through the Advisory Committee of the Planning Commission set up for the clearing power projects. The railways have been approached for provision of broad guage line required for transport of coal and have confirmed inclusion of this in their programme.

Broad Guage Line from Samastipur to Raxaul via Darbhanga.

3895. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the reasons for which Government have given priority to the construction of broad guage line from Samastipur to Raxaul *via* Darbhanga in preference to the other route *via* Muzaffarpur ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : No priority is being given to the conversion *via* Darbhanga.

Non-Stopping of Trains at Halt Station at Nariar Pannapur Village (North East Railway)

3896. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether trains do not stop at the Halt Station at Nariar Pannapur Village between Kanti and Motipur Stations on Muzaffarpur and Narkatiaganj railway line on the North East Railway; and

(b) if so, the reasons therefor and by what time trains would start stopping there ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) There is no such halt station between Kanti and Motipur stations at present. It is proposed to open a train halt between Kanti and Motipur stations. Earth work which was to be completed through 'Shramdan' was left incompleted due to dispute over the name of the proposed train halt. The Mukhia has since promised to complete the earthwork by 'Shramdan' quickly and trains will stop at this halt as soon as earth-work is complete.

Broad Guage Line from Gorakhpur to Raxaul (North Eastern Railway)

3897. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have worked out the comparative cost of construction of a broad guage railway line from Gorakhpur to Raxaul on North Eastern Railway by constructing a bridge over Narayani river near Baganh and of a railway line on Gorakhpur-Chupra-Muzaffarpur route; and

(b) if so, which line is likely to cost more ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

जल-विज्ञान और मौसम विज्ञान के संभाग लक्षणों के दस सब–जोनों से सम्बद्ध प्रारूप प्रतिवेदन

3898. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल-विज्ञान और मौसम विज्ञान के सभांग लक्षणों के दस सब-जोनों से सम्बद्ध कितने प्रारूप प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) शेष प्रारूप प्रतिवेदनों को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ;

(ग) शेष 17 उप-डिवीजनों से सम्बद्ध आंकड़ों का विश्लेषण कब तक करने का कार्यक्रम हैं ; और

(घ) जिन प्रतीदवेनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है उनके बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) शायद माननीय सदस्य का आशय देश के विभिन्न भागों में पुलों के लिए डिजाइन बाढ़ों के प्राक्कलन पर रिपोर्ट तैयार करने से है। इस प्रयोजन के लिए देश को समान जल वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक लक्षणों के 27 उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर लिया है और अब तक नौ उप क्षेत्रों की अंतरिम रिपोर्ट तैयार

कर ली हैं। रेलवे और परिवहन मंत्रालयों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर इन रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जाना है। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और अन्य 18 उप क्षेत्रों के लिये रिपोर्ट तैयार करने के निमित्त और आंकडे इकठ्ठे किये जा रहे हैं। बहरहाल, उपलब्ध आंकड़ों से केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने देश के विभिन्न भागों में पुलों के डिजाइन के लिए 50 वर्ष को आवृत्ति बाढ़ पीकों के प्राक्कलन की प्रक्रिया के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। रेल मंत्रालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सलाह से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसके पश्चात् इसे पुल अभिकल्प से सम्बद्ध इंजीनियरों के उपयोग के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा। विभिन्न उपक्षेत्रों के लिए रिपोर्टों के मामले में इसी तरह की प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव है।

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों के लिये मंजूर की गई योजनायें

3899. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों की मंजूर की गई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) निगम द्वारा मंजूरशुदा योजनाओं के लिये निधि का उचित उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेजनाथ कुरील) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने जुलाई, 1969 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक सभी राज्य बिजली बोर्डों की 5 पायलट ग्राम बिजली सहकारी संस्थाओं और 206 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को मंजूरी दी है। इन स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा उपाबंध-एक में दिया गया है।

(ख) विविध स्कीमों पर प्रत्यक्ष प्रगति और वित्तीय परिव्ययों को बताते हुए आवधिक विवरणियाँ, जिनके लिए ऋण मंजूर किए जा चुके हैं, ग्राम विद्युतीकरण निगम से आती रहती हैं। ऋण की दूसरी और इसके बाद की किस्तों की स्वीकृति तब दी जाती है जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि स्कीमों पर उचित मात्रा में प्रगति हुई है। निर्माण-कार्यों की प्रगति का पुनरावलोकन करने के लिए और इन स्कीमों से संबंधित लेखों का निरीक्षण करने के लिए निगम के अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा भी करते हैं।

विवरण

31 मार्च, 1972 को ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्कीमों की कुल संख्या	ग्रामों की संख्या	पम्पसेटों की संख्या	ऋण सहायता
1	2	3	4	5	6
					(लाख रुपये)
1.	आंध्र प्रदेश	15*	1012	29678	1202.900
2.	असम	4	432	245	330.723

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	16	1930	26492	921.850
4.	गुजरात	13*	661	21412	792.138
5.	हरियाणा	10	618	12263	519.640
6.	हिमाचल प्रदेश	3	332	263	97.883
7.	केरल	8	246	5046	358.676
8.	मध्य प्रदेश	16	769	37051	853.946
9.	मैसूर	12*	760	14035	733.993
10.	महाराष्ट्र	17*	1717	30201	1408 758
11.	मेघालय	1	32	33	24.455
12.	उड़ीसा	11	1059	16826	505.637
13.	पंजाब	14	1789	19630	773.649
14.	राजस्थान	16	1010	22538	859..406
15.	तमिल नाडु	12	1549	30575	812.672
16.	उत्तर प्रदेश	27*	3476	26059	1956.439
17.	पश्चिम बंगाल	16	3387	12784	1186.679
	कुल योग	211	19769	305131	13339 444

*ग्राम बिजली सहकारी संस्था की एक स्कीम शामील है।

भारतीय रेलवे में औषध-कारकों के वेतन-मानों को क्रियान्वित करना

3900. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में औषधकारकों की पदोन्नति के स्रोतों को विस्तृत करने और उनके वेतनमानों पर पुनर्विचार करने के लिये नियुक्त की गई उप-समिति की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं ; और

(ख) इन्हें क्रियान्वित करने का भारतीय रेलों पर, डिवीजन-वार, क्या प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : रेलों मे सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को "कैश विटनेस" भत्ता

3901. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को "कैश विटनेस" भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भत्ता अन्य जोनों में भी दिया जाता है ; और

(ग) क्या इस भत्ते के साथ यात्रा-भत्ता भी दिया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

वर्दियों के बारे में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) से अभ्यावेदन

3902. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सर्दियों में उत्तर रेलवे द्वारा तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को बहुत ही घटिया किस्म की वर्दियां सप्लाई की गई थीं ;

(ख) क्या उक्त वर्दियों के बारे में कर्मचारियों से क्रय और स्टोर शाला के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) मुख्यतः वर्दी की किस्म और उनकी फिटिंग ठीक न होने के बारे में अभ्यावेदन दिया गया था। जांच करने से पता चला कि सामान घटिया किस्म का समझा जाने का कारण यह था कि देशी ऊन में कुछ नायलून मिला था जैसा कि वस्त्र निदेशक, बम्बई द्वारा सप्लाई किया जा रहा है जिसकी नवीनतम भारतीय मानक विशिष्ठि में अनुमति प्रदान की गयी है। विशिष्टि में यह उल्लिखित हैं कि 15 प्रतिशत तक नायलून के उपयोग की अनुमति है क्योंकि ऊन का आयात प्रतिबंधित है और चूंकि देशी ऊन न तो मुलायम है और न उस में यथा आवश्यक मजबूती हैं अतएंव उसमें नायलून मिलाया जाता हैं। फिर भी इस मामले की जांच की जा रही है कि क्या उसमें सुधार सम्भव है। जहां तक पोशाक की फिटिंग ठीक न होने का सम्बन्ध है, इसका कारण यह पता चला है कि वर्दियों की गलत नाम देने के कारण ऐसा हुआ है। वर्दियों की फिटिंग गलत न हो इससे बचने के लिए और कर्मचारियों की वर्दी की नाप उचित हो ऐसा सुनिश्चत करने के लिए मण्डल अधिकारियों को उपयुक्त आदेश दे दिये गये हैं।

वर्दियों संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय

3903. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री वर्दियों की सप्लाई के सम्बन्ध में वर्दी संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में 4 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1269 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समिति की सभी सिफारिशें पूरी-पूरी स्वीकार कर ली गई है ; और

(ख) सिग्नल तथा दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने क्या अन्तिम निर्णय लिए हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) कठिन वित्तीय स्थिति के कारण वर्दी समिति की विभिन्न सिफारिशों को अपनाने का विचार तब तक आस्थगित कर दिया गया है जब तक 1973-74 का बजट न बन जाये।

कोयला ढोने के लिए रेल वैगन

3904. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल अधिकारी कोयला ढोने के लिए वैगनों की कमी की समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) जी नहीं। कोयले का लदान, जो विभिन्न समाज-विरोधी गतिविधियों और बाढ़, वर्षा, लाइन की टूट-फूट, शरणार्थियों के लिए खाद्यान्न के भारी संचलन और रक्षा संबंधी संचलन आदि के कारण पश्चिमी बंगाल-बिहार की कोयला खानों से सम्बद्ध पूर्वी क्षेत्र में अस्त-व्यस्तता आ जाने के कारण सितम्बर 1970 से गिर गया था जनवरी' 72 से फिर से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेगा :—

लादे गये माल-डिब्बे की दैनिक औसत संख्या

मास	1971	1972
जनवरी	7512	7993
फरवरी	7490	8138
मार्च	7694	8337

1969-70 में प्राप्त किये गये स्तर से जबकि उपभोक्ताओं को कोयले की सब मांगें पूरी की गयी थीं, मार्च, 1972 में लदान अधिक अच्छा रहा। लदान में और अधिक वृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्य व्यापार निगम की क्रय क्षमता बढ़ाने हेतु प्रबंध

3905. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय किया है जिससे राज्य व्यापार निगम की क्रय क्षमता बढ़ जाये ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है और उसके कब तक क्रियान्वित होने की सभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम को निर्यात के लिए अपनी स्थानीय खरीदारी में या आयात के लिए विदेशों में अपनी खरीदारी में वित्तीय या अन्य किसी प्रकार की कोई विवशता नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के उपाय

3906. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी बंगाल के जिले (पश्चिम बंगाल) में बाढ़ नियंत्रण की दीर्घ कालिक योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : उत्तर बंगाल नियंत्रण आयोग ने, जिसकी स्थापना पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्तूबर 1971 में की थी, उत्तर बंगाल क्षेत्र में बाढ़-नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना के संबंध में अन्वेषण करने और उसे तैयार करने का काम हाथ में ले लिया है । एक व्यापक योजना के तैयार होने तक, असुरक्षित क्षेत्रों में जहां तक आवश्यक हैं, निर्माण कार्यों का कार्यान्वियन किया जा रहा है, जो अंततः बाढ़ नियंत्रण की समस्त योजना में ही आ जायेंगे ।

मार्च, 1972 के अंत तक कार्यान्वित निर्माण कार्यों में ये कार्य सम्मिलित हैं। 110 किलोमीटर के नये तटबंधों और 19 नगर-सुरक्षा कार्यों का निर्माण, नदी नियंत्रण कार्य और मौजूदा तटबंधों को उंचा और सुदृढ़ करना। इन निर्माण कार्यों का लक्ष्य लगभग 1.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को काफी मात्रा में सुरक्षा प्रदान करना है।

इन निर्माण-कार्यों पर मार्च, 1972 तक कुल परिव्यय लगभग 7 करोड़ रुपये हैं।

जो प्रमुख निर्माण कार्य इस समय निष्पादनाधीन हैं, वे इस प्रकार हैं —

(1) मंडलघाट से बीबीगंज तक तीस्ता नदी के दाहिने किनारे के बचाव की स्कीम (2) जल-पाइगुड़ी नगर के बचाव के लिये कराला नदी के व्यपवर्तन की स्कीम (3) सील तोरसा नदी के चेल में व्यपवर्तन को रोकने की स्कीम और (4) बिजनबारी शहर के बचाव की स्कीम । महानंदा तटबंध स्कीम (पश्चिम बंगाल) को हाल में क्रियान्विति के लिए मंजूरी दे दी गई है । माल्दा जिले में क्षेत्रों के बचाव के लिए गंगा नदी के बायें किनारे पर एक तटबंध के निर्माण को भी, फरक्का बराज परियोजना के एक अंग के रूप में, मंजूरी दे दी गई है।

निर्यात हेतु उत्पादन की योजना

3907. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय इस समय निर्यात की अत्यधिक संभावनाओं वाले उत्पादों के उत्पादन की कोई योजना तैयार करने में व्यस्त है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : कुछ विशिष्ट वस्तु समूहों के संबंध में ठोस निर्यात उत्पादन योजनाएं तैयार करने तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए बारह अंतः मंत्रालय कार्यकारी दल स्थापित किये गये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें कार्यकारी दलों के तथा उन उत्पादों के नाम दिये गये हैं जिनसे वे संबंधित हैं तथा उनके विचारार्थ विषय दिये गये हैं।

विवरण

(I) **कार्यकारी दलों के नाम**

दल	उत्पाद	टिप्पणी
दल–क	कच्चा लोहा नरम इस्पात औजार मिश्रित धातु तथा विशेष प्रकार का इस्पात	कार्यकारी दलों के अध्यक्ष उन विभागो के संयुक्त सचिव है जो कि इन मदों से प्रशासनिक रूप में संबद्ध हैं।
दल–ख	इलैक्ट्रोनिक उपस्कर तथा संघटक	
दल–ग	(i) एल्युमिनियम धातु (ii) पैट्रो रासायनिक पदार्थ तथा उनसे बनने वाले माल एकीकृत पैट्रो रसायन कमप्लैस्क रंजक रंग मध्यवर्ती पदार्थ, दवाइयां तथा भेषजीय पदार्थ (iii) प्लास्टिक, रेजिन तथा उससे बना माल	
दल–घ	धातु कार्मिक उपस्कर छोटे तथा काटने के औजार, दस्ती औजार, धातु काटने की मशीनेंधातु को आकार देने की मशीनें, रसायनिक पदार्थ तथा उर्वरक प्लांट	
दल–ङ	मोटरगाड़ी का अनुषंगी माल	
दल–च–I	लौह ढलाई तथा गढ़ाई, स्ट्रक्चरल इस्पात संरचना	
दल–च–II	एल्यूमिनियम धातु से बनी वस्तुएं	
दल–छ	सिलाई मशीनें तथा साइकिल सिलाई मशीनें तथा साइकिलें और साइकिल के संघटक	

दल	उत्पाद	टिप्पणी
दल—ज	साधित खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, डिब्बाबंद फल तथा सब्जियां	
दल—झ	चमड़ा तथा चमड़े से बना माल रबड़ से बना सामान जिसमें टायर तथा ट्यूबें भी शामिल हैं	

लघु क्षेत्र के चुने हुए अन्य उत्पाद

दल

(II) विचारार्थ विषय

सभी कार्यकारी दलों के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

1. समूह के भीतर निर्यात की संभाव्यता वाले विशेष उत्पादों के बारे में बताना।
2. वर्तमान क्षमता तथा निर्यात उत्पादन सहित उत्पादन का पुनरीक्षण करना।
3. निर्यात तत्वों का निर्माण।
4. किस्मों, विशिष्ट विवरणों, क्वालिटी तथा मात्रा में कमी के संबंध में वर्तमान क्षमता में कमियों का पता लगाना।
5. विविधीकरण, विस्तार तथा निर्यात क्षमता सहित क्षमता उत्पन्न करने के लिए माइक्रो स्तर पर योजना तैयार करना।
6. नया उत्पादन प्रारंभ करने तथा वर्तमान उत्पादन को बनाये रखने के लिए उत्पादन नियंत्रण प्रणाली (औद्योगिक लाइसेंस, पूंजीगत माल लाइसेंस तथा विदेशी सहयोग) के जरिये उत्पादन निविष्टों की विदेशों में व्यवस्था तथा प्रत्येक मामले का अलग-अलग मार्ग दर्शन करना।
7. 1 से 6 तक वर्णित कार्यों को संपन्न करने के लिए जानकारी, सूचना तथा पुनरीक्षण प्रणालियों को विकसित करना।

407 अप रेलगाडी का सहरसा जंक्शन से बनमांखी जंक्शन तक तथा वापस (पूर्वोत्तर रेलवे) बढ़ाया जाना

3908. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 407 अप रेलगाड़ी को सहरसा जंक्शन से बनमांखी जंक्शन तक तथा वापस बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक क्रियान्विन कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) जी हां। 1-5-1972 से प्रयोगात्मक रूप में तीन महीने के लिए।

चाय के डिब्बों का वितरण

3909. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चाय बोर्ड के कलकत्ता और दिल्ली स्थित कार्यालयों के माध्यम से प्रत्येक साईज के कुल कितने चाय के डिब्बे वितरित किये गये और उन पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(ख) इन चाय के डिब्बों का भारत में किन-किन को वितरण किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों में कलकत्ता में चाय बोर्ड के मुख्य कार्यालय तथा नई दिल्ली में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय से विभिन्न साइजों के चाय के डिब्बों का वितरण तथा उन पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है :—

कलकत्ता में स्थित मुख्य कार्यालय से वितरण

वर्ष	पशु/पक्षी संख्या	बड़ा साइज	मध्यम साइज	छोटा साइज	कुल संख्या	मुल्य रुपये में
1969–70	46	97	353	120	616	3828.55
1970–71	46	50	175	31	302	2308.59
1971–72	153	91	91	32	367	5015.73
			दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से वितरण			
1969	153	130	149	153	585	4106.57
1970	138	291	464	640	1533	8752.72
1971	203	481	191	203	1078	9567.49

टिप्पणी : दिल्ली कार्यालय के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) डिब्बे निम्न को वितरित किये/गये दिये गये :—

(1) विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तथा समय-समय पर दौरे पर आये प्रतिनिधिमंडलों तथा व्यापार मिशनों के सदस्यों को।

(2) विदेशों में दौरे के दौरान भेंट करने के लिये विदेश व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों को ।

(3) सरकारी अधिकारियों को, ताकि वे महत्वपूर्ण पर्यटकों तथा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को जो उनसे मिलने आये भेंट कर सकें ।

कलकत्ता के लिए वृत्ताकार रेलवे परियोजना

3910. **डा० रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे परियोजना बनाने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में वैगनों का निर्माण

3911. **डा० रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1971–72 में पश्चिम बंगाल स्थित वैगन बनाने वाली फर्मों को कितने वैगनों के लिए क्रयादेश दिये हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार 1972–73 में वैगनों के निर्माण के लिए दिये जाने वाले क्रयादेश में से 67 प्रतिशत क्रयादेश पश्चिम बंगाल स्थित फर्मों को देने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) माल डिब्बा निर्माण कार्यक्रम 1971–72 के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल स्थित माल डिब्बा निर्माताओं को चौपहियों के हिसाब से 4609.5 माल डिब्बों का आर्डर दे दिया गया है ।

(ख) माल डिब्बा निर्माण उद्योग को खासकर पश्चिम बंगाल में पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने विनिश्चय किया था कि 1972–73 कार्यक्रम में सम्बन्धित 8000 माल डिब्बों की साधारण आवश्यकता के अलावा, जिसके लिए सभी माल डिब्बा निर्माताओं को आर्डर देने है, चौपहियों के हिसाब से, 3000 अतिरिक्त माल डिब्बों के आर्डर केवल पश्चिम बंगाल के माल डिब्बा निर्माताओं को दिये जायें । तदनुसार, चौपहियों के हिसाब से, 11000 माल डिब्बों में से 7722.5 माल डिब्बों के आर्डर/प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के माल डिब्बा निर्माताओं को दिये गये । इसके साथ ही, चौपहियों के हिसाब से 5116 माल-डिब्बों के लिए अतिरिक्त आर्डरों में से 1150 माल-डिब्बों के आर्डर पश्चिम बंगाल के माल डिब्बा निर्माताओं को पहले ही दिये जा चुके हैं और 1729.5 माल डिब्बों के लिए आर्डर जारी किये जा रहे हैं ।

तालचेर-बिमलागढ़ रेल सम्पर्क

3912. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर और बिमलागढ को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के सम्बन्ध में किये गये इंजीनियरिंग सर्वेक्षण की रिपोर्ट की इस बीच जांच हो गई है; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) अभी नहीं ।

(ख) मंगल टोली खनिज भंडार के विकास के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

Attack on R. P. F. personnel at Gram Katia Station (North Eastern Railway)

3913. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether some goondas made a fatal attack on RPF personnel at Gram Katia Station of the North Eastern Railway in the last week of March, 1972 and snatched their rifles; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

रेलों में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए विभाग

3914. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या मंत्रालय के अन्तर्गत कोई ऐसा विभाग है जो इस समस्या का अध्ययन करता है और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए मंत्रालय को सुझाव देता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई विभाग बनाने का कोई **प्रस्ताव** है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेल कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार सम्बन्धी शिकायतों/आरोपों को निपटाने के लिए भारतीय रेलों की प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में भी एक पूर्ण रूपेण सतर्कता संगठन काम करता है। सभी प्राप्त वास्तविक शिकायतों/आरोपों और सूचनाओं पर विचार किया जाता है और अपेक्षानुसार जांच/छान-बीन की जाती है। इस छान-बीन के अलावा न केवल भ्रष्ट गतिविधियों का पता लगाने और इस तरह के भ्रष्टाचार के हथकंडों और उनकी गुंजाइश को प्रकाश में लाने के लिए बल्कि रेलों के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्बन्ध में की गयी

जांच/किये गये अध्ययन के दौरान नियमों में जो कमियां/त्रुटियां दिखाई देती हैं उन्हें दूर करने में सहायता देने के लिए सतर्कता संगठन स्वतः भी रोक-थाम के उपाय और विशिष्ट अध्ययन करता है। सतर्कता संगठन विशेष पुलिस स्थापना के साथ संयुक्त रूप से भी रोक-थाम के इस तरह के उपाय करता है। सरकारी कर्मचारियों (रेल कर्मचारियों सहित) के विरूद्ध अनाचार और घूस लेने की जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, विशेष पुलिस स्थापना द्वारा उनकी भी छान-बीन की जाती है।

नियमों और प्रक्रियाओं में जो त्रुटियां पायी जाति हैं और उन्हें ठीक करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है, उनके बारे में क्षेत्रीय रेलों के सतर्कता संगठन मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक अपनी रिपोर्टों के रूप में रेल मंत्रालय को अपनी गतिविधियों की सूचना भेजते रहते हैं।

रेलगाड़ियों के लिए फालतू बिजली के प्रयोग के लिये राज्य सरकारों से वार्ता

3915. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू बिजली वाले विभिन्न राज्यों से इस बारे में बातचीत चल रही है कि उनकी फालतू बिजली को बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाने के लिए प्रयोग किया जाये और यदि हां, तो बातचीत किस अवस्था में है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो रेलवे को बिजली सप्लाई करने के लिए बहुत अधिक दरों की मांग कर रहे हैं; और

(ग) वर्तमान तथा आगामी पंचवर्षीय योजना में किन क्षेत्रों में रेलवे द्वारा बिजली से रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चौथी योजना के दौरान (1969–74) निम्नलिखित खण्डों पर बिजली कर्षण पहले से प्रारम्भ कर दिया गया है।

(i) दक्षिण पूर्व रेलवे का राउरकेला-दुर्ग खण्ड; और

(ii) उत्तर रेलवे का कानपुर-टूंडला खण्ड।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद-बड़ोदा खण्ड और दक्षिण पूर्व रेलवे के पांशकुड़ा-हल्दिया खण्ड पर भी अब बिजली कर्षण चालू हो जाने की आशा है।

इसके अलावा, निम्नलिखित खण्डों पर अब बिजलीकरण सम्बन्धी निर्माण कार्य चालू है और पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान उनके पूरा हो जानें की सम्भावना है।

(i) बड़ौदा-विरार (पश्चिम रेलवे)

(ii) टूंटला-दिल्ली (उत्तर रेलवे)

(iii) वालतेरू-किरंदुल (दक्षिण पूर्व रेलवे)

(iv) मद्रास-विजयवाड़ा (दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे)

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान किये जाने वाले बिजलीकरण सम्बन्धी निर्माण कार्य के कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

रेलवे वर्कशाप खड़गपुर का विस्तार

3916. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे वर्कशाप, खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) के विस्तार के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इसका विस्तार कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) खड़गपुर कारखाने में कुछ विस्तार योजनाएं शुरू की जा रही है ताकि वहां डीजल रेल इंजन, बिजली रेल इंजन, बोगी के पुर्जे और नये सवारी डिब्बा कारखाने तथा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सवारी डिब्बों सहित अधिक आधुनिक और परिष्कृत किस्म के चल स्टाक को सम्हाला जा सके।

एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०– 1848/72**]

रूस को तम्बाकू का निर्यात

3917. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत से और अधिक तम्बाकू खरीदने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो रूस द्वारा कितना तम्बाकू खरीदा जायेगा और उसका मूल्य कितना होगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सोवियत संघ को 1970-71 में 5.5 करोड़ रुपये मूल्य का 7000 मे० टन तम्बाकू निर्यात किया गया था जबकि 1972 में 16.0 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य का 18,000 मे० टन तम्बाकू निर्यात होने की संभावना है। सोवियत संघ ने 1972 के व्यापार योजना में की गई व्यवस्था से अधिक तम्बाकू खरीदने की कोई पेशकश नहीं की।

रेल वेगनों को असाधारण तौर पर रोके रखना और वेगनों की कमी

3918. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम के अनुसार सप्लाई करने के लिए "टैंक वैगनों" के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अन्य प्रकार के वैगनों के निर्माण के क्रयादेश दे दिये गये हैं; और

(ख) किस किस प्रकार के वैगनों के क्रयादेश गये दिये हैं; और उनके किस तारीख तक मिलने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1971–72 और 1972–73 के माल डिब्बा निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राईवेट माल डिब्बा (टंकी माल डिब्बों के अतिरिक्त) की संख्या निर्माताओं को आर्डर दिये गये माल–डिब्बों और उनकी किस्म तथा उनकी सुपुर्दगी की निर्धारित तारिखें नीचे दी गयी है।

माल-डिब्बा निर्माण कार्यक्रम, 1971–72

निजी क्षेत्र

माल-डिब्बे की किस्म	आर्डर दिये गये माल-डिब्बों की संख्या	ठेके के अनुसार सुपुर्दगी की तारीख
बी० ओ० एक्स० टी०	245	31.12.1972
बी० ओ० वाई०	350	31.12.1972
सी० आर० सी० आर० टी०	1828	31.12.1972
बी० डब्ल्यू० टी० ए०	101	30.6.1972
एम० बी० बी० जी०	120	31.12.1972
एम० बी० टी० पी० जेड०	225	31.12.1972
एम० बी० डब्ल्यू० जेड०	59	31.7.1972
माल-डिब्बा निर्माण कार्यक्रम, 1971–72		
बी० ओ० एक्स० टी०	1360	31.3.1974
सी० आर० टी०	3214	31.3.1974
बी० ओ० वाई०	950	31.3.1974

माल-डिब्बों की निम्नलिखित किस्म और संख्या के लिए प्राईवेट माल-डिब्बा निर्माताओं को और आर्डर दिये जा रहे हैं :—

माल-डिब्बों की किस्म	संख्या	सुपुर्दगी की तारीख
बी० ओ० एक्स० टी०	706	31.3.1974
सी० आर० टी०	2677	31.3.1974
बी० बी० जी० टी०	210	31.3.1974

रेलवे कारखाने

1971–72 कार्यक्रम

कोई नहीं।

1972–73 कार्यक्रम

बी० ओ० एक्स० टी०	150	मार्च, 1974 तक सुपुर्दगी हो जाने की आशा है ।
सी० आर० टी०	500	
बी० सी० एक्स०	115	

1971–72 और 1972–73 के कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राइवेट माल-डिब्बा निर्माताओं को टंकी माल-डिब्बों के लिए दिये गये आर्डरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1971–72 कार्यक्रम

माल-डिब्बों की किस्म	आर्डर दिये गये माल-डिब्बों की संख्या	सुपुर्दगी की तारीख
टी० पी० आर०	1333	31.12.1972
	792	30.4.1973
1972–73 कार्यक्रम		
टी० पी० आर०	1000	31.12.1973
	600	31.3.1974
	400	31.12.1972

1971–72 और 1972–73 के कार्यक्रमों के अन्तर्गत टंकी माल-डिब्बों के लिए रेल कारखानों को कोई आर्डर नहीं दिये गये हैं ।

भारतीय रुई निगम की दोहरी नीति

3920. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम एक ओर यह प्रचार कर रहा है कि रुई के मूल्य-समर्थन में वह स्वदेशी रुई की खरीद अधिक कर रहा है और दूसरी ओर अपने भंडार से गैर-सरकारी व्यापारियों को रुई बेचने के लिए निजी तौर पर बातचीत कर रहा है और इस प्रकार बाजार में आतंक की स्थति पैदा कर रहा है ;

(ख) क्या रुई की कीमत बहुत अधिक गिर गई है और कृषकों, व्यापारियों और बैंकों आदि को रुई निगम की दोहरी नीति के कारण उसमें विश्वास नहीं रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

केरल में व्यापार केन्द्रों की स्थापना

3921. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल में अर्नाकुलम तथा अन्य स्थानों पर व्यापार केन्द्रों की स्थापना करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां तो राज्य सरकार के सुझाव की मुख्य बातें क्या हैं और केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केरल राज्य के लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यातों के विकास हेतु एर्नाकुलम में एक व्यापार केन्द्र स्थापित करने की एक प्रस्थापना राज्य सरकार प्राधिकारियों ने भेजी है। प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

देवीघाट में पन बिजली परियोजना का विस्तार

3922. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नेपाल सरकार ने भारत द्वारा बनाई गई देवीघाट पन बिजली परियोजनाओं के विस्तार का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) जी हां। बहरहाल अन्य विकल्प भी विचाराधीन हैं और अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है।

अमरीका को बाइसिकलों का निर्यात

3923. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारत की बाइसिकलों की मांग बढ़ रही है; और

(ख) वर्ष 1970–71 और 1971–72 में कितनी बाईसिकलें अमरीका को निर्यात की गई और इस उद्योग द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1970–71 (12 महीने) के दौरान निर्यात की गई 15.83 लाख रुपये मूल्य की 13152 बाइसिकलों की तुलना में अप्रेल, 71 से जनवरी, 1972 (10 महीने अवधि के दौरान 12.53 लाख रुपये के मूल्य की 8682 पूरी साइकिलों का सं० राज्य अमरीका को निर्यात किया गया था। भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम ने हाल ही में 14,76,000 अमरीकी डालर (जहाज पर मूल्य) के मूल्य की 60,000 थ्री स्पीड हब साइकिलें सं० राज्य अमरीका को सप्लाई करने की एक पुख्ता संविदा प्राप्त की है ।

सिंचाई के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

3924. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सिंचाई के विकास के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि के अनुदान दिए गए ; और

(ख) 31 मार्च 1972 तक कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई सुविधायें दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकारों द्वारा धनराशि की व्यवस्था उनके बजट में कुल विकासात्मक योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है । केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप से समस्त राज्य योजनाओं के लिए दी गई और इसका संबंध किसी विशिष्ट शीर्ष अथवा क्षेत्र या परियोजना से नहीं था ।

चतुर्थ योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए राज्यों का कुल योजना परिव्यय 3456 करोड़ रुपये था, जिसमें केन्द्रीय सहायता 1950 करोड़ रुपये की थी । इन तीन वर्षों के दौरान बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर राज्य सरकारों द्वारा 627 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया ।

(ख) देश में मार्च, 1972 तक लगभग 100 मिलियन एकड़ के कुल क्षेत्र में सिंचाई-सुविधाएं दी गई ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए परिव्यय

3925. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसके लिए कितना परिव्यय प्रस्तावित है तथा उसकी समयावधि क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विशेष रूप से अल्पविकसित पहाड़ी इलाकों के लिए प्रस्तुत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की वित्त व्यवस्था हेतु विशेष रियायती शर्तें लागू की हैं। निगम ने अबतक उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के लिए एक ऐसी स्कीम स्वीकृत की है जिसमें 215 ग्रामों और 109 पम्पसेटों के विद्युतीकरण के लिए लगभग 56 लाख रुपये की ऋण सहायता परिकल्पित है। स्कीम की अनुमानित लागत लगभग 77 लाख रुपये है और ऐसी आशा है कि यह जनवरी 1972 में अपने स्वीकृत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के अन्दर पूरी हो जायेगी।

उत्तर प्रदेश में टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन

3926. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में टनकपुर (जिला नैनीताल) से बागेश्वर (जिला अल्मोड़ा) तक 170 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कितने समय में होगा और क्या इस लाइन को आगे पौड़ी-गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल और पिथौरा गढ़ के जिलों से मिलाया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जल तथा विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा द्वारा आरम्भ किये गये कार्य

3927. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल तथा विद्युत विकास परमर्शदात्री सेवायें (इंडिया) लिमिटेड द्वारा भारत से बाहर अपनी स्थापना से लेकर अब तक कौन-कौन से काम अपने हाथ में लिए हैं;

(ख) अब तक भारत में तथा भारत से बाहर कितने कार्यों को पूरा किया जा चुका है;

(ग) पूरे हो गए कार्यों से कम्पनी को कितनी आय हुई है; और

(घ) पूरे किए जाने वाले कार्यों के लिए कुल कितना शुल्क लिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) देश के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में उत्तरी क्षेत्र भार प्रषेण केन्द्र के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य

जल और विद्युत विकास सलाहकारी सेवा (भारत) लिमिटेड (वैपकोस) को सौंपा गया था। इसके अलावा, कम्पनी ने जो कार्यभार हाथ में लिए हैं, उनमें निम्नलिखित आते हैं :—बिहार में बरौनी विद्युत केन्द्र के लिए कच्चे और खनिज रहित जल का रासायनिक विश्लेषण; राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की इच्छानुसार बैलाडिला ड़िपाजिट परियोजना के टेलिंग बांध के लिए जल-संचय ट्रावनकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, केरल के संयंत्र के विस्तार के लिए अतिरिक्त जल की सप्लाई; बृहत्तर बम्बई के लिये नये जल संसाधनों के संबंध में अध्ययन; कोनार बांध से संबद्ध दामोदर घाटी निगम द्वारा अपेक्षित सलाह और हैदराबाद स्थित मंजोरा जल सप्लाई स्कीम से संबंधित पूछताछ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, वैपकोस को सेवाओं का लाभ इस प्रकार उठाया गया; भूमि सर्वेक्षणों के संबंध में मलावी में; सुमात्रा में वाम्पू बाढ़ नियंत्रण परियोजना के लिए जिसके संबंध में एशियाई विकास बैंक ने कम्पनी द्वारा प्रतीनीयुक्ति एक वरिष्ठ विशेषज्ञ के सेवाओं का लाभ उठाया; अफगानिस्तान में कुछ सूक्ष्म जल-विद्युत स्कीमों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिये, जिसमें दो विद्युत केन्द्रों के लिए परियोजना अपिकल्पों और प्राक्कलनों को तैयार करना सम्मिलित है और ईरान में उनको सौंपे गये कार्य के संबंध में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा लाओस में मा...नाओं परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के कार्य कम्पनी को सौंप दिये गये हैं। भारतीय इंजीनीयरों के चयन के लिए वैपकोस ने जाम्बिया विद्युत प्रदाय निगम और तेहरान क्षेत्रीय विद्युत कम्पनी के लिए सहायता की व्यवस्था कर दी है। इसने तंजानिया थाईलैंड और नाइजीरिया में कार्य के लिए इंजीनियर-विशेषज्ञों को सेवाओं की व्यवस्था भी कर दी।

(ख) और (ग) तकनीकी सलाह के छोटे कार्यभारों के अलावा, कम्पनी ने विदेश में चार और भारत में तीन सौंपे गये कार्य पूरे कर लिये हैं। निगम ने लगभग 79,000 रुपये अर्जित किये जिसमें 56,000 रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में हैं।

(घ) सौंपे गये जो कार्य अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं, उनसे लगभग 15.25 लाख रुपये की आशा है, जिसमें 7 लाख रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे।

क्षेत्रीय विद्युत्-भार पारेषण केन्द्रों की स्थापना

3928. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों के विद्युत् भंडारों के समेकित उपयोग को सुलभ बनाने के लिए कितने क्षेत्रीय विद्युत्-भार पारेषण केन्द्र स्थापित किए गए हैं ;

(ख) सम्पूर्ण देश में ऐसे कितने केन्द्र कहां-कहां पर खोले जायेंगे ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) इसलिए कि क्षेत्रों में विद्युत् प्रणालियों का प्रचलन हो, उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली (बदरपुर) में, दक्षिणी क्षेत्र के लिए बंगलौर में, पश्चिमी क्षेत्र के लिए बम्बई (कुलाबा) में और पूर्वी क्षेत्र के लिए कलकत्ता (हावड़ा) में चार क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोशिशें जारी हैं। क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों की प्रतिष्ठापना प्रणाली के आवश्यकतानुसार चरणबद्ध होगी, कुछ जटिल उपस्कर जैसे स्वचालित नियंत्रण आदि, बाद में लगाये जायेंगे। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों की

प्रतिष्ठापना के प्रथम चरण के, जो हाथ में लिया जा रहा है, चतुर्थ योजना के अन्त तक पांचवी योजना के आरंभ तक पूर्ण होने की संभावना है । प्रस्तावों को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात अन्य क्षेत्रों में ऐसे केन्द्रों के भी चतुर्थ योजना के दौरान हाथ में लिए जाने की संभावना है ।

सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभाग के अत्यावश्यक सेवा वर्ग के कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन और ब्रेक डाउन भत्ता

3929. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिग्नल तथा टेलीकम्युनिकेशन विभाग के कर्मचारियों को रेल दुर्घटनाओं, रेल पटरी से गाड़ी के उतर जाने जैसी खराबियों, रेल कांटो से आगे निकल जाने और फाटकों की क्षति आदि से संबंधित कार्य करना पड़ता है ;

(ख) क्या दुर्घटनाओं एवं ब्रेक डाउन के अवसरों पर कार्य करने वाले अन्य विभागों के कर्मचारियों को निःशुल्क भाषण तथा ब्रेक डाउन भत्ता दिया जाता है जबकि सिगनल तथा टेलीकम्युनिकेशन विभाग के कर्मचारियों को वही कार्य करने पर इन सुविधाओं और लाभों से वंचित रखा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, यदि आवश्यक हो ?

(ख) और (ग) अन्य सभी विभाग के कर्मचारियों को ब्रेकडाउन भत्ता नहीं दिया जाता बल्कि रनिंग शेड, सवारी और माल डिब्बा शेड तथा सहायता गाड़ियां खड़ी रखे जाने वाले जकंशनों की बिजली सहायता गाड़ी यूनिटों के कर्मचारियों में से कुछ विशिष्ट कर्मचारियों को दिया जाता है । बुलाये जाने पर सब कर्मचारियों को सहायता गाड़ियों पर अनिवार्य रूप से जाना पड़ता है ।

सिगनल और दूर-संचार विभाग सहित सभी विभाग के अन्य कर्मचारी, जो वास्तव में ब्रेकडाउन के काम में लगाये जाते हैं, को ऐसी डयूटी करने की अवधि के दौरान मुफ्त भोजन दिया जाता हैं और काम का घण्टा तथा दैनिक भत्ता की पात्रता के प्रयोजन से दुर्घटना स्थल की ओर वहां से यात्रा की गणना के लिए सामान्य नियमों में ढील देकर उन्हें कतिपय रियायतें भी दी जाती हैं ।

चूंकि सिगनल और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को सामान्यतः अन्य विभाग के कर्मचारियों जैसा ही माना जाता है अतएव उनके साथ ऐसा कोई भेद-भाव नहीं किया जाता जिससे उनकी हानि हो । लेकिन सहायता गाडी उपस्करों के प्रभारी होने के कारण रनिंग शेड, सवारी और माल डिब्बा शेड तथा बिजली सहायता गाड़ी यूनिट के सहायता गाड़ी स्थल के लिए निर्धारित कर्मचारियों की स्थिति कुछ भिन्न है और इस लिए उन्हें ब्रेकडाउन भत्ता दिया जाता है ।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सिग्नल और दूर संचार व्यवस्था के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था

3930. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन में ओखला, सफदरजंग, तिलकब्रिज, साहिबाबाद, जींद, बंढलाढा, तुगलकाबाद, गन्नौर, सरहिन्द, में सिगनल और दूर संचार उपकरणों की देखरेख करने के लिये नियुक्त

कर्मचारियों की दिन रात में किसी भी समय सिगनलों और दूर संचार उपकरणों में उत्पन्न त्रुटियां दूर करनी पड़ती हैं ;

(ख) क्या ये कर्मचारी रेलवे की आवास व्यवस्था की दृष्टि से 'आवश्यक' वर्ग में आते हैं ;

(ग) क्या उक्त स्थानों पर नियुक्त कर्मचारियों को अपने कार्य करने के स्थान के निकट रेलवे क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इन कर्मचारियों की कठिनाई हल करने के लिये प्रशासन का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) जितने रेलवे क्वार्टर उपलब्ध होते हैं, आवंटित कर दिये जाते हैं । अनिवार्य कर्मचारियों को क्वाटरों की उपलब्धि और प्रतीक्षा सूची में उन कर्मचारियों की बारी के अनुसार क्वार्टर आवंटित किये जाते हैं । धन की उपलब्धि के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर प्रति वर्ष नये क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया जाता है ।

लोक-सभा के दरभंगा उप-निर्वाचन में सेनाध्यक्ष के चित्रों का प्रयोग

3931. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के उप-निर्वाचन अभियान में सेनाध्यक्ष के चित्र प्रयोग में लाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो चित्रों का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या निर्वाचन विधी के अधीन सरकार ने कोई कार्यवाही की थी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या राज्य प्राधिकारियों से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के उप-निर्वाचन में सेनाध्यक्ष के चित्र प्रयोग में लाए गए थे ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा खिरई रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्वी रेलवे) पर गोली चलाया जाना

3932. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्वी रेलवे के खिरई रेलवे स्टेशन (पश्चिमी बंगला) पर 27 मार्च, 1972 को रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा गोली चलाये जाने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप एक विद्यार्थी और एक गेंगमेन सहित चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के विचार से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) कुछ गैंगमैनों और रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र स्कंध के कर्मचारियों के बीच एक आपसी झगड़े में कुछ गैंगमैनों को चोटें आ गयीं। बाद में बहुत से गैंगमेंन और गांव वाले, जिनमें छात्र भी शामिल थे, वहां इकट्ठे हो गये और उन्होंने रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जो घबरा गये। इस भय से कि उनकी बंदूके छीन ली जायेगी और उनकी जाने खतरे में पड़ जायेगी उन्होंने गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति मर गये और कुछ अन्य लोग घायल हो गये।

(ख) सामान्य स्थिति लाने के लिए वहां तैनात रेलवे सुरक्षा दल को हटा लिया गया है। अपराधी रक्षक पुलिस की हिरासत में है और उन्हें जांच होने तक निलम्बित कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को उपयुक्त हिदायतें दी गयी है कि जनता के साथ व्यवहार करते समय उन्हें अधिक चतुरता और सहनशीलता से काम लेना चाहिए।

राजस्थान में नहर सम्बन्धी परियोजनाओं की धीमी प्रगति

3933. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में नहर सम्बन्धी योजनाओं की धीमी प्रगति की जांच करने तथा व्यास नदी के जल का उपयोग करने के लिए, जो सिन्धु नदी संधि सम्बन्धी दायित्वों के समाप्त हो जाने के दो वर्ष पश्चात् थी पाकिस्तान की ओर बह रही है, सिफारिशें देने हेतु एक समिति की नियुक्त की मांग उठाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपडवंज रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के लिये रेलवे वैगन

3934. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़वंज रेलवे स्टेशन पर रूई के परिवहन के लिए रेलवे वैगनों की बहुत कमी है जिसके कारण रुई के मूल्य कम हो गये हैं और व्यापारियों को कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) वह रेलवे वैगनों की कमी को दूर करने के विचार से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) लदान साथ के साथ ही रहा है । 1 जनवरी से 17 अप्रैल, 1972 की अवधि में 121 माल डिब्बों का लदान हुआ जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 117 मालडिब्बे लादे गये थे । 17-4-1972 को अनुपालन के लिए कोई मांग शेष नहीं थी ।

तारापुर आणविक बिजली घर के कार्यकरण के बारे में गुजरात चेम्बर्स आफ कामर्स के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत

3935. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात चेम्बर्स आफ कामर्स के आठ-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली का दौरा किया था और तारापुर आणविक बिजली घर के कार्यकरण के बारे में उनसे बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत हुई और बातचीत का परिणाम क्या निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) जी, हां । गुजरात वाणिज्य और उद्योग मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल सिंचाई और विद्युत उपमंत्री से 25 मार्च, 1972 को मिला और उसने गुजरात में विद्युत कमी की स्थितियों के बारे में विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया । विचार-विमर्श के दौरान, तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र द्वारा, जिसका प्रबंध परमाणु विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, सामना की जाने वाली कठिनाइयों का संक्षेप में उल्लेख किया गया । गुजरात में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए हाथ में ली गई विभिन्न परियोजनाओं का पुनरीक्षण किया गया । इसमें धुवरण ताप विद्युत केन्द्र में 140-140 मेगावाट के दो सेटों के प्रतिष्ठापन और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ गुजरात विद्युत प्रणाली को जोड़ने वाली अंतर्राज्यिक लाइनों के निर्माण की प्रगति सम्मिलित थी। मौजूदा विद्युतजनन सेटों से यथासंभव अधिक से अधिक विद्युत-जनन करने के उद्देश्य से धुवरण विद्युत केन्द्र को ईंधन तेल और गैस की सप्लाई में सुधार लाने और सौराष्ट्र में एक नये परमाणु विद्युत केन्द्र के लिये स्थान निश्चित करने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया गया । इन मामलों पर सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा की जा रही कारवाई से प्रतिनिधि-मंडल को अवगत कराया गया । प्रतिनिधि मंडल ने इस बात को माना कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय गुजरात में विद्युत स्थिति में सुधार के लिए अनेक मोर्चों पर प्रयास कर रहा है।

गुजरात में बिजली की कमी

3936. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के विचार से उस राज्य में नौ बिजली परियोजनाओं का कार्य युद्धस्तर पर प्रारम्भ किया गया है ;

(ख) केन्द्र सरकार ने बिजली की अत्यन्त कमी को दूर करने लिये राज्य सरकार को और कौन से उपाय करने को कहा है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि उच्च वोल्टता वाले उपभोक्ताओं की सप्लाई में 25 प्रतिशत कटौती की जाये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गुजरात बिजली बोर्ड ने कुल 754 मेगावाट की नौ विद्युत-जनन यूनिटों का प्रतिष्ठापन कार्यान्विति के लिए शुरू किया था ताकि वे चौथी योजना के अन्त तक मांग को पूरा कर सकें :

1. उकाई हाइड्रो में 75–75 मैगावाट के 4 विद्युत-जनन सेट ।
2. उकाई थर्मल में 120 मैगावाट का 1 विद्युत-जनन सेट ।
3. धुवरण में 140–140 मैगावाट के 2 विद्युत-जनन सेट ।
4. धुवरण में 27–27 मैगावाट की दो गैस-टर्बाइनें ।

कुल : कुल 754 मैगावाट के 9 विद्युत-जनन यूनिट ।

इन नौ विद्युत-जनन सेटों में से कुछ 54 मैगावाट के दो गैस टर्बाइन सेट चालू कर दिए गए है । धुवरण में 140 मेगावाट के प्रथम विद्युत-जनन सेट का प्रतिष्ठापन किया जा चुका है और उसे चालू करने से संबंधित परीक्षण किये जा रहे हैं । इसके तत्काल पश्चात दूसरा सेट चालू किया जाएगा। अन्य सेटों में यथासम्भव तेजी लाई जा रही है ।

(ख) मध्य प्रदेश और मैसूर से फालतू विद्युत की व्यवस्था की गई है । केन्द्र में अधिकतम विद्युत-जनन किया जा सके इस हेतु धुवरण विद्युत केन्द्र के लिए अतिरिक्त ईंधन तेल की सप्लाई की भी व्यवस्था की गई है । स्थापनाधीन विद्युत-जनन सेटों को चालू करने में तेजी लाने के लिए राज्य से भी कहा गया है ।

(ग) राज्य प्राधिकारियों ने स्वेच्छा से उच्च वोल्टता वाले उपभोक्ताओं पर मार्च 1972 में विद्युत उपभोग पर 25 प्रतिशत की कटौती लगादी थी जिसे अब कम करके 16 प्रतिशत कर दिया गया है । केन्द्र को सूचित कर दिया गया है ।

सिरे का निर्यात

3937. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत से कितना सिरा निर्यात किया गया और उससे 'जहाज पर्यन्त' मूल्य के रूप में कितने धन की प्राप्ति हुई ;

(ख) किन-किन राज्यों से कितनी-कितनी मात्रा में और किन-किन बन्दरगाहों से सीरे का निर्यात किया गया ; और

(ग) निर्यात हेतु खरीदे गये सीरे के लिये चीनी मिलों कों कितनी 'फैक्टरी द्वारा' मूल्य दिया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत से पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई सीरे की मात्रा तथा वर्षवार जहाज पर्यन्त मूल्य की प्राप्ति निम्नलिखित है:–

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (मे. टन)	जहाज पर्यन्त मूल्य की प्राप्ति (लाख रुपये में)
1968–69	1,640	14.54
1969–70	2,069	12.45
1970–71	1,23,870	162.29
1971–72 (अक्तूबर' 71 तक	35,993	48.45

(ख) मंत्रालय में इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ग) चीनी के कारखानों को कारखाने से निकलते समय पर दी जाने वाली कीमत ।

प्रत्येक चीनी के कारखाने को दी जाने वाली कीमतें अलग-अलग होती हैं जो सीरे की क्वालिटि, रेलवे स्टेशन/पत्तन से चीनी की मिल का फासला तथा जहाज पर निर्यात मूल्य आदि पर निर्भर होती हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई न्यूनतम तथा अधिकतम कीमतें निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	न्यूनतम कीमत	अधिकतम कीमत
1969–70	10 रु० प्रति मे. टन	40 रु० प्रति मे. टन
1970–71	8 रु० प्रति मे. टन	40 रु० प्रति मे. टन
1971–72	8 रु० प्रति में. टन	22 रु० प्रति मे. टन

ऐलको हल का आयात तथा निर्यात

3938. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भारत से एलको हल की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और कितनी मात्रा का भारत में आयात किया गया तथा निर्यात के द्वारा कितना 'जहाज-पर्यन्त' मूल्य प्राप्त हुआ ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

वर्ष	आयात (लीटरों में)	निर्यात (लीटरों में)	निर्यातों का जहाज पर मूल्य (रुपये में)
1968–69	8,13,320	12,181	30,884
1969–70	13,09,290	8,077	40,518
1970–71	2,51,752	11,329	75,818

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 'केला साइडिंग' पर रेल वैगनों से फलों के पार्सलों की कमी

3939. **श्री लालजी भाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 'केला' साइडिंग पर नियुक्त पार्सल कर्मचारियों द्वारा, व्यापारियों की सांठ-गाठ से ऐसी रेल वैगनों से ताजा फलों के पार्सल कम होने की 'क्षति/कमी संदेश' जारी किए जाते हैं जिन वैगनों की मोहरें ठीक होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1970-71 तथा 1972 के दौरान इस प्रकार की वैगनों से माल की कमी के परिणामस्वरूप कितने मूल्य के दावों की अदायगी की गई ; और

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार की हानियों को रोकने के लिए सरकार का विचार माल बुक करने एवं मोहर लगाने वाले स्टेशनों पर "टैस्ट वैगने" तैयार करने के आदेश देने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) इस तरह का कोई मामला नोटिस में नहीं आया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं ।

मेरठ शहर स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के विरूद्ध शिकायत

3940. **श्री लालजी भाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे पुलिस, मेरठ शहर को मेरठ शहर रेलवे स्टेशन के एक बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध एक यात्री से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस को जनवरी, 1972 में टिकट खरीदते समय धोखा दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 8-2-1972 को सरकारी रेलवे पुलिस मेरठ शहर को एक ऐसे यात्री से शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके साथ धोखा हुआ था।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस, मेरठ शहर ने 8-2-1972 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 और रेल अधिनियम की धारा 120 के अधीन मेरठ शहर के टिकट बाबू श्री ताराचंद के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था । उसने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया और उसे जमानत पर छोड़ दिया गया । इस मामले की छानबीन की जा रही है।

ऊन धुलाई की क्षमता

3941. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊन की धुलाई की सुविधाओं से युक्त ऊन मिलों को छोड़ कर परन्तु उनकी अपनी आवश्यकताओं से इतर स्थापित क्षमता सहित इस समय देश में ऊन की धुलाई की क्षमता क्या है ;

(ख) क्या कपड़ा आयुक्त संगठन अथवा सरकार ने सामान्य रूप से ऊनी कपड़ा उद्योग और विशेष रूप से छोटी ऊन मिलों एवं शक्ति-चलित ऊनी करघा उद्योग के हित के लिए ऊन की धुलाई की उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग के कोई प्रबन्ध किए हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में ऊनी मिलों में व इतर रूप से ऊन-धुनाई की उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कमीशन पर ऊन सफाई की कुल मंजूर की गई क्षमता 3.83 करोड़ पौंड प्रति वर्ष की है । इसमें से, अखिल भारतीय ऊन कोम्बर्स सहकारी सोसायटी लि. को मंजूर की गई 50 लाख पौंड की क्षमता काम में नहीं लाई जाती। काम में लाई जाने वाली कमीशन पर ऊन सफाई क्षमता 3.33 करोड़ पौंड है । जहां तक, बद्ध सफाई एककों का संबंध है, उन्हें केवल 25 फरवरी 1971 को समाप्त छः महीनों की अवधि के लिए कमीशन पर ऊन सफाई कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इस तारीख के पश्चात् वस्त्र आयुक्त द्वारा इस सुविधा की अवधि नहीं बढ़ाई गयी है ।

(ख) व्यापक रूप में ऊनी वस्त्र उद्योग के लाभ के लिए प्राप्य ऊन सफाई सुविधाओं के उपयोग हेतु वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने निम्नलिखित प्रबन्ध किये हैं :--

ऊन सफाई करने वाले सभी एककों को इस आशय के निदेश जारी किये गये हैं कि प्रत्येक कोम्बर के पास प्राप्य कुल प्रभावी ऊन सफाई क्षमता का आधा भाग, ऐसे कच्चे माल की सफाई के लिए अनन्य रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए जिसका विशेषतः उपयोग उस माल को तैयार करने में किया जाना है जिसका निर्यात पुख्ता क्रयोदेशों के आधार पर किया जायेगा या जो पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय की संविदाओं के आधार पर रक्षा कार्यों के लिए आवश्यक हैं । जहां कोम्बर के पास नवीन और फ्रेन्च दोनों प्रकार की ऊन सफाई क्षमता हैं, वहां निर्यात तथा रक्षा संबंधी उद्देशों के लिए क्षमता का 50 प्रतिशत आरक्षण नवीन तथा फ्रेन्च कोम्बर्स के लिए पृथक-पृथक लागू होगा । कच्चे माल की सफाई का कार्य दृढ़ता से 'पहले आवे पहले पावे' आधार पर किया जाना है । एक ओर निर्यातकों तथा रक्षा संबंधी संभरकों हेतु प्राथमिकता के आधार पर और दूसरी ओर शेष कार्यों के लिए ऊन सफाई 'पहले आवे पहले पावे' आधार पर की जानी चाहिए ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	राज्य	कमीशन पर सफाई	बद्ध आधार पर सफाई	योग (10 लाख पौंड में)
1.	पश्चिम बंगाल	13.00	–	13.00
2.	महाराष्ट्र	1.50	3.60	5.10
3.	उत्तर प्रदेश	3.00	3.75	6.75
4.	चंडीगढ़	4.50	–	4.50
5.	राजस्थान	3.00	–	3.00
6.	हरियाणा	0.80	–	0.80
7.	पंजाब	12.50	3.88	16.38
	योग	38.30	11.23	49.53

पश्चिमी बंगाल में बिजली का संकट

3942. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में बिजली के संकट को दूर करने के उपायों के बारे में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् मंडल अथवा राज्य सरकार के साथ कोई बातचीत की थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार अथवा राज्य विद्युत् मंडल से कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उस राज्य को बाहर के स्रोतों से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जाए अथवा बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में विद्युत् उपलभ्यता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तुत की है :

(1) अल्पकालीन उपाय के रूप में सिलिगुड़ी, कूच-बिहार' धीरपाद और जलपाईगुड़ी विद्युत्–केन्द्रों पर कुल 4.7 मेगावाट के पुराने डीजल विद्युत्–जनन सेटों का प्रतिष्ठापन।

(2) 200 मेगावाट का एक विद्युत्-जनन यूनिट देकर बंदेल ताप-विद्युत् केन्द्र का विस्तार।

(3) उत्तरी बंगाल में प्रतिष्ठापित क्षमता की अनुपूर्ति करने के लिए कुल 12 मेगावाट के डीजल विद्युत्-जनन सर्वे का आयात ।

(4) 200–200 मेगावाट की दो यूनिटों सहित कोलाघाट में एक नये तापविद्युत् केन्द्र की स्थापना ।

(ग) ऊपर (1) पर उल्लिखित स्कीम तो क्रियान्वित की जा चुकी है लेकिन अन्य तीन स्कीमों की केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में जांच हो रही है ।

इसके अलावा ऐसा प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सेन्टर में 120–120 मेगावाट के दो सेटों सहित डालखोला में एक तापविद्युत् केन्द्र की स्थापना की जाए जिससे उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार की विद्युत् संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।

Consumption of Coal and Diesel Oil in trains

3943. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value and quantity of coal and diesel oil utilised in trains during the last three years, year-wise;

(b) the estimated value thereof for the current year; and

(c) the reasons for the difference and the action being taken in this regard ?

The Minister for Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Quantity of coal and diesel oil consumed for traction purposes.

Year	Coal (Million tonnes)	Diesel oil (In million Litres)
1969-70 (Actuals)	15.22	536
1970-71 (Actuals)	14.32	566
1971-72 (Revised Estimate)	14.43	627
1972-73 (Budget Estimate)	14.18	683

(b) Cost of fuel for traction purposes.

Year	Total cost of coal, diesel oil and electric energy consumed for traction purposes. (In crores of rupees)
1969-70 (Actuals)	151.1
1970-71 (Actuals)	146.93
1971-72 (Revised Estimate)	154.50
1972-73 (Budget Estimate)	158.94

(c) Reasons for the difference and the action being taken in this regard.

There is reduction in coal consumption and increase in the diesel oil consumption over the years due to progressive dieselisation. The marked reduction in coal consumption and the value of total fuel consumed during 1970-71 were due to drop in the originating traffic.

Fuel economy receives close attention on Railways. The steps taken in this regard, *inter-alia*, include control on quality and consumption, prevention of losses and wastages, proper maintenance of locos and training of staff.

रेलवे सेवा आयोग को बम्बई से नागपुर ले जाना

3944. **श्री किशन मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित रेलवे सेवा आयोग को नागपुर ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसका राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के प्रत्याशियों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) यह निर्णय सेवा आयोगों को अधिक केन्द्रीय स्थानों पर स्थापित करने की मांग को पूरा करने और रेलों के लिए अनुदान की मांगों (1971-72) पर बहस की समाप्ति के अवसर पर 15-6-1971 को सदन में दिये गये मेरे बयान के अनुसरण में किया गया है।

(ग) जी नहीं।

विदेश व्यापार मंत्रालय में जन संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति

3945. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध के अन्तर्गत उनके मंत्रालय और उस से सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में जन-सम्पर्क अधिकारियों के पदों पर नियुक्त करने के लिए कोई नियम बनाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे सभा पटल पर इसकी एक प्रति रखेंगे ;

(ग) इस समय इन पदों पर नियुक्तियां किसी प्रकार की गई हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ली गई थी तथा इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए उनका अनुमोदन मांगा गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इस मंत्रालय में जन सम्पर्क अधिकारियों के पद के भर्ति नियम कार्मिक विभाग तथा संघ लोक सेवा

आयोग के परामर्श से बनाये जा रहे हैं। सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) तदर्थ आधार पर, जहां तक मुख्य मंत्रालय में इस पद का संबंध है।

(घ) जी हां।

धर्मनगर और सिलचर से लुमडिंग तक रात में रेल गाड़ी का चलाया जाना

3946. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या रेल मंत्री 28 मार्च 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 203/204 रेलगाड़ी रात के समय बदरपुर से लुमडिंग को नहीं चलती हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार धर्मनगर और सिलचर से लुमडिंग और गौहाटी तक रात के समय अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : ऐसी बात नहीं हैं। 203 अप/204 डाउन सवारी गाड़िया लुमडिंग और बदरपुर खन्ड पर रात के समय अवश्य चलतीं हैं। गाड़ी नं० 203 बदरपुर से 19—00 बजे छूटती है और लुमडिंग 5-00 बजे पहुंचती है। गाड़ी नं० 204 लुमडिंग से 18-45 बजे छूटती है और बदरपुर 5-05 बजे पहुंचती है। इस तरह असम मेल पकड़ने के लिए लुमडिंग में प्रतीक्षा-समय में काफी कमी हो गयी है।

(ख) जी नहीं, लेकिन 201/202 सिलचर गुवाहाटी सवारी गाड़ी का चालन क्षेत्र न्यू बोंगाईगांव तक बढ़ाया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Marketing Board for Tobacco

3947. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a Marketing Board is being set up for increasing production of tobacco and for the sale and export thereof;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the time by which the board is likely to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (c) A proposal for formation of a Tobacco Board to look after all aspects of Tobacco Industry is under consideration.

Shifting of Jawanwala City Railway Station (Kangra Valley)

3948. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government had acquired three years ago about 25 acres of land for the construction of new railway station and for laying of new line in order to shift Jawanwala city (Kangra Valley) Railway Station due to the construction of Pong dam there;

(b) whether nothing has been done so far either to shift the railway station or to lay the new line; and

(c) if so, whether Government propose to return the land to the land owners due to the suspension of the said scheme ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) to (c) Jawanwala Shahr station is not being shifted from its present premises, and no land is therefore being acquired for this purpose. However, about 24 acres of land was acquired in July 1971 at the present location of the station for development of the station yard and construction of offices, staff quarters, store yard, sub-station etc. in connection with re-alignment of the Narrow Guage line between Jawanwala Shahr and Guler. Though there has been delay in handing over the requisite land by the Beas Dam Authorities to the Railways, there is no proposal to suspend the re-alignment work. The question therefore of returning to the owners of the land, the land acquired at Jawanwala Shahr station for providing the facilities required in connection with the re-alignment between Jawanwala Shahr and Guler, does not arise.

त्रिपुरा को सीमेंट ले जाने के लिए वैगन

3949. **श्री दशरथ देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वैगनों के उपलब्ध न होने से सीमेंट त्रिपुरा नहीं ले जाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मानसून आरम्भ होने से पूर्व सीमेंट को त्रिपुरा ले जाने के लिए अपेक्षित वैगन आलाट करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) यह सही नहीं कि माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण त्रिपुरा को सीमेंट भेजा नहीं जा सका। जनवरी, फरवरी और मार्च, 1972 के दौरान दक्षिण-पूर्व, पूर्व और मध्य रेलों पर त्रिपुरा के लिए 156 माल डिब्बों में सीमेंट लादा गया।

(ख) इस क्षेत्र में शरणार्थियों के लिए बहुत भारी मात्रा में खाद्यान्न भेजने, इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था असंतोषजनक होने और तटवर्ती प्रतिकूल स्थितियों के कारण फरक्का बांध से होकर संचलन में होने वाली कठिनाइयों के कारण गत वित्तीय वर्ष के अधिकतम भाग के दौरान पूर्वी क्षेत्र में रेल प्रणाली पर भारी दबाव पड़ा जिसके कारण दूसरी सामान्य वस्तुओं के संचलन की तरह त्रिपुरा

के लिए सीमेंट के संचालन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा । फरक्का पर पुल खुल जाने से और सुरक्षा के लिए विशेष अभियानों की संख्या में क्रमशः कमी आने के कारण इस राज्य को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट भेजने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

रेलवे बोर्ड सहायकों के पद

3950. **श्री पी० के० घोष** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत 1 मार्च, 1972 तक सहायकों के कितने स्थायी और अस्थायी पद थे और वर्तमान आदेशों के अनुसार इनमें से कितने स्थायी और अस्थायी पदों पर सीधी भरती द्वारा नियुक्ति करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को कहा गया था ;

(ख) सहायकों के स्थायी और अस्थायी पदों पर वस्तुतः 1 मार्च, 1972 को संघ लोक सेवा आयोग ने सीधी भरती द्वारा कितनी नियुक्तियां की थीं ;

(ग) एक वर्ष की अवधि के ऐसे कितने स्थायी और अस्थायी रिक्त पद हैं जिनमें जून, 1972 में होने वाले आगामी सहायक ग्रेड परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मांग भेजी गई है ; और

(घ) यदि संघ लोक सेवा आयोग को इस प्रकार सूचित किये गये रिक्त पद सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले वर्तमान रिक्त पदों से कम हैं तो उसके क्या कारण हैं और शेष रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां की जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1-3-72 को रेलवे बोर्ड में सहायकों के स्वीकृत पदों की संख्या 359 स्थायी और 95 अस्थायी थी । रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियमों के अनुसार, स्थायी पदों में से 50% अर्थात् 180 पद लोक सेवा संघ द्वारा संचालित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने आवश्यक हैं ।

(ख) 138 स्थायी, 16 अस्थायी जिनमें से 5 शीघ्र ही कार्य-भार ग्रहण करने वाले हैं।

(ग) स्थायी पदों के लिए 8 ।

(घ) कमी को उत्तरवर्ती भर्ती वाले वर्षों में पूरा किया जायेगा ।

श्रेणी एक और श्रेणी दो के अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति

3951. **श्री अम्बेश** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी एक और दो के अधिकारियों के लिए एक स्थान पर रुकने की अधिकतम अवधि नियत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों का सार क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये एक स्थान पर कार्य करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी हैं। प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार, इनका स्थानान्तरण किया जाता है।

(ख) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के एक स्थान पर कार्य करने की अवधि के विषय में कोई आदेश नहीं हैं और न ही ऐसे आदेश आवश्यक समझे गये हैं।

चर्बी के लिए आयात लाइसेंस

3952. **श्री अम्बेश** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए भेड़-बकरी की चर्बी तथा अन्य प्रकार की चर्बी का आयात करने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) क्या इन कम्पनियों को अन्य प्रकार की चर्बी, जिसका प्रयोग साबुन बनाने में भी होता है, आयात करने के लिये पृथक लाइसेंस दिये जाते हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भेड़ की चर्बी का आयात 1971-72 और 1972-73 के दौरान राज्य व्यापार निगम की मार्फत मार्गीकृत किया गया है। आयातित माल मार्गीकरण करने वाले अभिकरण के द्वारा वास्तविक प्रयोक्ताओं को प्रायोजक प्राधिकारियों की सिफारिश पर या पंजीकृत निर्यातकों के लिये निर्यात नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में वितरित किया जाता है। 1971-72 और 1972-73 के दौरान जिन फर्मों को भेड़ की चर्बी दी गई है उसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। अन्य प्रकार की चर्बी के आयात की अनुमति नहीं है।

आंध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र को 'टैंक वैगनों' की सप्लाई

3953. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे में गूटी, अनन्तपुर, गूँटाकलम, येरा गुंटाला तदपत्री से बड़ी मात्रा में वनस्पति तेल बुक किया जा रहा है ;

(ख) क्या टैंक वैगनों की पर्याप्त संख्या में सप्लाई करने के लिए अभ्यावेदन दिया गया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए लदान में वृद्धि के लिए कार्रवाई की गयी है। 1969-70 की तुलना में दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलों पर टंकी माल डिब्बों में वनस्पति तेल के लदान में 1971-72 में 58.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। कुछ ठिकानों पर पर्यन्त सम्बन्धी

भारी विलम्ब को कम करने के लिए व्यापारी वर्ग से सहयोग के लिए आग्रह किया गया है ताकि लदान में और सुधार किया जा सके। जहाँ कहीं आवश्यक हो, अतिरिक्त टंकी माल डिब्बों का उपयोग करने के लिए भी कार्रवाई की गयी है।

आंध्र प्रदेश के लिए वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में अभ्यावेदन

3954. **श्री पी० वेंकटासुब्बय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के वेल्दुरथी बीटलचेरला, मलकापुर से दक्षिण मध्य रेलवे की मीटरगेज लाइन से बाराइटा, सेलखडी, शिलापट्टी, चूना पत्थर का पिण्ड तथा छिप्टी और राम रज जैसे खनिजों की बड़ी मात्रा में बुकिंग खनिज धातु व्यापार निगम सहित सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बहुत से महत्वपूर्ण उद्योगों को दूरस्थ स्थानों पर की जा रही है ;

(ख) क्या वहां रेल के डिब्बों की अनियमित तथा अपर्याप्त सप्लाई है जिसके कारण उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। तथा खान मालिकों के समक्ष भी वित्तीय कठिनाइयां पैदा हो रही है; और

(ग) क्या इस बारे में व्यक्तिगत रूप से अभ्यावेदन दिये गये हैं ; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वेतचेर्ला, मलकापुर और वेलदुर्ति स्टेशनों से चूना पत्थर, पत्थर की पटिया, सेलखड़ी आदि की ढुलाई हेतु अधिक मालडिब्बों की सप्लाई के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चालू वर्ष में इन स्टेशनों से इन वस्तुओं का कुल लदान अधिक हुआ है। 1 जनवरी से 10 अप्रैल, 1972 तक की अवधि के दौरान 2,591 माल डिब्बे लादे गये जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1,443 माल डिब्बे लादे गये थे। लदान और बढ़ाने के लिए प्रत्येक प्रयास किये जा रहे हैं।

Irrigation Scheme under D. V. C. for Bihar

3955. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any scheme for irrigation in Bihar has been formulated under the Damodar Valley Project; and

(b) if so, the broad outline thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) & (b) The Government of Bihar have proposed diversion of water from Tilaiya and Konar reservoirs in the Damodar Valley irrigating about 1,44,000 acres in Gaya and 1,70,000 acres in Hazaribagh districts respectively.

These proposals involve some inter-state aspects and can be considered for implemention after these are resolved.

नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन मजदूर संघ की मांगें

3956. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 48 मजदूरों की, जिन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन, आगरा में 10 से 15 वर्ष तक सेवा की है ; छटनी कर दी गई है ;

(ख) क्या नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन मजदूर संघ ने यह मांग की है की जिन मजदूरों की छटनी की गई है उनको वापस सेवा में लिया जाये ;

(ग) क्या नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन सेन्ट्रल वर्कशाप, आगरा के मंजदूर 22 मार्च, 1972 से हड़ताल पर हैं ; और

(घ) यदि, हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) आगरा स्थित राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन० पी० सी० सी०) केन्द्रीय कर्मशाला और भंडार में काम में भारी कमी हो जाने के कारण 40 कर्मचारियों की, जो फालतू पाए थे, 1-2-1971 से छटनी करनी पड़ी उनमें से किसी की नौकरी 10–15 वर्ष पूरी नहीं हुई थी । राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम कर्मचारी संघ के सदस्यों ने, जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ इन कर्मचारियों को फिर से नौकरी में लेने की मांग की थी, 20 मार्च, 1972 से हड़ताल कर दी । हड़ताल 18 अप्रैल, 1972 को वापस ले ली गई ।

कर्मचारियों को छटनी के मुआवजे और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन स्वीकार्य लाभों की अदायगी कर दी गई है । इसके अतिरिक्त उन्हें अनुग्रह के रूप में 3 महीने 15 दिन का वेतन दिया गया । छटनी किए गए कर्मचारियों ने ये शर्तें स्वीकार की थीं ।

नेशनल प्रोजेक्टस कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आगरा के जनरल सेक्रेटरी से ज्ञापन

3957. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल प्रोजेक्टस कारपोरेशन, आगरा के जनरल सेक्रेटरी, जिला मजदूर संघ और जिला कांग्रेस समिति, आगरा की उप-समिति के लेबर सैक्रेटरी से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ज्ञापन में मुख्य बाते राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन० पी० सी० सी०) को हुई क्षति और आगरा में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम केन्द्रीय कर्मशाला के 48 कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में थी ।

(ग) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन० पी० सी० सी०) को क्षति होने की मुख्य सहायक बातें यह है---खाली पड़ी मशीनों के मूल्यह्रास के सम्बन्ध में प्रावधान, कार्यों की पूर्ति के कारण फालतू श्रमिकों की धीरे-धीरे छटनी के परिणामस्वरूप फालतू श्रमिकों को अदायगी ; कार्यचालन पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए उधार पूंजी पर ब्याज की अदायगी। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन०पी०सी०सी०) की कार्यालयों में सुधार लाने के लिए विभिन्न पग उठाए गए है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल है बेकार और फालतू मशीनों का निपटान, फालतु श्रमिकों की छंटनी, निगम द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों की क्षेत्रीय जांच में सुधार और लागत नियंत्रण इसके अतिरिक्त निगम के लाभों में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नए कार्य प्राप्त करने के लिए एक आन्दोलन चलाया गया है। आगरा में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण (एन० पी० सी० सी०) केन्द्रीय कर्मशाला में कार्य की कमी होने के कारण 48 कर्मचारियों की, जिन्हें फालतू पाया गया था; छंटनी करनी पड़ी। इन कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश उद्योग विवाद अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य छंटनी का मुआवजा और लाभ दिये गये। इसके अतिरिक्त, उन्हें अनुग्रह के रूप में 3 महीने और 15 दिन का वेतन दिया गया। छंटनी किए गए इन कर्मचारियों ने ये शर्तें मान ली है।

बिजली परियोजनाओं के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता

3958. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार का विचार केरल राज्य को राज्य में बिजली परियोजनाओं के लिए कितनी धन राशि देने का है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल राज्य को वास्तव में कितनी राशि दी गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : चौथी योजना के प्रारम्भ से ही राज्य योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता उनके समस्त योजनागत व्यय के लिए न कि किन्ही विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है। चौथी योजना के लिए केरल को नियत की गई केन्द्रीय सहायता 175 करोड़ रुपयों की है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक व्यय पर आधारित अन्तर्राज्यिक पारेषण लाईनों के निर्माण के लिए केन्द्रप्रायोजित स्कीम के अधीन राज्यगत योजना से पृथक ऋण सहायता भी दी जाती है।

(ख) राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए 1971-72 के अंत तक केरल को दी गई ऋण सहायता की राशि 97.68 करोड़ रुपये है। केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अंतर्राज्यिक पारेषण लाइनों के लिए राज्य को 6.55 करोड़ रुपये की रकम दी गई।

केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना

3959. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971 के अन्त तक केरल में बन्द हुए काजू के कारखानों की संख्या क्या हैं ;

(ख) उन कारखानों के बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कितने कारखाने पुनः चालू हो गए हैं, और शेष कारखानों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1970-71 के दौरान केरल में 251 काजू फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई थीं तथा 1971 के अन्त फैक्ट्रियां बंद रही ।

(ख) मुख्य कारण ये थे :–

(i) कच्चे काजू की गिरियों की कमी ; तथा

(ii) वित्तीय कठिनाइयाँ ।

(ग) 1971 में 217 फैक्ट्रियां पुनः खुल गई। बंद फैक्ट्रियों को पुनः खोलने में सहायता देने के लिए केरल सरकार को 20 लाख रुपये का ऋण तथा केरल राज्य काजू विकास निगम को 90 दिन का 20 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

काजू और काली मिर्च के निर्यात व्यापार में सुधार करने के लिए नई योजना

3960. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों में काजू और काली मिर्च का निर्यात करके कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ; और

(ख) क्या काजू और काली मिर्च के निर्यात व्यापार में सुधार करने की सरकार की कोई नई योजना है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) (करोड़ रु० में)

वर्ष	काजू के निर्यात	काली मिर्च के निर्यात	योग
1969—70	57.42	16.2	73.62
1970—71	52.06	15.2	67.26
1971—72 (अनन्तिम)	61.73	14.8	79.53
	171.21	46.2	217.41

(ख) काजू और काली मिर्च के सम्बन्ध में निर्यात व्यापार सुधारने के लिए निम्नोक्त उपाय किये गये हैं :—

(1) **काजू** : विदेश व्यापार मंत्रालय की सिफारिशों पर कृषि मंत्रालय ने, कच्चे काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए चौथी योजना की शेष अवधि में 1 करोड़ रु० लागत वाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के अन्तर्गत एक द्रुतगामी कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसी आशा है कि इस योजना के अन्तर्गत 10,000 हेक्टार के अतिरिक्त क्षेत्र पर काजू बोया जायेगा।

(2) **काली मिर्च** : भारत ने इंडोनेशिया तथा मलयेशिया के साथ काली मिर्च समुदाय करार पर हस्ताक्षर किये हैं, ताकि प्रमुख काली मिर्च के उत्पादक देशों द्वारा ऐसे सामुहिक उपाय किये जा सकें, जिससे काली मिर्च की अर्थ-व्यवस्था पूर्णतः सुदृढ़ हो सके और अधिक निर्यात हो सकें।

केरल को बाढ़ से बचाने की योजना

3961. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य को बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) केरल सरकार ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए 1963 में 22.4 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की एक योजना का प्रारूप तैयार किया था। योजना में सम्मिलित निर्माण कार्यों की प्रमुख श्रेणिया और उनकी लागत नीचे लिखे अनुसार है :—

	(करोड़ रुपये में)
(1) संग्रह जलाशय	1.48
(2) तटबंध	3.43
(3) सरणियों और जल-निकास मार्गों का सुधार	10.04
(4) नदी नियंत्रण कार्य	2.47
(5) व्यपवर्तन और काटूनालियां	2.46

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में योजना के प्रारूप की जांच की जा चुकी है और 1963 के बाद की बाढ़ो के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार से योजना में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा संशोधित योजना को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। योजना के अंतिम रूप से तैयार होने तक, असुरक्षित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बचाव संबंधी उपायों का कार्यान्वयन राज्य योजना के अंग के रूप में किया जा रहा है।

धनबाद स्टेशन (पूर्व रेलवे) में कर्माशियल क्लर्कों, बुकिंग, पार्सल क्लर्कों तथा गुड्स आफिस में क्लर्कों की संख्या

3992. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के धनबाद स्टेशन के बुकिंग, पार्सल तथा गुड्स आफिस में अलग-अलग कर्माशियल क्लर्कों की प्रत्येक ग्रेड में संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) स्टेशन पर बुकिंग तथा पार्सल आफिस में रुपये 150-240 (ए) के ग्रेड में 'स्थायी तथा स्थानापन्न' कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उक्त कर्मचारी किस-किस तारीख से काम कर रहे ; और

(ग) स्टेशन स्टाफ को स्थानापन्न अवसर प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा बनाये गए नियमों की रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

यूरोपीय साझा बाजार के देशों तथा ब्रिटेन को निर्यात

3963. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में यूरोपीय साझा बाजार तथा इसके सदस्यों को दिये गये स्मारक पत्र आदि का सारांश क्या है ;

(ख) 1969 से लेकर अब तक यूरोपीय साझा बाजार को कितना निर्यात किया गया और यूरोपीय साझा बाजार में हमारे माल को क्या विभिन्न प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क सम्बन्धी बाधाओं का सामना करना पड़ा है ;

(ग) भारत के हित की मदों पर कामन एक्सटर्नल टैरिफ क्या है तथा इन मदों पर सदस्यों को क्या रियायतें प्राप्त है ; और

(घ) ब्रिटिश मण्डी में इस समय भारत को क्या राष्ट्रमण्डलीय प्राथमिकताएं प्राप्त हैं और ब्रिटेन द्वारा साझा बाजार में शामिल हो जाने के पश्चात् उन प्राथमिकताओं को बनाये रखने के लिए क्या भावी प्रबन्ध किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भेजे गए ज्ञापन, स्मारक-पत्र तथा अन्य अभ्यावेदनों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ घनिष्ठ व्यापार तथा वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने के लिए भारत की इच्छा तथा आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस संबंध में जिस प्रकार की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है वह है समुदाय के साथ वाणिज्यिक सहयोग करना। भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच प्रस्तावित वाणिज्यिक सहयोग करार का उद्देश्य होगा भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय

आर्थिक समुदाय के बाजारों में प्रवेश करने की शर्तों में सुधार करके भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार के आदान-प्रदान में अपेक्षाकृत अधिक उत्तम संतुलन प्राप्त करना। इन उत्पादों में विशेषत: ये शामिल हैं; पटसन की वस्तुएं, कयर उत्पाद, सूती वस्त्र, अनिर्मित तम्बाकू जैसे उत्पाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वर्तमान नीतियों के अंतर्गत भारत से जिनके आयातों को हानि पहुंचती है और हथकरघा के सूती तथा रेषमी वस्त्रों का सामान, हस्तशिल्प की वस्तुएं जिनके व्यापार के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है।

(ख) तथा (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय को 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के गत तीन वर्षों के दौरान क्रमश: 111 करोड़ रुपये 101 करोड़ रुपये, तथा 99 करोड़ रुपये के हमारे निर्यात हुए।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारत से आयातों पर लगे टैरिफ तथा गैर-टैरिफ प्रतिबंधों के ब्यौरे देने वाले दो विवरण इसके साथ संलग्न है (अनुबंध I तथा II)। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखीएं संख्या एल० टी० 1849/72.**]

सामान्यत: यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाजारों में सहयोगी राज्यों के उत्पादों की प्रविष्टि सीमा शुल्क तथा प्रभारों से मुक्त होती है। समुदाय सहयोगी राज्यों से आयातों के लिए तृतीय देशों के उत्पादों के आयात के लिए दिए जाने वाले सामान्य व्यवहार के मुकाबले में अधिक अनुकूल व्यवहार प्रदान करता है।

(घ) फरवरी 1972 में भारत सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा ब्रिटिश सरकार दोनों को अलग-अलग स्मारक पत्र भेजकर यह अनुरोध किया है कि भारत के व्यापार की समस्याओं के लिए उपयुक्त हल निकालने के उद्देश्य से परिवर्धित समुदाय तथा भारत के बीच प्रबंधों के संबंध में जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए ब्रिटिश बाजारों में भारत को इस समय उपलब्ध लाभों को 31 जनवरी 1975 तक अंतरिम अवधि के दौरान बनाये रखा जाये।

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प का विकास

3964. **श्री राम स्वरूप** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत हस्तशिल्प के विकास के लिए कितनी धन राशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है और इस बारे में यदि कोई कमी है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में दस्तकारों के रोजगार को स्थायी बनाने हेतु निधि का उपयोग करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) चौथी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय योजनाओं के लिए "हस्तशिल्प" के अन्तर्गत कुल योजना परिव्यय 8 करोड़ रु० है, जो राशि अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड तथा राज्य सरकारों को सौंप दी गई है। 1969-70 तथा

1971-72 में लगभग 40.75 लाख रु० की राशि का उपयोग किया जा चुका है। यद्यपि राशि के उपयोग किये जाने में कमी रही, पर यह मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई नई योजनाओं की सीमित संख्या के कारण थी। परन्तु आखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने हस्तशिल्प वस्तुओं के क्वालिटी उत्पादन, निर्यात संवर्धन, डिजाइन विकास, प्रशिक्षण, विपणन, गवेषणा, उन्नत औजारों तथा प्रविधियों, ऋण, प्रदर्शनियों तथा प्रचार सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं शुरू की हैं जिनका लक्ष्य देश के भीतर तथा भारत से बाहर, दोनों में, अधिक मांग बढ़ाना है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य हस्तकारों के लिये अधिक रोजगार उत्पन्न करना है।

दस्तकारी के क्षेत्रों के लिए मण्डी की सुविधायें

3965. **श्री राम स्वरूप :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र में पांच से दस करोड़ रुपये का सामान निर्यात करने वाले दस्तकारी क्षेत्रों में भी मण्डी सेवा सुविधायें (मार्केटिंग सर्विस) उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे क्षेत्रों से मण्डी सेवा सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) दस्तकारी वाले ऐसे क्षेत्रों की संख्या कितनी है जिनमें एक करोड़ रुपये से अधिक के माल के निर्यात की क्षमता है और चौथी योजना में कितने क्षेत्रों में मार्केटिंग सुविधायें करा दी जायेंगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए विपणन सम्बन्धी सुविधाएं, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न एम्पोरियमों के माध्यम से उपलब्ध हैं। देश में इस प्रकार के एम्पोरियमों की कुल संख्या लगभग 220 हैं। एक करोड़ रुपये से अधिक की निर्यात क्षमता रखने वाले दस्तकारी के क्षेत्र ये हैं:—

1. भदोही (मिर्जापुर)
2. सहारनपुर
3. मुरादाबाद
4. फरुखाबाद
5. जयपुर
6. त्रिवेन्द्रम
7. वाराणसी
8. बम्बई
9. अहमदाबाद
10. श्रीनगर

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने मुरादाबाद तथा नागरकोइल में दो बाजार विस्तार केन्द्र खोले हैं तथा कुछ और केन्द्र आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

लेखा विभाग (पश्चिम रेलवे) में क्लर्क ग्रेड एक में पदोन्नतियां

3966. **श्रीमती कृष्ण कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग में क्लर्क ग्रेड दो से क्लर्क एक में पदोन्नति के मामलों में शंकर सरन पंचाट, अर्थात् 75 प्रतिशत अर्हता प्राप्त कर्मचारियों और 25 प्रतिशत अनिर्हं कर्मचारियों को पदोन्नति देने सम्बन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ख) क्या क्लर्क ग्रेड एक से पदावनति के मामलों में भी सिफारिशों का पालन किया जा रहा हैं।

(ग) यदि हां, तो क्या 1 अप्रैल, 1968 से 24 सितम्बर, 1969 तक की अवधि में पदोन्नति तथा पदावनति के मामलों में उक्त सिफारिशों का पालन किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Appointment of Hindi Officers in Ministry

3967. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of sections and staff engaged in Hindi work in his Ministry and the Central Water and Power Commission and the service conditions of the staff ; and

(b) the steps being taken to improve the working of the Hindi sections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) There is one section each engaged exclusively on Hindi work in the Ministry proper and the Water and Power Wings of the Central Water and Power Commission with the following sanctioned posts :—

	Ministry Proper	Central Water and Power Commission	
		Water Wing	Power Wing
Hindi Officer	1	1	—
Translator Grade I	2	—	—
Hindi Assistant	1	—	1
Hindi Translator (Grade II)	2	3	4
Stenographer (Grade III)	1	—	—
L. D. Cs.	3	3	1

Considering the existing work load, the post of Hindi Officer and one post of Hindi Translator (Grade II) in the Power Wing have held in abeyance. The Hindi work of both

the Wings of the Central Water and Power Commission is being looked after by the Hindi Officer in Water Wing.

The best available staff is recruited to man the posts in Hindi Sections. Service conditions of staff working in Hindi sections are governed by general rules issued by Government from time to time. The work of these sections is reviewed from time to time to locate any shortcoming in regard to adequacy of staff, working conditions etc.

पश्चिम कोसी नहर परियोजना

3968. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के संबंध में कार्य अनुसूची, व्यय रेखांकन, भूमि अर्जन आदि ब्यौरों को नेपाल सरकार के साथ मिल कर अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तृत तकनीकी पहलुओं, जैसे संरेखण, डिजाइन और नहर संरचनाओं, पर 9 से 11 अप्रैल, 1972 तक काठमांडू में बिहार सरकार और नेपाल सरकार के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श और निर्णय हुआ था।

---

21 मार्च 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 936 के उत्तर में शुद्धी करने वाला वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING TO USQ NO. 936 DATED 21-3-1972

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : दिनांक 21 मार्च 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 936 के भाग (क) के उत्तर में मैंने कहा था कि कालीन अस्तर तथा हैसियन पर निर्यात शुल्क में 13-12-71 से 200 रु० प्रति मे० टन की वृद्धि की गई थी। निर्यात शुल्क में 400 रु० प्रति मे० टन की वृद्धि की गई थी, 200 रु० प्रति मे० टन की नहीं। मुझे खेद है कि यह गलती असावधानीवश हो गई।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की कथित सांकेतिक हड़ताल

एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ होने से पूर्व मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं । जीवन बीमा निगम के 42,000 कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने नियम 377 के अंतर्गत नोटिस दिया है। जीवन बीमा निगम के 42,000 कर्मचारी आज से सांकेतिक हड़ताल पर हैं। प्रबंधक कर्मचारियों की कठिनाईयों को दूर करने में असफल रहे है। श्री पाई ने आश्वासन दिया था कि न्यायसंगत मांगें मान ली जायेंगी तथा पूरी की जायेंगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपने कल के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है। परन्तु इस बीच जो 42,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं........

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए अनुमति दे दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह देश व्यापी हड़ताल है।

अध्यक्ष महोदय : यदि कहीं हड़ताल होती है तो उस पर चर्चा के लिये हम बाध्य नहीं हैं।

श्री शशि भूषण (दक्षिण-दिल्ली) : यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह हड़ताल प्रबंधकों के कठोर रूख अपनाये जाने के कारण हो रही है।

Shri Hukam Chand Kachawai (Murand) : I have also given a notice....

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सम्बन्ध में हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस बहुत समय पहले दिया था। जब हड़ताल आरम्भ नहीं हुयी थी। परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया। अब इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कल के लिये अनुमति मिली है। अब यह चर्चा शव परीक्षा के समान है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें प्रसन्नता है कि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए अनुमति दे दी है। मुझे शिकायत यह है कि सरकार को पता था कि 25 तारीख से हड़ताल आरम्भ हो रही है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी और हड़ताल आरम्भ होने दी गई। यदि एक दिन की सांकेतिक हड़-ताल के बाद भी कोई निर्णय नहीं किया गया तो मुझे भय है कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के झंडे के नीचे देशव्यापी हड़ताल हो जायेगी। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में आज एक वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य थोड़ी प्रतीक्षा करते तो मैं इस विषय को उचित समय पर सदन के सम्मुख रखता। परन्तु आप कार्यसूची की चिन्ता किये बिना ही प्रश्न काल के पश्चात् तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ होने से पूर्व यह मामला उठा बैठे। यही ठीक नहीं है। भविष्य में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि 42,000 कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो क्या आपने सोचा है कि एक सार्वजनिक संस्थान के कार्य के कितने घन्टे बेकार होंगे। हड़ताल को रोका जा सकता था परन्तु प्रबंधकों के कठोर रूख अपनाने के कारण ऐसा हुआ है। जितने कार्य के घन्टे बेकार होंगे, हमें करों के रूप में उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : आपकी अनुमति से.......

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह हानि प्रबन्धकों के कठोर रूख अपनाने के कारण हुई है।

श्री के० आर० गणेश : मुझे खेद है कि जीवन बीमा निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल का कारण यह है कि जीवन बीमा निगम तथा उसके कर्मचारियों के बीच चार वर्ष के लिए करार हुआ था जिस पर जून 1970 में हस्ताक्षर किये गये थे। यह करार 31 मार्च 1973 तक वैध है। अब कर्मचारी इस बात पर अड़े हुये हैं कि क्योंकि जीवन बीमा निगम को बहुत लाभ हुआ है इसलिये वे करार के चलते हुये भी इस मामले को उठाना चाहते हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): करार के कारण ही उन्हें हड़ताल करने के लिये बाध्य होना पड़ा है।

श्री के० आर० गणेश : करार के होते कर्मचारियों ने यह बात उठायी है। क्योंकि जीवन बीमा निगम को इस वर्ष अधिक लाभ हुआ है इसलिये कर्मचारी इस प्रश्न को पुनः आरम्भ करना चाहते हैं। जीवन बीमा निगम का कहना यह है कि जब तक यह करार चलेगा तब तक कोई भी बात चीत बेकार है। परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि जीवन बीमा निगम से इस विषय पर बात चीत करने का कर्मचारियों को अधिकार है।

जीवन बीमा निगम गत 15 वर्षों से स्वायत्त शासी निगम है। कर्मचारी जीवन बीमा निगम से परस्पर बातचीत करके मामले को सुलझा रहे हैं। यह करार जिनका संदर्भ दिया गया है, न्याय निर्णय के लिये भेजा गया था। तत्पश्चात् इस पर निर्णय हुआ और निर्णय पर करार के रूप में हस्ताक्षर किये गये। यह करार अब भी चल रहा है। और कर्मचारी फिर वही मामला उठाना चाहते हैं। क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुयीं इसलिये उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ यह एक स्वायत्त शासी निगम है जहाँ मामले पारस्परिक बात-चीत से निर्णीत होते हैं। पता नहीं श्री बनर्जी मुझ से क्या चाहते हैं! परन्तु एक ऐसे मामले में जिसमें 15 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है मुझसे आश्वासन देने के लिये नहीं कहा जा सकता। यह संभव नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I have given a notice regarding breach of privilege. I have been given wrong information in reply to my question.

Mr. Speaker: Hon. Member should not raise the matter of privilege while the discussion on a different matter is going on. You should know the rules. While one matter is under discussion, how you can raise another matter in between.

Shri Hukum Chand Kachwai : I have been waiting for two days.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुल प्रश्न यह है कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भेद भाव किया जाता है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन का 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जाता है जबकि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 रुपये तथा 15 रुपये मकान किराये भत्ते के रूप में दिये जाते हैं। चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें भी प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक दी जाती हैं। भवन निर्माण ऋण के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति है। अधिकारियों को स्टेट बैंक से ब्याज रहित ऋण मिलते हैं और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ऐसे ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

देना पड़ता है । प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को कार खरीदने के लिये बिना ब्याज 20,000 रुपये की राशि दी जाती है ।

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, जिसे तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का बहुमत प्राप्त है, को मान्यता देने की बात भी इसी विषय से सम्बन्धित है । प्रबंधकों ने मान्यता नहीं दी है । उक्त संघ को तत्काल मान्यता दी जानी चाहिये ।

मुझे खेद है कि मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं । सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण देश को इस हड़ताल से 42,000 कार्य के घन्टों की हानि होगी । यह सार्वजनिक उपक्रम है परन्तु प्रबंधक स्वयं इसे चला रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने करार का संदर्भ दिया है । क्या यह सच नहीं है कि करार के अंतर्गत आने वाले बहुत से महत्वपूर्ण मामलों का, करार पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् पुनर्विलोकन किया गया, उन पर फिर से विचार किया गया और पारस्परिक बात-चीत के परिणाम स्वरूप निर्णय किया गया । इसके परिणाम अच्छे निकले । जीवन बीमा निगम के कारोबार में वृद्धि हुई । सामान्य कार्य कुशलता में वृद्धि हुई तथा व्यय कम हुआ । जीवन बीमा निगम का कारोबार 1971-72 में वर्ष 1957 के 234 करोड़ रुपये से बढ़कर 1651 करोड़ का हुआ । परन्तु खेद की बात यह है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बोनस दर वर्ष 1957 से ही चली आ रही है ।

23 अक्टूबर 1971 को तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था कि मैं निगम के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों के विषय में कम चिन्तित नहीं हूँ । सुविधाओं के मामले में उन्हें अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के समान स्तर पर लाने के लिये मैं चिन्तित हूँ । इसके पश्चात् बंगला देश से बहुत से शरणार्थी भारत में आ गये । श्री पाई ने एक खुले पत्र में कर्मचारियों से कहा कि "बंगला देश से शरणार्थी आ जाने के कारण" देश नाजुक स्थिति से गुजर रहा है । देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझा पड़ गया है । अतः सुविधाओं के विस्तार के प्रश्न पर निर्णय के लिये देश के संकट मुक्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी ।" अब संकट समाप्त हो गया है । अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने एक वर्ष तक प्रतीक्षा की । अब क्योंकि बात-चीत बन्द कर दी गई है, श्री पाई ने त्याग पत्र दे दिया है और दूसरे अध्यक्ष ने उचित ढंग से बात-चीत नहीं की है तब पूर्व करार कर्मचारियों के मार्ग में बाधक नहीं है । मेरे विचार से बोनस के रूप में तीन मास का मूल वेतन दिया जाना चाहिये । कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाना चाहिये । यदि इस समय इस मामले पर गम्भीर रूप से विचार नहीं किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि किसी न किसी दिन सांकेतिक हड़ताल सामान्य हड़ताल का रूप ले लेगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : जीवन बीमा निगम के लगभग 42,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं । कर्मचारियों की कई पुरानी शिकायतों के अतिरिक्त जिनमें उनके संघ को मान्यता देना, जो कुछ समय पहले वापिस ली गई थी, मूल सिद्धांतों की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है । अब बोनस की भी मांग की गई है । मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कर्मचारियों को अधिक बोनस मांगने का हक है । बोनस की मात्रा की राशि के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय 1957 अथवा 1958 में किया गया था, जोकि डेढ़ महीने के बोनस के लिए था । बोनस लाभ का ही एक

रूप है। जीवन बीमा निगम ने जो लाभ कमाया है उसमें उसके कर्मचारियों का पूरा योगदान है। आज जिस दिशा में कर्मचारी चल रहे हैं उसे देखते हुए यह उनका हक है कि वह बोनस की मांग करें। अत: मेरा निवेदन है कि हमारे मंत्री महोदय यह क्यों नहीं कहते कि वे तुरंत जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के संघ के साथ बैठकर बोनस तथा अन्य सम्बद्ध प्रमुख समस्याओं पर उनसे बात चीत करेंगे और जो कुछ उचित होगा उस पर विचार करेंगे ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार और कर्मचारियों के बीच जो वर्तमान समझौता है क्या उसके अन्तर्गत कर्मचारियों के साथ किसी समस्या पर बात-चीत करने का अधिकार समाप्त किया गया है? मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए । यह बोनस तथा अन्य परिलब्धियों का मामला है। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी तथा तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भेद-भाव का मामला भी इसके अन्तर्गत आता है । कार्मिक संघ को मान्यता देने का प्रश्न भी इसके अन्तर्गत आता है । क्या प्रबंधकों को कर्मचारियों से बात-चीत करने अथवा किसी समस्या पर चर्चा करने में कोई आपत्ति है? मंत्री महोदय को इस समस्या का हल करने का प्रयास करना चाहिए ।

श्री के० आर० गणेश : जीवन बीमा निगम ने इन प्रश्नों पर चर्चा करने हेतु कर्मचारियों को 10 और 11 मई, 1972 को बुलाया है। श्री जोतिर्मय बसु ने वेतनों में अन्तर के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। वेतनों में जो अन्तर है 1970 में उसके बारे में चर्चा करके मामला न्यायनिर्णय के लिए दिया गया था। बाद में द्विपक्षीय बात भी हुई और एक समझौता भी किया गया। समझौते को एक न्यायाधिकरण के समक्ष रिकार्ड किया गया । मेरा विचार है कि कोई भी समझौता आगे चर्चा का मार्ग अवरुद्ध नहीं करता, क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत तो किसी भी समय की जा सकती है ।

जीवन बीमा निगम एक स्वायत्त संगठन है। 15 वर्षों से कर्मचारी बातचीत के द्वारा अपनी मांगे पूरी कराते रहे हैं । अब भी जीवन बीमा निगम ने कर्मचारियों को बातचीत हेतु बुलाया है। मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा के परिणामस्वरूप वे कोई ऐसा समझौता करने में समर्थ होंगे जो नियोजकों तथा कर्मचारियों दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा ।

जहाँ तक मान्यता का प्रश्न है, मामले को श्रम मंत्रालय की केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के पास भेजा गया है । किन्तु अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी परिषद् ने अनुशासन संहिता पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है और फरवरी 1972 में जो संकल्प पारित किया गया था उसमें परिषद् ने इस संहिता को अस्वीकार कर दिया है । मान्यता अनुशासन संहिता पर आधारित होती है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपने कहा था कि विवरण आधा घंटा पहले सप्लाई कर दिया जाएगा । किन्तु वह 11.45 म. पू. पर दिया गया है। वह हमारी तो परवाह करते नहीं, किन्तु अध्यक्ष महोदय की बात तो उन्हें माननी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि कभी कभी इस बारे में कठिनाइयां होती हैं । इसके बावजूद, मैं फिर निदेश देता हूं कि ऐसा किया जाय ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उड़ीसा की आदिवासी लड़कियों के अवैध एवं अनैतिक व्यापार का समाचार

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे :

"उड़ीसा की आदिवासी लड़कियों के अवैध एव अनैतिक व्यापार का समाचार।"

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : उड़ीसा के मयूरगंज जिले में गुरनमासैनी तथा बदमपहार में टाटा बन्धुओं के लौह खानों में कुछ वर्ष पूर्व खनन कार्य के बन्द हो जाने से खनन कार्य में लगे हुए श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए। उनमें से अधिकांश लोग आदिवासी समुदायों के थे। उनमें से कुछ निकटवर्तीय खनन क्षेत्रों तथा बिहार के औद्योगिक नगरों में चले गए शेष अभी भी बेरोजगार हैं। खनन ठेकेदारों की ओर से समय-समय पर भर्ती दलों द्वारा इस क्षेत्र में भर्ती की गई तथा भर्ती किए गए श्रमिकों को खनन क्षेत्रों तथा कारखानों में अधिकांशतः बिहार ले जाया गया।

उड़ीसा से हाल में दो घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें ठेकेदारों के स्थानीन एजेंटों द्वारा इस क्षेत्र से महिला श्रमिकों की भर्ती की गई। राज्य पुलिस के अनुसार, इस मामले में सितम्बर 1971 में इस क्षेत्र से तीन नवयुतियों तथा एक वृद्ध महिला को बिहार से सिंहगढ़ ले जाया गया, जहाँ से इन चारों स्त्रियों को अधिक वेतन दिलाने के बहाने से एक अनजाने स्थान पर ले जाया गया। परन्तु वृद्ध महिला किसी तरह उनके चंगुल से बच निकली और अपने गाँव वापिस आ गई। उसने वापस आकर, यह मामला गुरनमासैनी पुलिस थाने में दर्ज करा दिया।

दूसरी घटना रायरंगपुर की है। वर्ष 1971 में पूजा से कुछ दिन पहले, तीन लड़कियों को अधिक वेतन देने का लालच देकर फुसलाया गया और राज्य से बाहर ले जाया गया। वे लड़कियाँ अभी तक लापता हैं। लड़कियों के माता पिता ने पहले स्वयं खोज की फिर बाद में यह मामला नवम्बर 1971 में थाने में दर्ज कराया।

इन घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस के गुप्तचर विभाग को इस मामले की पूर्ण जाँच करने का आदेश दिया है।

राज्य सरकार ने सूचना दी है कि यह सही नहीं है कि बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से आदिवासी लड़कियों का अपहरण किया गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल ने मयूरगंज के निवासियों से सहयोग देने की अपील की है ताकि अपहरण के मामलों को रोका जा सके।

श्री डी० के० पंडा : वक्तव्य में कुछ बातों का उल्लेख या तो जानबूझ कर नहीं किया गया या सरकार इनसे अवगत नहीं है। सितम्बर 1971 में कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में लायी गयीं, पर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

दूसरे, वक्तव्य में कहा गया है कि गुरनमासैनी में खानें कुछ वर्ष पूर्व बन्द कर दी गई थीं। 1961 से यह खानें बन्द हैं तथा मयूरगंज निवासी जो इन खानों में काम करते थे बेकार हो गए हैं। बेरोजगार लोगों में से आदिवासियों की संख्या अधिक है क्योंकि मुख्यत: यह एक आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 60 प्रतिशत व्यक्ति आदिवासी हैं। तीसरे, वक्तव्य में आदिवासियों के प्रति सरकार के दायित्व का कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया जबकि संविधान में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि सरकार का आदिवासी क्षेत्रों के प्रति कुछ विशेष दायित्व है। उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 24.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों की संख्या 15 प्रतिशत के लगभग है। उड़ीसा के एक तिहाई क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बताया गया है। उड़ीसा में खानों के बन्द हो जाने तथा लौह अयस्क के इकट्ठा होने और वैगनों की अनुपलब्धता के कारण हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो गए है। इनमें से 90 प्रतिशत आदिवासी हैं।

जनजातीय विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में 1968 में एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने देश के सारे जनजातीय क्षेत्रों का दौरा किया था तथा कुछ सिफारिशें की थीं किन्तु तब से इनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक जांच आयोग की नियुक्ति करेगी ? क्या इन जनजातीय क्षेत्र से आर्थिक नैराश्य को दूर किया जायगा और क्या इस क्षेत्र में वैगन उपलब्ध करायेज ायेंगे, ताकि इकट्ठे हुए लौह अयस्क को वहां से हटाया जा सके ? पुलिस का कहना है कि अनैतिक पण्य दमन अधिनियम में बहुत संशोधन करने की आवश्यकता है। क्या सरकार इसमें आवश्यक परिवर्तन करेगी ? क्या एक केन्द्रीय दल को इसकी जाँच करने के लिए कहा जाएगा ?

अन्त में मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं। उड़ीसा के जिला गंजम के भंजनगर के तीन अधिकारियों ने एक आदिवासी लड़की से दुर्व्यवहार किया और जब हमें इस बात का पता लगा तो हमने इसके विरोध में एक जांच आयोग की नियुक्ति करने की प्रार्थना की। एक सैशन जज ने इसकी जांच की और कहा इनमें से एक अधिकारी वास्तविक दोषी है तथा अन्य दो ने उसका साथ दिया पर उड़ीसा सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही क्योंकि वह एक प्रतिक्रियावादी सरकार है। वह उल्टा अपराधी की सहायता कर रही है। क्या सरकार का विचार इन आदिवासियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का है ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने कई ऐसे प्रश्न उठाये हैं जो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं आते। उन्होंने आदिवासियों के विकास हेतु इस क्षेत्र में खनिज सम्बन्धी उद्योग स्थापित करने की सिफारिश की है। सरकार समय-समय पर इन लोगों के विकास हेतु समुचित कार्यवाही करती रहती है और इस क्षेत्र में कई उद्योग भी स्थापित किये जाने वाले हैं।

यह कहना ठीक नहीं कि सरकार ने अपहरण के मामलों में समुचित कार्यवाही नहीं की है। हमें वर्ष 1969 में ऐसे मामलों की जानकारी प्राप्त हुई थी तथा हमने उड़ीसा और बिहार की सर-

[श्री राम निवास मिर्धा]

कारों को लिखा था कि वे अधिक सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं पर गम्भीरता से विचार करें। हमने उन्हें इस बारे में भी सचेत किया था कि विधि तथा व्यवस्था बनाए रखना एवं विशेषतया ऐसे अपराधों को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। तब से अब तक हम इन दो राज्यों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।

परन्तु यह बात माननी होगी कि मामले दर्ज करना, उसकी जांच, करना लोगों को पकड़ना तथा उनपर मुकदमा चलाना मूल रूप से राज्य सरकार का कार्य है। केन्द्रीय सरकार इन विषयों के बारे में सतर्क रहती है। ऐसी घटनाओं के बारे में हम सूचना एकत्र कर रहे हैं। इन सूचनाओं को हम राज्य सरकारों के पास भेज रहे हैं तथा उनसे सतर्क रहने के लिये कह रहे हैं। ऐसे मामलों का पता लगाने के लिये राज्य सरकारें हर संभव प्रयत्न कर रही हैं।

जहांतक गंजम जिले के मामले का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है अतः मैं इस समय कुछ नहीं बता सकता।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): यह एक गम्भीर समस्या है। संसद में इस विषय पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। दुर्बल वर्ग के लोगों की स्थिति तथा जीवन को सुरक्षित रखने के लिये कई संसद सदस्यों ने मंत्री महोदय तथा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि सरकार ने गुप्तचर विभाग के अधिकारी की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया है। जब गुप्तचर विभाग के अधिकारी ने ऐसी घटनाओं पर खेद तथा चिन्ता व्यक्त की है तो वह यह जांच किस प्रकार कर सकता है कि आदिवासियों के साथ न्याय किया जाता है अथवा नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि "मानव का पण्य और बेट-बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिसिद्ध किया जाता है और इस उपलब्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।" जब संविधान में ऐसी व्यवस्था है तो केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से मामले की जांच करने के लिये कहने की क्या आवश्कता है। ये दलित वर्ग के लोग अतितकाल से अमानवीय व्यवहारों से पिसते रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही आदिवासियों के समक्ष अनेकों कठिनाइयां तक समस्यायें हैं। सरकार ऐसे मामलों की जांच करने के लिये विशेष आयोग का गठन क्यों नहीं करती है जिससे जब भी कोई ऐसा मामला हो उसकी अविलम्ब जांच की जा सके। दूसरे सरकार को चाहिये कि आदिवासियों को ठेकेदारों तथा स्वार्थी व्यक्तियों के शोषण से बचाने के लिये एक विशेष संस्था आदिवासियों की सेवा हेतु बनाये।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि उन क्षेत्रों से 2000 लड़कियों का अपहरण किया गया परन्तु राज्य सरकार ने हमें बताया है कि यह सच नहीं है। उसे इस बात का पता नहीं है। उसके पास जो भी मामले हैं, वह उनकी जांच कर रही है। पहले इस मामलों की पुलिस ही जांच कर रही थी परन्तु चूंकि ये महत्वपूर्ण मामले थे अतः इनकी जांच के लिये सी० आई० डी० एजेन्सी को लाया गया है।

विशेष जांच आयोग का गठन करना संभव नहीं है। हमारे देश के कानूनों के अन्तर्गत इन मामलों की जांच करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

ठेके के मजदूरों की प्रथा समाप्ति का प्रश्न व्यापक है जिसके बारे में श्रम मंत्रालय कुछ कह सकता है ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच): वक्तव्य में कहा गया है कि खनन कार्यों के बंद हो जाने से अनुसूचित जन जातियों तथा समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों की बहुत सी लड़कियां बेरोजगार हो गई यह कार्य 1967 में हुआ था । क्या इन बेरोजगार व्यक्तियों को पुन: रोजगार देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, क्योंकि जिन मामलों का समाचार है वे अपहरण के साधारण मामले नहीं हैं । स्त्रियों तथा लड़कियों को अश्लील कामों के लिये भगा ले जाने को रोकने का सीधा उत्तरदायित्व केन्द्र का है । इस खतरनाक स्थिति के बारे में उड़ीसा की पुलिस के महानिरीक्षक ने सार्वजनिक घोषणा की । इससे स्पष्ट है कि स्थिति अधिक गंभीर है जो दो मामले स्थानीय पुलिस के पास दर्ज कराये गए हैं उनसे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि स्थिति उन दोनों मामलों तक ही सीमित है । क्या मंत्री महोदय जांच समिति के माध्यम से विस्तृत जांच करवायेंगे कि ऐसे और कितने मामले हैं तथा उन्हें भविष्य में होने से रोकने के लिये इन युवा लड़कियों को रोजगार देकर कोई कार्यवाही की जायेगी ? खनन कार्य बंद करने के परिणामस्वरूप न केवल लड़कियों को ही निकाला गया है अपितु पुरुषों को भी निकाला गया है । स्पष्ट है कि इस घृणित कार्य में सिद्धान्तहीनता तत्त्व अन्तर्गत हैं । क्या उन लड़कियों से वेश्यालयों में अश्लील कार्य करवाये गये थे अथवा करवाये जा रहे हैं ? समाचार-पत्रों में ऐसा समाचार हैं कि रोजगार देने के लालच से इन लड़कियों से वेश्यालयों में अश्लील कार्य करवाया जा रहा है ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह सही है कि 1967 में खनन कार्य बंद हो जाने के बाद उस क्षेत्र में थोड़ी बेरोजगारी रही है, परन्तु आस-पास के क्षेत्रों में बहुत से उद्योग-धंधे पनप रहे हैं । यह बात ध्यान में आई है कि जहां रोजगार उपलब्ध है वहां इन स्त्रियों को आदिवासी क्षेत्रों से लाया जा रहा है, यथा उनका अपहरण किया जा रहा है अथवा उन्हें फुसलाया जा रहा है ।

जहां तक जांच आयोग के गठन का प्रश्न है, इसके गठन से कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा । कुछ ठेकेदारों द्वारा गड़बड़ की जा रही है तथा राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिये ठोस कार्यवाही कर रही है । इस कार्य को व्यापारिक दृष्टि से करने वाले व्यक्ति निकृष्ट अपराधी हैं । राज्य सरकार ने इस कार्य के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों के नाम बताये है तथा वह उनके विरुद्ध जांच कर रही है ।

केन्द्रीय सरकार इस बारे में चिंतित है तथा हम राज्य सरकार से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं । यदि इस गिरोह को पकड़ने के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय पुलिस एजेन्सियों की आवश्यकता हैं तो उसकी सेवायें देने के लिये पेशकश की है ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): वे बहुत ही जघन्य अपराध करते हैं । यह बहुत गंभीर मामला है तथा सरकार इसे गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है । सी० आई० डी० के जांच करने वाले अधिकारी ने आदिवासी लड़कियों की संख्या 2000 बताई जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा अन्य राज्यों को ले जाई जा रही हैं । यह नई बात नहीं है । 1965 से आज तक ऐसा होता रहा है । क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना दी है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ? क्या ऐसे अपराधियों को पकड़ना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य नही है जो लड़कियों को वेश्यालयों में बेच रहे

[श्री चिंतामणी पाणिग्रही]

हैं ? उन व्यक्तियों को शर्म आनी चाहिये जो हमारी महिलाओं का, आदिवासियों का सम्मान नहीं रख सके हैं । उन व्यक्तियों को शर्म आनी चाहिये जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के विरुद्ध कार्यवाही की, विरोधी दल के नेता के विरुद्ध कार्यवाही की तथा संसद सदस्यों एवं विधायकों को पीटने की कार्यवाही की। यह ऐसा मामला है जिस पर भारत सरकार का ध्यान तुरंत जाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. . . .

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : वह मार्क्सवादी हैं । वह वहां पर स्वतंत्र सदस्यों से मिले हुए हैं । उन्होंने उत्कल कांग्रेस से मिलकर वहां चुनाव लड़े थे. . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : दो वर्ष पूर्व अध्यक्ष-पीठ द्वारा जो विनिर्णय दिया गया था उसका पालन करते हुए हम राज्य सरकार अथवा मुख्य मंत्रियों की यहां सभा में आलोचना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे अपना बचाव करने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं । श्री पाणिग्रही ने जो कुछ कहा है तथा अध्यक्ष-पीठ ने उनसे ऐसा न कहने के लिये कुछ नहीं कहा है, इसे देखते हुए इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही उस राज्य के रहने वाले हैं अतः थोड़ा भावुक होना स्वाभाविक ही है । श्री पाणिग्रही मंत्री महोदय के वक्तव्य का खंडन कर रहे हैं । वह विषय से थोड़ा दूर चले गये हैं परन्तु इसमें व्यवस्था का प्रश्न तो कुछ नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने इस सभा में एक बार किसी राज्य सरकार की आलोचना की थी तब आपने उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही ह तथा मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार हर सम्भव कार्यवाही कर रही है। इसमें गलत क्या है ?

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा): उन्होंने कहा है कि उड़ीसा सरकार इस भगा ले जाने के कार्य को प्रोत्साहन देती रही है । यह सर्वथा गलत है । **(व्यवधान)** इसका सत्यापन किया जाये कि यह सच है या फिर इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : कारण कुछ भी हो परन्तु भावुक होना भी स्वाभाविक है ।

श्री राम निवास मिर्धा : जो कुछ घटना घटी है वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और श्री पाणिग्रही जैसे माननीय सदस्यों आवेश आना या क्षुब्ध होना स्वाभाविक है । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिये आदिवासी लोगों का, गरीब तथा पिछड़े होने के कारण, शोषण कर रहे है। भारत सरकार स्थिति में सुधार करने तथा अपराधियों को सजा देने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी । हमारी अपनी एजेन्सी ने इन घटनाओं से हमें अवगत कराया और इस मामले पर हम अपने-आ; उड़ीसा तथा बिहार की सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं । इन घृणित कार्यों का दमन करने के लिये हमने उन्हें हर संभव सहायता देने की पेशकश की है ।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला): समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि इस वर्ष लगभग 2000 आदिवासी लड़कियां इन तहसीलों से लाई गई हैं। एक वर्ष में 2000 लड़कियां लाई गई हैं तो न जाने पहले कितनी लाई गई होंगी।

राज्य के सी० आई० डी० अधिकारी का कहना है कि उनके चलने के बाद उनमें अधिकांश के अते-पते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर राज्य सरकार कहती है कि कोई गंभीर बात नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, सी० आई० डी० अधिकारी ने स्वयं कहा है कि ठेकेदार अथवा भगा ले जाने वाले प्रति लड़की 100 रुपये लेते हैं। आज स्वतंत्र भारत में इस प्रकार मानवों को बेचा जाता है इससे और अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है?

यह नया वर्ग, यह ठेकेदार वर्ग जो पूंजीपति प्रथा का ही एक भाग है, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में इस समस्या को उत्पन्न करता है।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

इस समस्या का मूलतः समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ताकि नगरीय क्षेत्र में इन महिलाओं को वेश्यालयों के रूप में न बेचा जा सके। सरकार ने इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि ठेकेदारों के विरुद्ध अमुक कार्यवाही की गई। राज्य सरकार ने इन ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? अपराधी व्यक्तियों को सजा देने के क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री राम निवास मिर्धा: हमने समाचार-पत्रों में इस क्षेत्र से भगाई गई लड़कियों की संख्या 2000 देखी है परन्तु राज्य सरकार इस बात से इन्कार कर रही है। जांच करने वाले अधिकारी ने इस बारे में जो कुछ कहा है उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। हमने इन बातों को राज्य सरकार की टिप्पणी हेतु भेज दिया है। राज्य सरकार ने हमें सूचना दी है कि कुछ मामलों को छोड़कर, जिनकी उचित ढंग से जांच की जा रही है, बहुत बड़े पैमाने पर अपहरण के मामले नहीं हुए हैं।

संविधान के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये सरकार का जो उत्तरदायित्व है उसे हम निभा रहे हैं, परन्तु हमें ऐसी शक्तियां नहीं मिली हुई है कि हम अपने आप किसी विशेष राज्य में जाकर पुलिस की शक्तियां अपने हाथ में लेकर अपराधियों को पकड़े। राज्य सरकार स्थिति के प्रति जागरूक है तथा हम यह प्रयास करेंगे कि इस सभा में जो आरोप लगाये गये हैं। उनके बारे में कुछ और अधिक बातों का पता लग सके। हम राज्य सरकार के साथ साथ मिल कर भर-सक प्रयत्न करेंगे तथा जिन अपराधियों के नामों का पता लगा है उन्हें सजा दिलायेंगे। कुछ अपराधी फरार हैं। हम इस मामले के पीछे पड़े हुए हैं।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा): हम चाहते हैं कि इस विषय पर पूर्ण चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर विचार करूंगा।

सदस्य की रिहाई

RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर से प्राप्त दिनांक 23 अप्रेल 1972 के एक तार की सूचना देनी है, जिसमें बताया गया कि लोक सभा के सदस्य, श्री मोगेन्द्र झा को जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत विचारण के लिये जिला जेल, मिर्जापुर में अवरूद्ध किया गया था, विचारण होने तक की अवधि के लिये, मुचलका देने पर 24 अप्रेल, 1972 को जेल से रिहा कर दिया गया है।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

43 वां तथा 45 वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:—

(1) सीमा शुल्क के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1969—70 संबंधी प्रतिवेदन के अध्याय 2 केन्द्रीय सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियों के बारे में 43 वां प्रतिवेदन।

(2) विनियोग लेखे (रेलवे) 1969—70 और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1969—70 संबंधी प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (रेलवे) के बारे में 45 वां प्रतिवेदन।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

7 वां प्रतिवेदन

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : मैं रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति, के लिये आरक्षण के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 7 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की मांगे

DEMANDS FOR GRANTS

विदेश मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रखेंगे । श्री दशरथ देव मध्यान्य भोजन के उपरान्त अपना भाषण दें ।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock).

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर तीन मिनिट (म० प० पर पुन: समवेत हुई) ।

(The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past Fourteen of the Clock).

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : कल मैं बता रहा था कि किस प्रकार अमरीकी साम्राज्य जिसका रवैया कुछ माह पूर्व भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है, एशिया के अन्य भाग का दमन करने का प्रयत्न कर रहा है । भारत सरकार वियतनाम पर अमरीकी बमबारी की निन्दा नहीं कर रही और वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार और सैगोन की कठपुतली सरकार को एक लाठी से हांक रही है ।

हमारा दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने तथा सैगोन सरकार से अपने सम्बन्ध तोड़ने की मांग करता रहा है । परन्तु खेद की बात है कि सरकार ऐसा करने में हिचकिचा रही है । हमारा दल सरकार के इस वक्तव्य का समर्थन करता है जिसमें वियतनाम से विदेशी फौजें हटाने की मांग की गई है और युद्ध के लिए अमरीकी सरकार को दोषी ठहराया गया है ।

सैगोन की कठपुतली सरकार सारे एशिया के लिए घातक बनी हुई है और एशियाई राष्ट्रों की आबादी को खतरे में डाल रही हैं । वही सरकार हजारों नागरिकों के बमबारी से मारे जाने की जिम्मेदार है । ऐसी सरकार को मान्यता दिए रखना सरकार के लिए अपराध है ।

बंगला देश के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं । परन्तु दोनों देशों में ऐसे समाज-विरोधी तत्व विद्यमान है जो अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं । सरकार को इन गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो हमारे सम्बन्ध खतरे में पड़ सकते हैं । बंगला देश को सरकारी स्तर पर सहायता देनी चाहिए, अन्यथा पूंजीपति अपने स्वार्थ पूरे कर हमारे आपसी सम्बन्धों को बिगाड़ देगें । हमारी नीति पाकिस्तान और चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने की रही हैं । विदेश मंत्रालय के प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि हाली ही के युद्ध तथा 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया और हमें भी उसका जवाब देना पड़ा । ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के

[श्री दशरथ देव]

लिए भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बात करने और विवादों को निपटाने पर विचार कर रही हैं। मेरे विचार में भारत सरकार को अपने इस रवैये पर कायम रहना चाहिए। चीन के साथ भी हमें अपने सम्बन्ध बातचीत के जरिए सुधारने चाहिए।

गत 20 वर्षों से भारत सरकार साम्राज्यवादियों के हाथों का खिलौना बनी रही। भारत सरकार को चाहिए कि वह अब शांति और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएँ और समाजवादी सरकारों से अपने सम्बन्ध कायम करें।

हमें समाजवादी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। जिस प्रकार चाइल के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हैं उसी प्रकार क्यूबा के साथ भी होने चाहिए।

अमरीका द्वारा जातिगत भेद भाव की नीति अपनाने के कारण वहाँ रह रहे भारतीयों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार को इसकी निन्दा करनी चाहिए। साथ ही हमें अफ्रीकी लोगों का समर्थन करना चाहिए जो दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया की जातिगत भेद-भाव की नीति अननाने वाली सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही हमें लातीनी अमरीकियों का भी समर्थन करना चाहिए जो अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

सभापति महोदय : हर दल के लिए समय नियत किया गया है यदि प्रत्येक दल अधिक समय लेगा तो मेरे लिए चर्चा को जारी रखना कठिन हो जाएगा।

श्री उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : विरोधी दल हमेशा यह कहते रहे है कि भारत सरकार साम्राज्यवादियों का समर्थन कर रही है और गुट निरपेक्षता की नीति न अपनाकर साम्यवादियों की नीति अपना रही है। खेद की बात है कि गत 25 वर्षों के दौरान विपक्षी दलों ने यह कभी स्पष्ट नहीं किया कि अगर सत्ता उनके हाथों में दे दी जाए तो वह क्या करेंगे .... (**व्यवधान**)

जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, हम अपने वचनों पर अडिग रहे हैं और हमने हमेशा शांति का समर्थन और साम्राज्यवाद का विरोध किया है। गत एक वर्ष में हमने इस उप-महाद्वीप में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। परिणामस्वरूप, एक स्वतंत्र राष्ट्र का अभ्युदय हुआ। हम उपमहाद्वीप में स्थायीरूप से शांति बनाए रखना चाहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई परिवर्तन हुए। हमने गत वर्ष सोवियत संघ के साथ एक संधि की जिसका सभी भारतवासियों ने स्वागत किया।

यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण घटना बर्लिन समझौता है। हम आशा करते है कि इस समझौते की पुष्टि की जाएगी क्योंकि विश्व के इस भाग में भी शांति को खतरा है। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्री सम्बन्धों में यूरोप का बहुत अधिक महत्व है। इससे हमें नए अवसर मिले हैं तथा हम पर कई जिम्मेदारियाँ आ गई हैं।

एशियाई क्षेत्र के लिए सामूहिक सुरक्षा का विचार केवल ब्रिजनेव सिद्धान्त का भाग नहीं, अपितु भारतीय सिद्धान्त का भाग भी है। यह भारतीय विचार है। क्योंकि भारत एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा तथा शांति चाहता है। विश्व शांति के लिए इस क्षेत्र में शांति का होना बहुत जरूरी है।

जहां तक भारत-रूस संधि का संबंध है, रूस ने हमारा साथ दिया है तथा संसार में शायद रूस ही एक मात्र ऐसा देश है जिसने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया। वे हमारा साथ देते रहेंगे तथा हमें आशा है कि रूस और अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के साथ हमारे सम्बन्ध और सुदृढ़ होंगे।

अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध दिन प्रति दिन बिगडते जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में सांतवे बेड़े के आने से इन सम्बन्धों पर और भी कुप्रभाव पड़ा है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हम स्वतंत्रत के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। अमरीका में भारत के राजदूत ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के निकट आना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि विदेश नीति भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है या राजदूतों द्वारा। अगर अमरीका को गरज है तो वह स्वयं हमसे बातचीत करेगा।

कई माननीय सदस्यों ने मांग की है कि सरकार अरब राज्यों की प्रतिक्रिया को देखते हुए स्थिति का पुनरीक्षण करें लेकिन मेरे विचार में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि अरब, देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। मैं आशा करता हूँ कि विदेश मंत्रालय लातीनी अमरीका में न केवल चाईल के साथ बल्कि वेंजुएला और कोलम्बिया के साथ भी अपने निकट सम्बन्ध कायम करेगा।

निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में बातचीत करने के बारे में भारत उतना सक्रिय नहीं है जितना कि पहले था। विश्व में भारत के अनेक मित्र देश इस बारे में काफी चिन्तित हैं। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

जहाँ तक विदेशी सेवाओं की समस्याओं का प्रश्न है, यद्यपि सरकार नीतियाँ बनाती हैं तथापि इनका क्रियान्वयन विदेश मंत्रालय और विदेशों में भारत के दूतावासों द्वारा किया जाता है। इसमें कोई सदेह की बात नहीं कि गत वर्ष में श्री टी० एन० कौल और श्री डी० पी० धर ने बहुत सराहनीय कार्य किया, परन्तु कई दूतावासों का कार्य ठीक प्रकार नहीं चल रहा।

देश में यह समझा जाता है कि हमारी विदेश सेवा के अधिकारियों को बहुत अधिक वेतन दिया जाता है। परन्तु यह सही नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में एक अधिकारी को आरम्भ में 1250 रुपये मिलते हैं और भारतीय विदेश सेवा में एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी को आरम्भ में 400 रुपये मिलते हैं। विदेश सेवा की समूची समस्याओं की पूर्ण जाँच की जानी चाहिए न केवल वेतन वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अपितु अन्य संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भी एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।

देश का निर्माण वस्तुतः देश में हो रहे विकास पर निर्भर करता है। मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों और हमारे दल के सहयोग से भारत की प्रतिष्ठा विश्व में और बढ़ेगी।

विदेश मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं.	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
9	19.	श्री एच० एन० मुकर्जी	अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्षरत क्यूबा, चिली और अन्य लैटिन अमरीकी देशों	100 रुपये

1	2	3	4	5
			के साथ निकट वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने की आवश्यकता ।	
9	19.	श्री एच० एन० मुकर्जी	अफ्रीका के प्रगतिशील देशों के साथ भारत के सम्बन्धों की कमी को दूर करने के लिये विशेष प्रयास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9	20.	,, ,,	जर्मन लोकतंत्री गणराज्य के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध तुरन्त स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
9	21.	,,	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को तुरन्त मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
9	22.	श्री ज्योतिर्मय बसु	दक्षिण वियतनाम की सरकार के साथ जो अमरीका की कठपुतली सरकार है, सम्बन्ध तोड़ने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जावे
9	23.	,,	वियतनाम, लाओस और कम्बोदिया में साम्राज्यवादी अमरीका के सैनिक हस्तक्षेप की स्पष्ट शब्दों में निंदा करने में असफलता ।	,,
9	24.	,,	विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितो की सुरक्षा के लिए ठोस और जोरदार कदम उठाने में असफलता ।	,
	25.	,,	दक्षिण वियतनाम को अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को राजनीतिक मान्यता देने में असफलता ।	,,
	26.	,,	जर्मनी लोकतंत्री गणराज्य को राजनीतिक मान्यता देने में असफलता ।	,,
9	27.	,,	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में ब्रिटेन की रायल एअर फोर्स के विमानों को ईंधन के लिए उतरने हेतु दी गई सुविधा को वापस लेने में असफलता ।	,,
9	28.	,,	"स्वेच्छिक व्यय" के अन्तर्गत बिना लेखे-जोखे की धन राशि का, जिसके लिये कोई विवरण नहीं दिये गये हैं अथवा नहीं दिये	13,88,00,000 रुपये

1	2	3	4	5
			जा रहे हैं तथा इस धन राशि का गृह मंत्रालय के अधीन, जिसके प्रभारी प्रधान मंत्री हैं, "गवेषणा और विश्लेषण कक्ष," एक गुप्त संगठन की गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिये व्यय किया जा रहा है।	
9	29.	श्री ज्योतिर्मय बसु	देशों में स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों तथा मिशनों में भ्रष्टाचार।	100 रुपये
9	30.	,,	विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों और मिशनों के व्यय में कमी करने की आवश्यकता।	,,
9	31.	,,	जनवादी गणतंत्र चीन के साथ शांति पूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के आधार पर सम्बन्धों को सामान्य बनाने की आवश्यकता।	,,
9	32.	,,	एक ओर भारत तथा दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच मैत्री सम्बन्धों को बनाये रखने और उनमें वृद्धि करने की तुरन्त आवश्यकता।	,,
9	33.	श्री एन० श्रीकान्तम् नायर	श्रीलंका में भारतीय तथा भारत-मूलक लोगों के हितों की रक्षा करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।
9	34.	,,	पाकिस्तान के साथ युद्धबन्दी के पश्चात् राजनयिक प्रयत्नों में शिथिलता।	,,
9	35.	,,	मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों में भारतीय कूटनीति की असफलता।	,,
9	36.	,,	हमारे दूतवासों में अक्षम तथा अनुत्तरदायी राजनीतिक कर्मचारियों को बनाये रहना।	,,

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व): यह वर्ष हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति का रजत जयन्ती वर्ष है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी वर्ष बंगला देश का अभ्युदय हुवा। हम इस देश के पुनर्निर्माण में सहयोग दे रहे हैं और यह हमारे लिए सन्तोष का विषय है।

हम देश से गरीबी को पूरी तरह हटाना चाहते हैं। गरीबी हटाने का कार्यक्रम हमारी जनता का एक ऐसा संघर्ष है जिससे हमें देश में पूर्ण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक क्रांति लानी है और इसका

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

अमरीका द्वारा चीनी नेताओं के साथ सांठ गांठ करके विश्व में साम्राज्यवाद की नीति को हटाने के लिए किए जा रहे संघर्ष से गहरा सम्बन्ध है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि हम सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के साथ अपनी मित्रता को और प्रगाढ़ बनाएं।

माननीय विदेश मंत्री को समस्याओं के आंतरिक पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने बंगला देश को मान्यता देने में काफी विलम्ब किया। सरकार कई मास तक यही तर्क देती रही कि अभी बंगला देश को मान्यता देने का समय नहीं आया है। इसी प्रकार माननीय विदेश मंत्री वियतनाम की अस्थायी क्रांतोकारी सरकार को भी मान्यता देने में हिचकिचा रहे हैं। मंत्री महोदय का यह कथन कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अमरीकी सरकार सैगोन सरकार की सहायता कर रही है, भी हास्यास्पद है। विदेश मंत्री का यह कहना कि दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतीकारी सरकार कभी मान्यता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, समझ में नही आता। उन्होंने यह किस प्रकार कहा है कि विश्व के उस भाग में जो कुछ हो रहा है वह अब असाधारण सा लगता है जब कि ऐसा वहां कई वर्षों से होता चला आ रहा है यह अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री ने वियतनाम के स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस तथा उच्च भावनाओं की सराहना की है। किन्तु यह भावना किसी ठोस कार्यवाही में परिवर्तित की जानी चाहिए।

यद्यपि निक्सन ने उत्तर वियतनाम में अपनी हिंसक कार्यवाहियां तेज कर दी है किन्तु कभी न कभी उन्हें इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि अमरीका के भय को हम अपनी विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग न समझें। हमें सैगोन जैसी हिंसक तथा कठपुतली सरकार के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध समाप्त कर देने चाहिए और दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए।

पिछले सत्र के दौरान दोनों सदनों के 500 से अधिक सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें जर्मन जनवादी गणराज्य को तुरंत मान्यता देने की मांग की गई थी। हमने अभी तक पूर्वी जर्मनी के साथ पूर्ण राजदूतावास स्तर के राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। पूर्वी जर्मनी के साथ हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक तथा अन्य सम्बन्ध अत्यधिक मैत्रीपूर्ण हैं। पूर्वी जर्मनी ने बंगला देश को शीघ्र मान्यता प्रदान करके इसकी वास्तविकता को समझा है और इस संकट में भारत द्वारा निभायी गई भूमिका की सराहना की है। जर्मन जनवादी गणराज्य के प्रभुत्व को ऊंचा रखने में हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उसकी सहायता करते हैं। केमरीन में भारत के शिष्ट मंडल ने अन्तसंसदीय सम्मेलन में जर्मन जनवादी गणराज्य को शामिल करने का समर्थन किया जब कि पश्चिमी देश इसके विरुद्ध हैं। पश्चिमी देश चाहते हैं कि जर्मन जनवादी गणराज्य को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल करने का मामला तबतक स्थगित रखा जाए जब तक सोवियत रूस तथा पौलैंड और संघीय जर्मन गणराज्य के बीच हुई संधि का अनुसमर्थन उनकी सरकारें नहीं कर देती।

.. हमें एक राष्ट्र के नाते अपने आत्मसम्मान द्वारा पूर्वी जर्मनी जैसे समाजवादी मित्र देश के साथ तत्काल राजनयिक स्तर के सम्बन्ध स्थापित करके उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए।

संघीय जर्मन गणराज्य हमें यह कह कर ब्लैकमेल कर सकता है कि वह अपने द्वारा दी जाने वाली सहायता को बन्द कर देंगे। हम इस कथन का आशय भली-भांति समझते हैं । सभी समाजवादी देशों के सम्बन्ध हमारे प्रति अत्यधिक मैत्रीपूर्ण हैं विशेषकर जर्मन जनवादी गणराज्य तो हमें बहुत सहयोग देता है अतः सरकार को बिना विलम्ब किए जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ पूर्ण राजनियक सम्बन्ध स्थापित कर लेने चाहिए ।

कल से भारत तथा पाकिस्तान के बीच मुरी में अधिकारी स्तर पर वार्ता प्रारम्भ होने वाली है। मैं आशा करता हूँ यह वार्ता सफल होगी।

युद्ध बन्दियों के वापिस जाने के सम्बन्ध में बंगला देश की अनुमति अपेक्षित है । शान्ति वार्ता में भारत, पाकिस्तान और बंगला देश, तीनों को भाग लेना चाहिए, जिसमें सभी विवादग्रस्त विषयों को तय किया जाये ।

कश्मीर भारत का अंग है, यह पाकिस्तान के साथ बातचीत का विषय नहीं है, और यदि पाकिस्तान बुद्धिमत्ता से काम लेता है और पाश्चात्य देश बीच में टांग नहीं अड़ाते तो उसे भारत के साथ स्थायी सीमा निर्धारित करने के लिए राजी किया जा सकता है। यह एक कठिन कार्य है पर हम आशा करते हैं कि सरकार इस कार्य को अपने हितों को ठेस पहुंचाएं बिना सावधानी से सम्पन्न करेगी।

भारत को निक्सन की एशिया के देशों को लड़ाने की नीति का सामता करने के लिए बंगला देश के साथ लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद के आधार पर अपनी मित्रता और अधिक मजबुत करनी चाहिए तथा पाकिस्तान के साथ भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए और सभी पड़ौसी देशों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए ।

मुझे अपने हाल ही के विदेशी दौरे में पता चला, कि विदेश मंत्रालय चिलि जैसे देशों से, जहां क्रांतिकारी लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, सम्पर्क बनाए रखने में असफल रहा है । यदि प्रधान मंत्री क्यूबा और चिली और गियाना जैसे देशों का दौरा करें और जाम्बिया तथा तन्जानिया के साथ अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें तो यह एक लाभप्रद कार्य सिद्ध होगा ।

मंत्रालय का स्वविवेक व्यय बढ़ रहा है । 1970–71 में यह 6,86,68,000 रुपये था जो 1971–72 में बढ़कर 12 करोड़ हो गया जब कि 1972–73 के बजट में इस मद में 13,88,00,000 रुपये रखे गये हैं। नागरवाला जैसे मामलों को देखते हुए पता रहीं चलता कि इस मद में इतनी वृद्धि करने के क्या कारण हैं।

हम प्रतिवर्ष राष्ट्रमण्डल सचिवालय को 15 लाख रुपये अंशदान के रूप में देते हैं जब कि इससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 1,34,000 रुपये ऐटले स्मारक को किस लिए दिये जाते हैं ? भारतीय सांस्कृतिक मामलों की परिषद को दिए जानेवाले दान में इतनी वृद्धि क्यों की गई है जो 1971–72 की 14,50,00 रुपये से बढ़ कर इस वर्ष 29,25,000 रुपये हो गई है।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

सरकार को सी० आई० ए० की गतिविधियों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए । आजकल वह बंगला देश में अत्यधिक सक्रिय है। सरकार को दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देनी चाहिए और जर्मन जनवादी गणराज्य को पूर्ण मान्यता देनी चाहिए । हमें समय का लाभ उठाना चाहिए और भारतीय विदेश नीति तथा आर्थिक नीति को समर्थित ढंग से सम्मान पूर्वक कार्य करने के मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए ।

श्री० एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : इस मंत्रालय के विभाग तथा हमारे दूतावास सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं । हमारी विदेश सेवा में लगे लोग साम्राज्यवाद के पिट्ठू हैं । इन्होंने बंगलादेश के प्रति हमारी नीति का समर्थन नहीं किया तथा पाकिस्तान के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाई । उनके वेतनों में वृद्धि करना ठीक नहीं पर उन्हे कुछ आर्थिक सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे कि अन्य देशों जैसे अमरीका आदि में अपने साथियों के समान रह सकें ।

श्रीमावो शास्त्री समझौता दोषपुर्ण था । 7:4 का अनुपात स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था । श्रीलंका में वास्तव में रह रहे 10 लाख भारत मूलक लोगों में से लगभग 1½ लाख व्यक्ति छूट गये । इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए 15 वर्ष की अवधि निर्धारित करने का क्या कारण था । यदि भारत लोगों को नागरिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में गम्भीर था तो वह उन्हे तत्काल वापिस बुला लेना चाहिए था इससे श्रीलंका को हानि होती और उसे बाध्य होकर उन्हें वापिस आने के लिए कहना पड़ता । 7½ वर्ष गुजर गये हैं और अभी तक हम श्रीलंका से 46,000 लोगों को वापिस ला सके हैं और श्रीलंका ने 22,000 लोगों को नागरिकता प्रदान की है । इस कार्य को पूर्ण रूप से सम्पन्न करने के लिए सरकार ने क्या किया । जिन लोगों को भारत वापिस बुलाना है उन्हें हमें शीघ्र ही बुला लेना चाहिए ।

मुझे इस बात का खेद है कि कुछ पथभ्रष्ट क्रान्तिकारी छात्रों को दबाने के लिए सरकार ने श्रीलंका की शस्त्रों से सहायता की । एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र के लिए क्या यह एक अनुकूल कार्य था ?

हमने देखा है कि हाल ही में स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देश भारत के विरोधी हैं क्योंकि वहाँ हमारे कुछ देशवासियों ने काला धन्धा अपनाया तथा अशोभनीय कार्य करने आरम्भ कर दिए । यही सब उन्होंने बंगला देश में भी किया । अतः सरकार को इन लोगों की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए अन्यथा हमारे सम्बन्ध सभी पड़ोसी देशों से और बिगड़ जायेंगे ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : At present our foreign policy is based on the very principles for which we had waged the freedom struggle against the imperialists. India had always lent a helping hand to the revolutionaries fighting against the imperialist domination in any part of the world. Bangla Desh is a glaring example. The credit for the success of our foreign policy during Bangla Desh crisis goes to the hon. Minister and his co-workers in the Ministry.

It has been remarked that our foreign policy had been soft towards imperialists. The remark came from a C. P. M. member. But I would like to ask as to what had been their policy from the very beginning ? They have always joined hands with reactionary forces.

U. S. A. is perpetrating untold atrocities on the people of North Vietnam for compelling the Provisional Revolutionary Government in South Vietnam to bow down before them. But it is a futile attempt. It is high time that our government should recognise the Provisional Revolutionary government as was done in the case of Bangla Desh. It will boost their moral. Recognition to German Democratic Republic should also be accorded at the earlier possible time.

Our foreign policy has always been sympathetic towards Arab countries in their fight against imperialist powers, because it is in our interest to do so. We should support liberation front of Palestine.

I congratulate the Ministry for the Indo-U. S.S. R. Treaty. This is a very important Treaty and we are proud of it. It will further strengthen our friendly relations with U. S. S.R.

Is is a good sign that Pakistan is interested in having friendly relations with India and for that purpose the talks are going to be started at emissary level. But I will request the hon. Minister as that the question of Kashmir should be included in the talks.

Britain has entered the European Common Market because she is not at all worried about the interests of Commonwealth Countries. Britain's policy towards Catholics in Ireland is deplorable. They are fighting for their rights when Britain is to crush them. We should give our moral support to them.

We should further strengthen our friendly relations with Nepal. Afghanistan and Burma. Their languages should be included in the English Schedule because there are many people in India speaking these languages.

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : हमारी विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और यही कारण है कि जिस नीति को मैंने पहले संकोचपूर्ण, नकारात्मक और अनुत्पादक की संज्ञा दी थी अब मैं उसकी सफलता पर बधाई देता हूँ विशेषकर भारत पाक युद्ध के अवसर पर हुई उसकी सफलता पर।

अमरीका के राष्ट्रपति और चीनी नेताओं के बीच हुई वातचीत के बाद विश्व भर में यह धारणा व्याप्त हो गई थी कि अब वियतनाम में युद्ध नहीं होगा। परन्तु उसके तुरन्त बाद हम देख रहे हैं कि उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम तथा कम्बोदिया में क्या हो रहा है। उत्तर वियतनाम के लोगों की अभूतपूर्व भावना, अदम्य साहस, तथा अडिग मनोबल ने निक्सन तथा उसके प्रशासन की बर्बरता का पर्दाफाश कर दिया है।

प्रधान मंत्री ने बताया कि भारत और अमरीका की सरकारों में आपसी समझौता होने की पुरी सम्भावना है। पर इसमें मुझे सन्देह है क्योंकि अभी तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि निक्सन के हटे बिना यह समझौता नहीं हो सकता।

मैंने एक समाचार में पढ़ा कि भारत सरकार ने हाल ही में एशियाई और पूर्व एशियाई देशों मे स्थित अपने सभी राजदूतों को बुलाया था। वे यहां आए और यह तय किया गया कि इस भाग में एक तीसरा गुट बनाया जाये, जो कि इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

चीन जाते समय श्री निक्सन ने कहा था कि यह मेरी शान्ति यात्रा है पर श्री किसिंजर ने जबकि वे चाउ-एन लाई से वार्ता कर रहे थे, बताया कि वे अपने पुनः निर्वाचित होने के लिए यह यात्रा कर

[श्री के० मनोहरन्]

रहे हैं । यह एक राजनीतिक कार्य था । अमरीका के विचारशील लोगों को यह निश्चय करना है कि श्री निक्सन को विश्व के देशों के हितों को देखते हुए पराजित किया जाये ।

विदेश मंत्री शान्त तथा गम्भीर व्यक्ति हैं । उन्होंने प्रधान मंत्री के सहयोग के साथ विदेशी मामलों की समस्याओं का बड़ी योग्यता के साथ समाधान किया है । प्रधान मंत्री समय की पहचान के लिये प्रसिद्ध हैं । मैं समझता हूं कि जर्मन जनवादी गणराज्य और दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने का समय आ गया है । हमारे प्रधान मंत्री को अफ्रीकी तथा लैटिन अमरीकी देशों की यात्रा करनी चाहिये जो स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : तब हमारे देश के लिये कम समय बचेगा ।

श्री के० मनोहरन : दुर्भाग्यवश वह सारा उत्तर दायित्व श्री मिश्र को नहीं सौंप सकती अतएव वह बाहर नहीं जा सकतीं ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : मैं ने कुछ लैटिन अमरीकी देशों की यात्रा की है ।

श्री के० मनोहरन : फिर भी उन्हें उन देशों की यात्रा करनी चाहिए और हमारी विदेश नीति लचीली और दूरदर्शी होनी चाहिए ।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : राष्ट्रों के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब उन्हे ऐतिहासिक महत्व के निर्णय लेने पड़ते है । मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री संकट के समय खरी उतरी हैं ।

विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत अलग-थलग नहीं रह सकता और न ही विश्व के देश भारत की उपेक्षा कर सकते हैं । इससे हमें अनेक लाभ भी हैं और कई उत्तर दायित्व भी हमारे ऊपर आन पड़ते हैं । हमें एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देशों के आर्थिक-औद्योगिक विकास में प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए जिससे कि वे देश शक्ति शाली बन सके और बाह्य शक्तियों के दबाव में न आएं ।

इसी विचार से हमने अपने राजदूतों का सम्मेलन बुलाया था ताकि हम जान सके कि वे देश हमसे क्या आशाएं रखते हैं । यह खेद की बात है कि जब यूरोप के देश दो युद्धों के परिणामों से शिक्षा लेकर परस्पर निकट आ रहे हैं परन्तु हम एशियावासियों ने परस्पर कई लड़ाईयां लड़ी हैं । हमे इस स्थिति को बदलना है ।

उन देशों के साथ आर्थिक सहयोग के अलावा हम एशिया और सुदुर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के साथ सहयोग कर रहे हैं और हमारा मंत्रालय अफ्रीकी एशियाई देशों की सहायता के लिये अंतरराष्ट्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम चला रहा है, जिसके अंतर्गत हम तकनीकी जानकारी देते हैं तथा परामर्श दाता सेवाएं प्रदान करते हैं । इस कार्य पर 1968-69 में 27.56 लाख रुपये व्यय किये गये और यह व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में 105 लाख रुपये हो गया है ।

हम अपनी विदेश नीति के आर्थिक महत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। इस मंत्रालय के आर्थिक डिवीजन में एक अन्य संयुक्त सचिव और अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति कर के इसे अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। सभी स्तर के विदेश सेवा अधिकारियों को आर्थिक कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। राजदूतों को भी कहा गया है कि वे अपनी नियुक्ति के देशों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये महत्वपूर्ण योजनाएं विचारार्थ भेजें।

अपने पड़ोसी देशों के साथ हम मैत्री स्थापित करने, एक दुसरे को समझने और सहयोग करने की नीति पर चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि चीन और पाकिस्तान को छोड़ कर अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण हैं।

कुछ समय पूर्व नेपाल के साथ हमारे व्यापार संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। अन्ततः हमारे सम्बन्ध उनके साथ सुधर गये हैं।

नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा एवं उनकी हमारे प्रधान मंत्री से बातचीत अत्यन्त उपयोगी रही। हम उस देश को पर्याप्त सहायता देते हैं। पिछले 20 वर्षों में हमने उसे 81 करोड़ रुपए की सहायता दी है। हमारा वहां की 1.0 परियोजनाओं से संबंध रहा है। उस देश के साथ हमारी सीमाएं खुली हैं।

सिक्किम के साथ भी हमारे निकट के संबंध हैं। तीन योजनाओं में हमने उसे 20 करोड़ रुपए की सहायता दी है और चौथी योजना में 18.5 करोड़ रुपये रखे गये हैं। वहां पर सड़कों और पुलों के निर्माण का पूरा व्यय हम स्वयं करते हैं।

भूटान के साथ हमारे अत्यन्त निकट के संबंध हैं। भूटान अब राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया है जिसका हमने स्वागत किया है।

भारत और भूटान के आपसी सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। हाल ही में जब भारत के एक प्रतिनिधि ने भूटान की यात्रा की तो उस समय भूटान नरेश ने स्वयं यह बात कही कि भूटान के अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रवेश करने से भारत के साथ भूटान की मैत्री और भी सुदृढ़ हो गई है। भूटान के नरेश के नेतृत्व में वह देश निरन्तर प्रगति की और अग्रसर हो रहा है। उस देश की विकासशील योजनाओं के लिए भारत चालू वर्ष में 33 करोड रुपये की वित्तीय सहायता दे रहा है।

बर्मा एक अन्य ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। दोनों देश एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करते हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए जो भारत-बर्मा सीमा करार हुआ है, उससे दोनो देशों के आपसी सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हो गये हैं और सीमा निर्धारण का कार्य बहुत संतोषजनक ढंग से हो रहा है। भारत के मूल निवासी जो अपनी सम्पत्ति बर्मा में छोड़ आये थे, उनके मामले के बारे में भी दोनों सरकारों के बीच बहुत मित्रतापूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है।

श्रीलंका के साथ भारत के सम्बन्ध काफी मैत्रीपूर्ण है और हाल ही में श्रीलंका के विदेश और आन्तरिक व्यापार मंत्री द्वारा की गई भारत की यात्रा से यह सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हो गये हैं। कुछ समय पूर्व श्रीलंका में कुछ भारत विरोधी तत्वों द्वारा भारत और श्रीलंका के सम्बन्धों को बिगाड़ने

[श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

के लिए प्रचार आरम्भ किया गया था। प्रचार में भारत पर विस्तारवादी होने का आरोप भी लगाया गया था। परन्तु यह खुशी की बात है कि अब श्रीलंका के लोग यह समझ चुके हैं कि भारत विस्तारवादी देश नहीं है। अब आर्थिक, तकनीकी तथा अन्य अनेक विषयों में भारत और श्रीलंका का आपसी सहयोग चल रहा है। हम श्रीलंका को आर्थिक तथा औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों से सशक्त बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार यदि भारत भी आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से सशक्त हो जाता है तो इससे दोनों ही देशों की शक्ति में वृद्धि होगी। श्रीलंका को हमारे इरादों के बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिये। हम सभी पड़ौसी देशों के साथ मित्रता के इच्छुक हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो फिर आपने अपनी सेनायें वहां क्यों भेजी थीं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : वैसे इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर मेरे वरिष्ठ साथी द्वारा दिया जा चुका है। वहां लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार की सहायता करना हमारा कर्त्तव्य था।

श्री श्रीकांतन नायर ने भारत श्रीलंका करार, 1964 का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसे शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मामले के निपटारे में कुछ विलम्ब हुआ है, परन्तु इस का प्रमुख कारण यह है कि यह मामला बहुत जटिल था। इस मामले से सम्बद्ध और भी बहुत सी समस्यायें थीं। मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि इस मामले से सम्बद्ध आरम्भिक कठिनाईयों पर काबू पा लिया गया है और यह सम्पूर्ण योजना 15 वर्ष के निर्धारित समय में ही पूरी कर ली जायेगी।

हिन्द महासागर में गत कुछ वर्षों से विदेशी नौसैनिक जहाजों तथा अन्य जंगी जहाजों की संख्या में जो वृद्धि हुई, उसके बारे में निश्चय ही हम भी चिंतित हैं। बड़ी शक्तियों की शत्रुता निश्चय ही इस क्षेत्र के छोटे देशों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हमने यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में भी उठाया है। सितम्बर 1970 में लुसाका में हुए तटस्थ देशों के सम्मेलन के बाद यह घोषणा की गई थी कि हिन्द महासागर को आणुविक प्रभाव से मुक्त और शांतिपूर्ण क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसी आशय का एक संकल्प श्रीलंका द्वारा पेश किया गया था, जिसका भारत ने समर्थन किया था। यह संतोष की बात है कि इस मामले के बारे में हम ने विश्व में काफी जनमत तैयार कर लिया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बड़ी शक्तियों का एक सम्मेलन होने वाला है, हमें आशा है कि हिन्द महासागर से सम्बद्ध सभी बड़े-छोटे देश भी इसमें भाग लेंगे और इस समस्या के बारे में कोई भी निर्णय हमारे विचारों को दृष्टिगत रखते हुये ही किया जायेगा।

अब मैं एक दो बातें सांस्कृतिक सम्बन्धों के बारे में भी कहना चाहता हूं। विश्व के अन्य देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के साथ-साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिये हमने विश्व के अधिकांश देशों विशेषतया उन देशों के साथ जहां कि भारत मूल के निवासी अधिक हैं, सांस्कृतिक करार किये हुये हैं, इस प्रकार ऐसे सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए हम हर सम्भव सहयोग देते रहते हैं। मैं इन्ही मुख्य बातों पर प्रकाश डालना चाहता था।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : आज हमारा देश पहले से कहीं अधिक सशक्त है। बंगाल देश का उदय निश्चय ही एक ऐसी घटना है जिसके लिए मंत्री महोदय और भारत सरकार बधाई

के पात्र हैं। भारत सरकार ने बंगला देश की समस्या का राजनीतिक समाधान खोजने की बात बार-बार कही।

[श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

परन्तु राजनीतिक समाधान क्या होना चाहिये, इसके बारे में हमारी सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा। यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई थी कि भारत की विदेश नीति बंगलादेश को स्वतंत्रता दिलाने की है। बंगलादेश के उदय से यदि यह भ्रम पैदा हो गया है कि भारत एक बड़ी शक्ति है, तो हम पूर्णतया गलत है। आज भी हिंद महासागर में अमरीका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के समुद्री बेड़े मौजूद हैं, परन्तु भारत सरकार उसमें कुछ कर सकने में पूर्णतया असमर्थ है। इन सब बातों का निष्कर्ष केवल यही है कि जब तक हमारी सुरक्षा का आधार शक्ति नहीं होगा, तब तक हमारी विदेश नीति प्रभावशाली नहीं बन सकती। हम अपनी विदेश नीति के अन्तर्गत, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एशियाई सुरक्षा व्यवस्था करना चाहते हैं। स्वर्गीय श्री नेहरू के दिनों में भी ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया था। परन्तु इसके लिए हमें सम्बद्ध देशों का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। वैसे भी इस व्यवस्था के लिए विश्व की बड़ी ताकतों को निमन्त्रण देने के तात्पर्य एशिया में ही उनकी आपसी शत्रुता को निमंत्रण देना होगा। इस व्यवस्था से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की प्रभुसत्ता और अखंडता की सुरक्षा भी किसी प्रकार नहीं की जा सकेगी। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़ी शक्तियों को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की एशिया सुरक्षा व्यवस्था में निमन्त्रित करने की आवश्यकता ही क्या है? वास्तविकता यह है कि यह योजना तीन वर्ष पूर्व श्री ब्रेजनेव द्वारा बनाई गई थी परन्तु यह उस समय स्वीकृत नही हो पाई थी। अब हमारे विदेश मंत्री सोवियत संघ के लिए फिर इसे आरम्भ करना चाहते हैं। मैं चीन की शासन व्यवस्था की सराहना तो नहीं करता परन्तु हां मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जब तक एशियाई सुरक्षा व्यवस्था में चीन शामिल नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था सफल नहीं हो सकती।

इसी सम्बन्ध में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री नेहरू के दिनों में विश्व के मामलों में भारत की विदेश नीति सक्रिय थी। परन्तु अब हमारी विदेश नीति में सक्रियता का पूर्ण अभाव है। वियतनाम में आज जो कुछ हो रहा है उसके बारे में विदेश मंत्री ने बताया हैं कि न वह शिखर-सम्मेलन बुलाना चाहते हैं और न ही वह अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण अयोग के सम्मेलन के पक्ष में हैं। यदि हम किसी किसी के मामलों में हस्ताक्षेप नहीं करना चाहते तो एशियाई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हम किसी देश का सहयोग प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकते हैं? एशियाई देशों के अनुभव से अब तक हमने क्या सीखा है? अपने कार्य की सूची बनाना तो एक ओर रहा, अभी तक ये देश अपने लिए एक स्थाई सचिवालय भी नहीं बना सके हैं। अतः पूर्व अनुभवों के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि एशियाई सुरक्षा व्यवस्था सफल होने वाली नहीं है और न ही उसमें बड़ी शक्तियों यथा सोवियत संघ, अमरीका या चीन को आमंत्रित करने से दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों की प्रभुसत्ता और अखंडता ही सुनिश्चित की जा सकती है।

अन्त में मैं विदेश मंत्री को बधाई देते हुए यह बात फिर दोहराना चाहता हूं कि उन्हें सराहनीय विदेश नीति अपनानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का सर्थन करता हूं।

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : विदेश नीति दो सूत्रीय व्यवस्था होती है जिसका एक सूत्र तो अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों से सम्बद्ध होता है और दूसरा राष्ट्रीय हितों से। पं. नेहरू की विदेश नीति में एशिया के लोगों की आकांक्षाएं नीहित होती थीं जिसे बाद में तटस्थता, पंचशील तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आदि कहा गया। आज इन सिद्धान्तों को वे लोग भी स्वीकार कर रहे हैं जिन्होंने पहले इसका विरोध किया था।

बंगला देश के मामले में हम उस एशियाई नीति का निर्वारण न कर सके जिसे निर्धारित करने के लिये पं. नेहरू प्रयत्नशील रहते थें। वियतनाम के मामले में भी हम वह न कर सके जिसकी हम से आशा की जाती थी। वियतनाम, जर्मन जनवादी गणराज्य : दक्षिण अफ्रीका के लोगों का संघर्ष, पुर्तगाल का उपनिवेशी राज्य आदि ऐसे प्रश्न हैं जिन पर एक-एक करके निर्णय नहीं लिया जा सकता।

या तो हम शोषितों का समर्थन करें या पीछे हट जायें। कोरी सहानुभूति दिखाने से काम नहीं चलेगा। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के देशों को एक साथ मिलाने के लिये, जो अब बडी शक्तियों की प्रतिद्वन्दती की नई चुनोतियों का सामना कर रहे हैं, एक गतिशील पहल करनी चाहिये।

एशिया में जो हमारे मिशन हैं, उनके अध्यक्षों के साथ हमारी कई बैठकें हुई हैं। उपमंत्री ने इसे चर्चा और इसके कुछ निष्कर्षों के बारे में संकेत दिया है कि आर्थिक मामलों पर किस प्रकार से बल दिया जा सकता है। लेकिन क्या इस से कार्य सिद्ध हो जाता है ? क्या हम यह कहेंगे कि क्योंकि हमारे राजदूतों को विक्रेता बनने के लिये कहा गया है, इसलिये एशिया में हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है।

इस नीति को केवल व्यापार द्वारा नहीं चलाया जायेगा। यह एक देश के विकास कार्य को दूसरे देश के विकास कार्य के साथ समन्वय करने का प्रश्न है जो केवल सहकारी और आर्थिक सहयोग से हो सकता है। किंतु यह भी पर्याप्त नहीं। भारत पददलित लोगों का, चाहे वे कहीं के भी हो, समर्थन करता रहा है।

वियतनाम का संघर्ष एशियाई जनता का विदेशी अधिपत्य के विरूद्ध संघर्ष करने का संकेत देता है। खेद की बात है कि हमने वह कार्यवाही नहीं की है जिसकी हमसे आशा की जाती थी। हमें इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की विशेष भूमिका निभानी चाहिये थी। वियतनाम में बदल रही स्थिति के अनुसार कार्य करना ही आयोग का कर्तव्य है। जनेवा सम्मेलन में हम पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है।

हमारी एक सर्वोत्तम विदेश सेवा के युवा सदस्य सर्वोत्तम व्यक्ति है जो विश्व भर में कहीं भी नहीं मिल सकते। फिर भी इसमें नौकरशाही का बोल बाला है, जिससे उनकी सभी आशायें और आकांक्षायें निरूत्साहित हुई हैं।

हम जानना चाहते हैं कि क्या विदेश मंत्री ने एशियाई देशों में हमारे राजदूतों को कोई मार्गदर्शन दिया है। जिससे कि वे उन देशों में, जिनमें वे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, नई गतिशी-

लता लाने का प्रयास करे ? हम आशा करते हैं कि इससे एशिया में एकता की भावना पैदा होगी। ऐसा करने पर हम इस दिशा में निस्सन्देह आगे बढ़ेंगे।

अरब क्षेत्र का संघर्ष इज्रायल तथा अरब देशों के बीच संघर्ष नहीं है। यह संघर्ष नव उपनिवेशवाद के विरूद्ध है। अरब राष्ट्र अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उसे जारी रखने के लिए हमें उनका समर्थन करना जाहिये। एशिया में आज शक्ति संतुलन है। यह एक ऐसा संतुलन है जिसमें चीन ने अपने आपको डाल दिया है। हमें वह देखना है कि इससे हमारे राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक प्रमुख शक्ति आज हमारे साथ है और दो प्रमुख शक्तियां हमारे विरूद्ध हैं। राजनीति की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि हम किस सीमा तक उस शक्ति के साथ, जो हमारे साथ है, मित्रता बढ़ाते हैं और इसके साथ-साथ हमारे विरूद्ध जो शक्तियां काम कर रहीं हैं, उन्हें निष्प्रभाव करते हैं।

चाहे चीन हो या अमरीका हमें अपने सम्बन्धों में लचीलापन लाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि इस चर्चा द्वारा वह गतिशील दृष्टीकोण बनाना सम्भव होगा जिससे हमारी नीतियों को शक्ति मिलेगी और उसे नई दिशा मिलेगी।

श्री आर० के० सिंह (फैजाबाद) : हमारी विदेश नीति शांति और तटस्थता पर आधारित रही है।

हमने गोआ और अन्य भागों को फ्रांस के उपनिवेशवाद से युक्त किया, गत वर्ष विरोधी दल के नेता बंगलादेश को मान्यता देने की दलीलें देते रहे और कहते रहे कि सरकार की नीति असफल रही है।

बंगलादेश की मुक्ति से हमने क्या सीखा है ? विरोधी दल सम्भवतः यह भूल जाते हैं कि बंगला देश के उदय से भारत का नाम विश्व में उंचा हुआ है। सत्तारूढ़ दल अपनी उपलब्धियों पर गर्व क्यों न करे बंगलादेश की मुक्ति आखिर हमारी विदेश नीति का ही परिणाम है।

अरब और हिन्दचीन की मुक्ति के लिये वर्षो से संघर्ष चल रहा है। लेकिन भारत के लोगों ने बंगलादेश के लोगों का साथ देकर किस प्रकार बंगलादेश की मुक्ति करायी, इससे विश्वव्यापी साम्राज्यवाद की श्रंखला विकराल में हुई है। साम्राज्यवाद अभी मरा नहीं। अफ्रीका और पुर्तगाल के उपनिवेशों में अभी साम्राज्यवाद विद्यमान है।

विश्व के साम्राज्यवादी देशों ने पश्चिमी एशिया के लोगों को पूरी तरह आपस में विभाजित कर रखा है। इजराइल की मार्फत अरब लोगों का एक भाग उसने हड़प लिया है।

इन्डो-चीन में अमरीका क्या कर रहा है ? वहां उसने अत्याचार के सभी ढंग अपनाए हैं जो जो हिटलर अथवा याह्या खां ने भी नहीं अपनाए थे। पर वियतनाम के लोग इस चुनौती का दृढ़ता से सामना कर रहे हैं। आज कल हमारी विदेश नीति ने अपने पैर जमा लिए हैं और अब भारत को कोई धमकी नहीं दे सकता। उसकी अपनी शक्ति है। यदि विरोधी दल उसकी आलोचना करते हैं, तो वह मिथ्या है।

[श्री आर० के० सिंह]

भारत और रूस की संधि को अवसरवादिता की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, यह संधि 25 साल के प्रयासों का फल है । अमरीकी राष्ट्रपति का चीन जाना एक अवसरवादिता है । वहाँ वियतनाम अथवा ताइवान की समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया । जबकि कश्मीर समस्या, रक्षा उद्योगों आदि के सम्बन्ध में रूस ने सदैव हमारा साथ दिया है ।

हमें दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के विशेष अध्ययन पर बल देना चाहिए । इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों की स्थापना करने में सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए । ये वे क्षेत्र हैं जहाँ हमारे पूर्वजों ने बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म का प्रचार किया था ।

पश्चिम एशिया के संबंध में हमें विश्व में अपनाई जा रही आक्रामक नीति के जाल में नहीं फंसना चाहिए । हो सकता है कि भूतकाल में इस क्षेत्र से हमारी नीति को समर्थन न मिला हो, पर हमें उसे अमरीकी साम्राज्यवाद तथा सी. आई. ए. से उसे बचाने के लिए हर स्तर पर–सरकारी और गैर सरकारी मैत्री बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

हमें अफ्रीकी देशों से सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, फिर चाहे वे छोटे देश ही क्यों न हो, जिससे कि वे यह न समझे कि भारत उनकी उपेक्षा कर रहा है । हमें वहाँ गैर सरकारी स्तर पर प्रतिनिधि शिष्ट मण्डल भेजने चाहिएं और उनके शिष्ट मण्डल अपने यहाँ आमन्त्रित करने चाहिए ।

चीन के हमारे प्रति विरोधी रवैया अपनाने पर भी हमें उसके साथ कुछ सीमा तक सद्भावना और मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए । हमें पाकिस्तान को साम्राज्यवादियों और चीन के चंगुल से बचाना चाहिए, जोकि उप-महाद्विप में तनाव पूर्ण स्थिति पैदा करना चाहते हैं । यदि सम्भव हो, तो हमें पाकिस्तान के साथ स्थायी शान्ति स्थापित करनी चाहिए । मैं आशा करता हूँ कि भारत, पाकिस्तान और बंगला देश हमारे स्वप्नदृष्टाओं के महान आदर्शों की रक्षा करेंगे ।

श्री सी० सी० देसाई (सबरकंठा) : इस समय देश भर की दृष्टि निकट भविष्य में होनेवाली भारत-पाक वार्ता पर केन्द्रित है । इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य इस उप-महाद्वीप में स्थायी शान्ति स्थापित करना है । श्री भुट्टो को शान्ति स्थापना की बात कहने मात्र से शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती । हमें इसके लिए भारत पर पाकिस्तान की आक्रमण करने की क्षमता को ध्यान में रखना होगा । यदि हम इस समझौते के द्वारा शस्त्रास्त्रों पर सीमा लगा कर पाकिस्तान की आक्रमण-क्षमता के सम्बन्ध में कुछ कर सकें, तभी स्थायी शान्ति स्थापित हो सकती है । यदि पाकिस्तान वास्तव में शान्ति का इच्छुक है तो उसे शस्त्रास्त्रों और सेना सम्बन्धी सीमा को मान लेना चाहिए और तभी उसकी इच्छा की वास्तविकता का पता चलेगा, अन्यथा हम समझेंगे कि वह केवल युद्ध बन्दियों को छुड़ाने के लिए यह वार्ता कर रहा है । उनके अनुसार उनकी दो समस्याएं हैं । एक तो युद्ध वन्दियों की रिहाई और दूसरी कश्मीर समस्या का स्थायी हल । वे भारतीय युद्ध वन्दियों को बिना भारतीय प्रधान मंत्री की सहमति के भी छोड़ने को तैयार हैं । पर इससे समस्या का समाधान नहीं होता ।

बंगला देश के संघर्ष के दौरान अनेकों अरब देशों का रवैया भारत के प्रति बड़ा ही शर्मनाक रहा है । अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में अपने हितों और पख्तूनों के साथ सहानुभूति रखते हुए अभी तक बंगला देश को मान्यता नहीं दी है । मिश्र, जो कि हमारा बड़ा मित्र है, का कहना है कि जब

श्री भुट्टो कहेंगे, तब हम बंगला देश को मान्यता देंगे। भारत पाक युद्ध के दौरान लीबिया ने भारत पर अनेकों आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान की शस्त्रास्त्रों द्वारा मदद भी की तब कौनसा कारण है कि हम इन देशों के प्रति सहानुभूति रखें। दूसरी ओर इजराइल ने हमारे प्रति मित्रता पूर्ण रूख रखा है। भारत-पाक युद्ध के दौरान बहुत आधुनिकतम शस्त्र इजराइल ने ही भारत को दिये जबकि मिश्र, अफगानिस्तान, इरान, तुर्की आदि बड़े मुस्लिम देशों ने बंगला देश को मान्यता नहीं दी है, छोटे से देश इजराइल ने उसे सबसे पहले मान्यता दी। हम उसे एक वाणिज्यिक दूतावास दिल्ली में खोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनके साथ वैसा व्यवहार हो जैसा कि हम अपने मित्रों के साथ कर रहे हैं।

अफ्रीकी देशों का उल्लेख किया गया। वहां के भारतीयों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। अपनी बहुनिन्दित रंगभेद नीति के बावजूद दक्षिण अफ्रीका में भारतीय केनिया, युगोंडा, और तन्जानिया से कहीं अधिक प्रसन्न हैं। हम दक्षिण अफ्रीका स्थित भारत मूलक लोगों के प्रति सांस्कृतिक पार्थक्य का रूख अपनाते रहे हैं। उनके लड़कों को पर्याप्त संख्या में मेडिकल कालेजों में प्रवेश नहीं देते। हमें तमिल नाडु और बिहार मूलक इन 7,00,000 लोगों के प्रति पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, जिसके कि वे अधिकारी हैं।

1971 के चुनावों के पश्चात् बंगला देश के शरणार्थियों को भारत आने की अनुमति देना, बंगला देश के मुक्ति आन्दोलन को समर्थन देना, भारत पर आक्रमण करने के पश्चात पाकिस्तान के विरूद्ध भारत को मिली विजय के बाद एक तरफा युद्ध विराम का निर्णय करना जैसे निर्णय लेना सही कदम थे। एकतरफा युद्ध विराम के निर्णय का श्रेय भारत के प्रधान मंत्री और उसकी जनता को दिया जाना चाहिए अन्य किसी देश अथवा व्यक्ति को नहीं।

यह प्रसन्नता की बात है कि पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की पेशकश की है। आशा है कि भारत की ओर से इस सम्बन्ध में उचित प्रतिक्रिया होगी। हम पाकिस्तानी जनता के विरूद्ध नहीं हैं। वे भी भारतीय जनता से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते हैं। पर वे अपनी सरकार की नीतियों का शिकार रहे हैं। दोनों देशों के बीच वीसा सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिए, जिससे कि लोग स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ आ जा सकें।

शक्ति स्थापना के बाद दोनों देशों को सुरक्षा परिषद में अपने-अपने मामले वापस ले लेने चाहिएं जिससे कि मौजुदा कटुता समाप्त हो जाये।

समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित पाकिस्तान अमरीकी पारस्परिक सुरक्षा सन्धि के सम्बन्ध में जनता को कुछ नहीं बताया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी जानकारी सरकार भारतीय जनता को देने में आना कानी क्यों कर रही है।

राष्ट्रमण्डल सचिवालय, ब्रिटिश विदेश सेवा के कुछ अवकाश प्राप्त अथवा हाल में अवकाश प्राप्त अधिकारियों के शरणस्थल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि उस कार्यालय के लिए धन देने में कौनसा तर्क है जो केवल ब्रिटिश सरकार के हितों के लिए बनी है। जब हम उसमें अपना योगदान देते हैं तब वहाँ होने वाली नियुक्तियों में भी हमारा हाथ होना चाहिए तथा उसमें हमारा भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद): 1971 का वर्ष हमारे देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए एक उखाड़-पछाड़ और आतंक का वर्ष रहा है । पर हमारी सरकार, संसद और जनता ने इस चुनौती का सामना किया और उसमें हम विजयी ही नहीं रहे, बल्कि हमें लाभ भी हुआ । हमारे प्रधान मंत्री का नेतृत्व इस सब में अद्वितीय रहा । विदेश मंत्रालय ने बहुत ही कठिन और नाजुक समस्याओं को बड़ी ही चतुराई और सावधानी से हल किया है ।

इस अवधि में एशिया के राजनीतिक क्षेत्र में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं । भारत इस सब में सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर कर सामने आया है और मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्णय प्रमुख रूप से एशिया में होगा । तथा भारत का इसमें महत्वपूर्ण योग होगा । भारत की विदेश नीति का आधार शान्ति रहा है । इस सम्बन्ध में संसार का कोई अन्य देश उसकी बराबरी नहीं कर सकता । गुट निरपेक्षता, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, स्वतंत्रता और आर्थिक प्रगति तथा अन्योन्याश्रय इस नीति के प्रमुख उपकरण रहे हैं ।

दक्षिण-पूर्व एशिया के सम्बन्ध में हमारी यह घोषित नीति रही है कि यह क्षेत्र विदेशी प्रभुत्व और प्रभाव से बचा रहे । 1968 की अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने कहा था कि बड़ी शक्तियों को संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र के अन्तर्गत इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा तथा तटस्थता की गारन्टी देनी चाहिए । उनके मतानुसार इस क्षेत्र के देशों को आवश्यक रूप में एशिया की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि बड़े देश इनकी तटस्थता का आश्वासन देते हैं ।

भारत पश्चिम की इस विचारधारा से पूर्णतया सहमत नहीं है कि ब्रेजनेव ने सामूहिक सुरक्षा की जो धारणा बनाई है उससे एक नया शक्ति गुट बनेगा जिसमें रूस की अधिक शक्ति होगी । भारत ने 'एशिया से दूर रहो' की धारणा की जो निरन्तर वकालत की है, वह नये शक्ति गठजोड़ का पूरा समर्थन नहीं कर सकता जिसे अमरीका ने एशिया में रखा है अतः इस क्षेत्र में शांति बनाये रखने हेतु आन्तरिक स्थिरता एवं सुरक्षा के कुछ उपाय करना आवश्यक है । भारत का विश्वास है कि गहन आर्थिक सहयोग से ही स्थिरता सम्भव है । हम चाहते हैं कि हमारे पड़ौसी देश सुदृढ़ और स्थिर हों जिससे वे बाह्य दबाव का सामना कर सकें ।

चीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत से काफी बाद में आया है फिर भी यह देश बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ा है, क्योंकि यह चयन के आधार पर आगे बढ़ा है । और कुछ इने गिने देशों को सहायता दी है । हमने भी अनेक देशों को सहायता दी है । अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों, अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों, शान्ति और क्षेत्रीय स्थिरता बनाने हेतु भारत सहायता देने में पीछे रहा है । अंकटाड के सदस्य के रूप में भारत ने आर्थिक सहायता में अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से एक प्रतिशत देने का वचन दिया है । यदि हम उन देशों के साथ सम्बन्ध बनायें, जिनके साथ इस क्षेत्र में निकट सम्बन्ध बढ़ाने से हमारा राष्ट्रीय हित होगा तो हम इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता बनाये रखने के लिए आर्थिक अन्योन्याश्रय और सहायता के इस आधार का उपयोग कर सकते हैं ।

यह सही है कि हमने नेपाल और श्रीलंका के साथ सम्पर्क बढ़ाना आरम्भ किया है और हमने इन देशों के साथ व्यापार सन्धि की है । हमने श्रीलंका को जान बूझकर भारत में अधिक निर्यात करने की अनुमति दी है जिससे यह देश अपने व्यापार सन्तुलन में आई अस्थिरता को कम कर सके ।

इसी प्रकार यदि हम पूर्वी अफ्रीका, फारस की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भी इसी प्रकार की उदार नीतियां अपनायें तो हम निश्चित ही आर्थिक अन्योन्याश्रय के माध्यम से इस क्षेत्र में अपने स्थिरता के सिद्धान्त को बढ़ावा दे सकते हैं । इस परिवर्तित परिस्थिति में हम पुरानी मान्यताओं पर नहीं रह सकते । इस उपमहाद्वीप में इतने बड़े परिवर्तन हुए हैं कि सारी स्थिति ही परिवर्तित हो गई है । बंगला देश के साथ शान्ति, मैत्री तथा सहयोग की सन्धि करने से बंगला देश के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत सुदृढ़ हो गये हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की पुरानी नीति, जिसे पाकिस्तान के कुछ नेताओं और विश्व की कुछ शक्तियों ने पुष्ट किया था, अब समाप्त हो गई है । जितने शीघ्र पाकिस्तान के नेता यह अनुभव करने लगेंगे कि भारत के साथ टकराना ठीक नहीं है उनके लिए यह उतना ही उचित सिद्ध होगा । हमारे नेता पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं और विश्व के इस भाग में भारत पाकिस्तान तथा बंगला देश के क्षेत्रीय सहयोग का युग लाना है, जैसी कि यूरोपीय समुदाय ने इस सम्बन्ध में सफलता प्राप्त की है । इस दिशा में प्रयास करने हेतु चिरकालीन शान्ति के लिए हमें कुछ छूट देने से हिचकना नहीं चाहिए ।

जापान नये परिवर्तनों से तीव्रता से प्रभावित हुआ है । यह हमारे हित में होगा कि हम इस देश के साथ घनिष्ठ आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करें क्योंकि यह विश्व के औद्योगिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकसित देशों में से एक देश है।

वृहत् योरूप तथा भारत के बीच कई ऐसे स्थान है जहां दोनों पक्षों का हित निहित है । बंगला देश के प्रति योरोपीय देशों, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का रवैया अमरीका के रवैये की तुलना में कुछ अच्छा था । इन देशों ने वह स्थिति की वास्तविकता को समझा है और उन्होंने घनिष्टता दिखाई है तथा हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि पूर्वी योरोपीय देशों के साथ अधिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना हमारे लिए अधिक लाभप्रद होगा ।

जहां तक रूस, अमरीका और चीन, इन तीन बड़ी शक्तियों का सम्बन्ध है, रूस के साथ दशकों से हमारे सम्बन्धो में निरन्तर विकास हुआ है और शान्ति मैत्री तथा सहयोग की संन्धि होने से तो यह मित्रता चरम सीमा पर पहुँच गई है । आज विश्व के लिए इन दोनों देशों के मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध आदर्श हैं जो पारस्परिक हितो, समान दर्जे पर आधारित हैं न कि एक दूसरे के शोषण पर । इस उप महाद्वीप विशेषकर भारत के प्रति अमरीका का जो रहा है । उसकी तुलना में रूस का रवैया बिल्कुल विपरीत है । इसका कारण है कि अमरीका की नीति वास्तविकताओं से दूर है और यह अपने दोषों को अनुभव नहीं करता कि इसे एक के पश्चात् दूसरी पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है । हमें आशा है कि अमरीका अपनी नीति में परिवर्तन लायेगा ।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, यह हमारा सबसे बड़ा पड़ौसी देश है । अच्छा होता यदि चीन की तर्कपूर्ण बात यह होती कि वह भारत-चीन विवाद को हल करने का प्रयास करता और भारत के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाता । पहले इस सम्बन्ध में कुछ संकेत मिले थे । हमें आशा थी कि राजदूतों की नियुक्ति से सम्बन्धों में सुधार होगा । परन्तु खेद की बात है कि ऐसा हुआ नहीं । फिर भी हमें आशा है कि चीन भविष्य में सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए भारत के प्रयासों के समझने का प्रयास

[श्री बी० आर० भगत]

करेगा और यदि उसने हमारी बातों को स्वीकार किया, तो हम अवश्य उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ायेंगे ।

हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबन्ध चाहते हैं जिनमें कई देश शामिल हों । आज विश्व की विशेष रूप से भारत पर नजर है । अतः हमें इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : बंगला देश के उदय से सम्पूर्ण भारतीय उप महाद्वीप में एक नये इतिहास का जन्म हुआ है ।

बंगला देश के मुक्ति योद्धाओं एवं भारत के मुक्ति योद्धाओं ने मुक्ति संघर्ष में भाग लिया । अतएव पाकिस्तान के साथ शान्ति की संधि करना दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व है । पाकिस्तान के साथ वार्ता त्रिदलीय वार्ता होनी चाहिए । श्री धर के साथ बंगला देश के विदेश सचिव को भी जाना चाहिए था । शिखर वार्ता तीनों देशों की होनी चाहिए । किसी भी सम्भावित शान्ति सन्धि पर तीनों देशों के शासनाध्यक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

बंगला देश की जनता के 25 वर्ष तक किए गये शोषण एवं युद्ध अपराधियों के मामले में बंगला देश के दृष्टिकोण को भुलना नहीं चाहिए ।

श्री भुट्टो इस समय बड़ी मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं परन्तु युद्ध बंदियों की वापसी के साथ ही उनकी भारत संबन्धी समूची नीति बदल जायेगी । यदि इस उपमहाद्वीप की समस्याओं का समाधान करना है तो हमें स्थायित्व, शान्ति और सुरक्षा पर ध्यान देना होगा ।

भारत-बंगला देश संबन्ध सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार पर होने चाहिए । दोनों देशों में यात्रा संबन्धी सुविधाएँ निर्बाध होनी चाहिए ।

बंगला देश के संबन्ध में शत्रु सम्पत्ति अधिनियम को लागू करने में सतकर्ता बरती जानी चाहिए ।

बंगला देश के मामले में श्री डी० पी० धर ने काफी भूमिका निभाई है । मैं समझता हूँ कि उन्होंने बंगलादेश की भाषा संस्कृति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाने बिना जो कार्य किया है उससे अधिक समस्याएँ पैदा हो गई है । मैं जानना चाहता हूं कि उनका दर्जा क्या है । क्या उनका दर्जा मंत्री पद से भी ऊपर का है । वह किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह मंत्री बनने वाले हैं ।

श्री समर गुह : आज विश्व में पुरानी गुटबंदी समाप्त हो रही है । मैं भारत-रूस मैत्री के तो पक्ष में हूँ, परन्तु हमारा रूसी गुट के इतना निकट होने के कारण अन्य देश हमारा विरोध कर रहे हैं । अन्य हमसे असंबद्ध होते जा रहे हैं । देश तो गुटबन्दी से परे हट रहे हैं परन्तु हम सोवियत रूसी गुट में अन्तर्ग्रस्त हो रहे है

हरीपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था कि भारत को विदेश नीति को देश की आंतरिक नीति से मिलाया नहीं जाना चाहिए। हमें मिस्त्र और इन्डोनेशिया से शिक्षा लेनी चाहिए और विदेश नीति को आंतरिक नीति से जोड़ना नहीं चाहिए।

हमारी चेष्टा यह होनी चाहिये कि हिन्द महासागर को विश्व शक्तियों के संघर्ष से मुक्त रखा जाय। यदि कोई सुरक्षा संधि की जानी है तो वह इस क्षेत्र के राष्ट्रों के मध्य होनी चाहिए जिसमें बड़ी शक्तियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों, स्थायित्व और सुरक्षा के दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए।

डा० एच० पी० शर्मा (अलवर) : 1971 में देश अपने सही स्वरूप में सामने आया, न केवल बंगला देश की मुक्ति से अपितु इस तथ्य से कि भारत को जो पाकिस्तान के समकक्ष माना जाता था वह बात समाप्त हो गई। सरकार और प्रधान मंत्री पर पड़ने वाले दबावों के बावजूद उचित समय पर उचित निर्णय लिया। विदेश मंत्रालय अपनी नीति सम्बन्धी उद्घोषणाओं के लिये प्रशंसा का पात्र है।

प्रधान मंत्री ने अमरीका को सही बात समझाने की चेष्टा की परन्तु उस देश का रवैया नितान्त निराशाजनक ही रहा। अमरीकी कार्यवाही का उग्रतम रूप सातवें बेड़े का हिन्द महासागर में भेजना था।

हमें अपने देश से संबद्ध समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। चीन के बारे में संबन्ध सुधारने की आशाएं लगाई गई थीं। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि हमने अक्साई चिन के बारे में भी वार्ता करना स्वीकार कर लिया था।

चीन के संबन्ध में हमें उसके मन को समझना चाहिए। इस समय उनके समक्ष सुरक्षा की समस्या है और रूस की शत्रुता सर्वाधिक है, जापान और भारत की शत्रुता को भी उसमें स्थान हैं। जब तक रूस से चीन को भय बना रहता है, उसके हमारे साथ संबन्धों में सुधार नहीं हो सकता। हमारे एक तरफा प्रयत्न सफल नहीं होंगे।

भारत-रूस संधि की धारा 9 और धारा 4 भी चीन को हमारे विरूद्ध बनाती है। इस समय चीन के साथ हमारे वार्ता प्रस्ताव फलदायक नहीं होंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The object of a country's foreign policy is protection and enhancement of it's national interests. There is room for ideals, principles and pronouncements but it's determination and operation is based on realities. Our policy has been to establish friendly ties with every country. We have friendship with country having different forms of governments.

I was shocked to hear from the Prime Minister that they formulated their policy not according to who did or who did not support whom, but on certain principles. Principles no doubt are important in the international field, but foreign policy cannot be determined unilaterally. Is it not a fact that due to recent U. S. opposition to India, our opposition to U. S. action in Vietnam has became more critical ?

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

The Arab countries adopted a policy opposed to us in the struggle of Bangla Desh. Now it becomes necessary for us to reshape our policy towards these countries.

Discussions with Pakistan are taking place shortly. What do we want to achieve in these talks ? Will the house be taken into confidence in the matter ? If the inflow of foreign arms to Pakistan is stopped, there can be permanent peace in the sub-continent. I fear that the powers which have so far been provoking Pakistan against India, will auow Pakistan to take up a new role.

The Sino-U. S. joint communigue gives strength to the fear that these two countries would not allow Pakistan to establish normal relations with India. I fear that U. S. might enter Bangla Desh in a big way and China might try to encourage trouble in Kashmir.

The Foreing Minister's speech delivered in the United Nations on December 21, 1971 is astonishing. I quote from that speech :

"There is thus need to avoid the rotation of such incidents by making some adjustments in the cease-fire line in order. to make it more stable, rational and viable. This we propose to discuss and settle with Pakistan."

Does this not mean that India is prepared to offer the portion of Kashmir in illegal occupation of Pakistan to that country ?

The other day the External Affairs Minister stated that entire State of Jammu and Kashmir is integral part of India. We have left 25 vacant seats in the State Assembly for Pak-occupied Kashmir. Pakistan was aggressess in Kashmir and the aggression should be asked to withdraw.

I agree with the Government's view that the question of prisoners of war should not be discussed exclusively. President Bhutto had announced that he wanted to make his Army the best in Asia. Bakistan itself cannot pose a threat to us, but the intentions of her foreign allies is not friendly towards. India. Some foreign powers do not like the emergence of India as a world power after the liberation of Bangla Desh.

There has been some misunderstanding in regard to Asian Security Part. It has been said that the idea had it's origin in Prime Minister's tour of Japan, Indonesia and other countries. The External Affairs Minister has given different statements in this regard. He said :

"The idea of an Asian Security Pact had not yet assumed concrete shape but as a preposition it's objective was good."

What is the purpose of Asian Security Pact and which countries would be included in it ?

Recently a conference of some of the Ambassadors was held with a pomp and show.

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : Not with pomp and show.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The External Affairs Ministry is setting up a new convention. It seems that some work has been assigned to them this time.

श्री स्वर्ण सिंह : उन्हें तो काम से बुलाया गया था ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It has been published in the newspapers :

"India will support a move towards guaranteeing the sovereignty, independence and territorial integrity of countries of the region through an international convention and agreement".

I want a clerification who would give this guarantee and against whom that guarantee would be given ?

Shri Swaran Singh : Something has been published in your party paper in this regard.

Shri Atal Bihari Vajpayee : There is no question of his party or my party. Everyone in the country wants to know the origin of Asian Security Pact ?

In the Indian ocean Area, there are U. S. ships, Russian ships and French ships, but where is Indian in the Indian ocean ? A resolution was passed in the United Nations as a result of the efforts of Ceylon to the effect that Indian Ocean should remain an area of peace but no big power agreed to that. What is the objection in calling for a conference of Indian ocean countries ?

A noted Hindi writer Shri Sachidanand Hiranand Vatsayayan visited same foreign country. Our Ambassador there organised a function in his honour and introduced Shri Vatsayayan by saying that he was the writer of 'Kamsutra'. There is a need to start a process of training of our ambassadors so that they may represent Indian culture in the real sense. It is necessary that we should have association with the past as well as the modern times.

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं विदेश मंत्रालय की मांगों पर हो रही चर्चा पर माननीय सदस्यों के भाषण दिनभर सुनता रहा । जनसंघ के नेता को भारत की विदेश नीति के बारे में कुछ गलत फहमी है। विशेष रूप से हमारी पाकिस्तान के प्रति नीति और एशिया सामूहिक सुरक्षा की नीति के बारे में। लेकिन भारत को आज सारे एशियाई क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाने में नेतृत्व करना है । प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति की संसार भर में प्रशंसा हुई है । पहले पहले बंगला देश की स्थिति को संसार में समझा नहीं था, परन्तु बाद में उन्होंने स्थिति को समझा और अधिकांश देशों ने बंगला देश को मान्यता प्रदान कर दी ।

अमरीका दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव जमाना चाहता था ताकि एशियाई राष्ट्रों को कमजोर करके उन्हें आत्म-निर्णय और आत्म विकास के अधिकार से वंचित रखा जाए ! इसी उद्देश्य से वह भारत के कुछ पड़ोसी देशों को निश्चित सहायता दे रहा है ताकि वे भारत के विरूद्ध काम आ सके । अत: हमारी सरकार का यह प्रयास होना चाहिये कि वह अमरीका को एशिया में ऐसा न करने दे । इस उद्देश्य के लिये भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ अपने सभी मामले सुलझाने होंगे ।

यह तर्क दिया गया है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिये जब तक कि वह सारा जम्मू और काश्मिर हमें देने को तैयार न हो । यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय है । इस तरह की नाजुक समस्याओं को छेड़ने का यह समय नहीं है । यह ठीक है कि हमें अपनी समस्यायें दृढ़ निश्चय के साथ इस तरह हल करनी चाहिये कि जहां तक सम्भव हो सके और जिस भी सीमा तक हम जा सके हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए ।

[श्री बी० के० दासचौधरी]

दुख की बात है कि अरब देशों के साथ हमारी मित्रता होने के बावजूद, अधिकांश अरब देशों ने बंगला देश की स्थिति को उचित रूप से नहीं समझा। क्या यह उचित है कि किसी विशेष समय में कुछ देश स्थिति को न समझें तो अब हमें उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखने चाहिये। हमारी गृह नीति हमेशा ऐसी होना चाहिये कि हम अपनी विदेशी नीति को उचित रूप से ढाल सकें। वास्तव में विदेश नीति और गृह नीति एक दूसरे की पूरक होती है, जब तक हम आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, कृषि सुधार आदि के सम्बन्ध में अपनी एक गृह नीति बनाने की स्थिति में नहीं हो जाते, तब तक हम अपनी विदेश नीति के जरीये और अच्छी तरह से योगदान नहीं कर सकेंगे।

वियतनाम की स्थिति में हमें रुचि लेनी चाहिये क्यों की यहां की घटनाओं का दक्षिण-पूर्व एशिया के राष्ट्रों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और इसका इस देश की भावी घटनाओं पर भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आज अमेरिका और चीन के बीच एक सीमा है तो अपने हितों के विकास के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र पर अपना दबाव डालने का प्रयत्न कर रहा है और कुछ देशों पर अपनी विचारधारा अथवा महत्ता के हित में अथवा अपने राष्ट्रीय हित में दबाव डाल रहा है किन्तु जब तक वियतनाम के मामले में हमारी गहन रूचि नही होगी तब तक हमारे भावी हितों पर भी कुप्रभाव पड़ता रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमारे राजदूतों, प्रशासकों या विदेश सेवा के अधिकारियों को जिस देश में उन्हें नियुक्त किया जाना हो उस देश की संस्कृति और भाषा का समुचित प्रशिक्षण दिया जाये। चीन के न चाहने पर भी हमें उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। हमें वहां अपना राजदूत भी नियुक्त करना चाहिये और उसे हमें अच्छी तरह समझने का अवसर देना चाहिये ताकि उस समस्त क्षेत्र में शान्ति और सहयोग स्थापित किया जा सके।

श्री तुलसीदास दासप्पा (मैसूर) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ गत वर्ष विदेश मंत्रालय ने जो सर्वोत्तम कार्य किया है उसके लिये वह बधाई का पात्र है। बंगला देश अपने मुक्ति संग्राम में सफल रहा है। बंगला देश हमारा अच्छा पड़ोसी और मित्र है। जब हमने युद्ध विराम का निर्णय लिया था तो हमारे विचार में वह हमारे राष्ट्र की एक शानदार कार्यवाही थी। इससे विश्व भर में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है।

पाकिस्तान के साथ अब हमारी वार्ता होनी है और हमें विश्वास है कि हमारे विदेश मंत्री इस मामले में पूर्णतया सतर्क रहेंगे। काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के सम्बन्ध में हम जो भी समायोजना करना चाहेंगे वह हमारे राष्ट्र हित में हो सकती है और उससे अधिक स्थिरता आने की सम्भावना है। हमें विश्वास हैं कि सरकार इस दिशा में कभी भी गलत कदम नहीं उठायेगी। हमारे विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उसके बारे में जनसंघ के नेता को कोई संदेह नही होना चाहिए।

हम यह जानते हैं कि श्री भुट्टो ने अपने वक्तव्यों द्वारा हमें काफी चेतावनी दी है। ऐसा नही है कि हमे इस बात का पता न हो कि वह क्या कर रहे हैं। हमें विश्वाश है पाकिस्तान द्वारा जो भी प्रस्ताव रखे जायेंगे उनका सामना करने के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल पूरी तरह तैयार है बार्तालाप करने के लिये जाने से पूर्व ही यह बात स्पष्ट हो गयी है कि राष्ट्रपति भुट्टो आपसी सहयोग से नहीं वरन् आपसी संघर्ष में रूचि रखते हैं।

वियतनाम के प्रति भारत सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमारा दृष्टिकोण ठीक रहा है और वियतनाम के लोगों द्वारा किये जाने वाले संघर्ष के प्रति हमारे मन में सहानुभूति है। किन्तु अब समय आ गया है कि हम कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर से ध्यान हटा कर मुसीबत में पड़े हुए लोगों की सहायता करें।

भारत-सोवीयत मैत्री संधी करके हमने भारी सफलता प्राप्त की है जो समस्त राष्ट्रों के लिये अनुकरणीय है। विदेशों में हमारे दूतावासों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और आशा है कि भविष्य में भी वे पहले की तरह सजग रहेंगे और अच्छा कार्य करते रहेंगे।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 26 अप्रैल, 1972/ वैशाख, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, April, 26 1972 Vaisakha 6, 1894 (Saka).

Nai Dunia Press Indore 590-7-72